R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.oksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 17
01 से 15 जून 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार

जब कोतवाल ही चोर?

फर्जीवाड़े में माफिया, नेताओं और अफसरों का गठजोड़ सामने आया

छात्रों का भविष्य खराब करने वालों पर सीएम डॉ. मोहन का चाबुक

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

राजकाज

9 | सुशासन का रोडमैप तैयार...

शासन-प्रशासन की सख्ती के बावजूद प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, खनन माफिया के दुस्साहसी जानलेवा कदम, गेहूं खरीदी में फर्जीवाड़ा, सागर की घटना, नर्सिंग घोटाला आदि को लेकर मुख्यमंत्री...

राजपथ

10-11 | परिणाम बदलेगा...

विधानसभा में मिली बंपर जीत के बाद मप्र भाजपा ने लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन 400 पार को पूरा करने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री...

जलसंकट

15 | मप्र में 42.27 लाख...

मप्र में जिस तेजी से गर्मी बढ़ रही है उसी तेजी से जलाशयों के जल संग्रहण में गिरावट आई है। वहीं जलस्तर में गिरावट के कारण सरकार नलकूप योजनाओं की सांस फूलने लगी है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के 42.27 लाख परिवारों के सामने सबसे अधिक...

अभियान

18 | चंबल की स्वच्छता...

शासन, प्रशासन से लेकर आमजन में मान्यता है कि चंबल नदी मप्र ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में शुमार है। लेकिन चंबल का पानी कितना स्वच्छ है, यह इंसानों के पीने लायक है भी या नहीं? चंबल के पानी में क्या खूबियां और क्या कमियां हैं? यह तकनीकी तौर पर किसी...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र में हुआ नर्सिंग कॉलेज घोटाला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। कैसे सालों तक फर्जी नर्सिंग कॉलेज प्रदेश में संचालित होते रहे और छात्रों का भविष्य दांव पर लगाते रहे, इसकी परतें अब खुलनी शुरू हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि घोटाला उजागर हुआ और सीबीआई को जांच सौंपी गई, लेकिन जांच करने वाले अधिकारी ही बिक गए। यह नर्सिंग घोटाला प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाला जैसा ही है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फर्जीवाड़े को गंभीरता से लिया है।

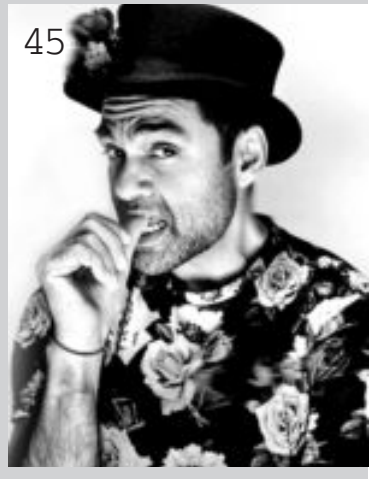

राजनीति

30-31 | अजब-गजब चुनावी वादे

पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाला है, जिसमें वह कहते हैं कि उनकी सरकार केंद्र की कुर्सी पर जैसे ही काबिज होगी, उसी दिन से हर गरीब परिवार की महिला के बैंक खाते में हर महीने साढ़े आठ हजार रुपए मिलने वाले हैं, खटाखट...

महाराष्ट्र

35 | मराठा गौरव का चुनावी दांव

महाराष्ट्र में इस बार एनडीए के लिए राह 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव जितनी आसान नहीं होगी। 2019 में एनडीए ने 48 में से 41 लोकसभा सीटें जीती थीं। एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का कहना है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में सहानुभूति की लहर है।

बिहार

38 | तेजस्वी के तेज की परीक्षा...

बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को जिताने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर है। कहने को तो राजद कांग्रेस, वाम दलों और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के साथ चुनाव...

6-7 अंदर की बात
40 विदेश
41 महिला जगत
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

उफ...! ये जानलेवा गर्मी

शा*यर मंजूर हाशमी का एक शेर है*

कुछ अब के धूप का ऐसा मिजाज बिगड़ा है
दरख्त भी तो यहां साएबान मांगते हैं...

कुछ इसी तरह की स्थिति इस बार की गर्मी में बनी हुई है। समय के साथ बढ़ता तापमान नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, हर तरफ जानलेवा गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी के लिए भले ही हम लोग सूरज को कोस रहे हैं, लेकिन इसके असली जिम्मेदार हम खुद हैं। जिस तरह धरती पर पेड़ों को काटकर कांक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं, उससे पृथ्वी पर नमी खत्म हो रही है। उस पर औद्योगिक विकास और एसी का बढ़ता उपयोग गर्मी को खतरनाक स्तर पर पहुंचा रहा है। आलम यह है कि मई महीने में देश के अधिकांश क्षेत्रों में 45 डिग्री तापमान लोगों को सामान्य लगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों का तापमान हाफ सेंचुरी लगा चुका है। तापमान बढ़ने से नदी, तालाब, बांध, कुएं के पानी सूखने लगे हैं, वहीं भूजल स्तर रिकार्ड स्तर पर नीचे खिसका है। इससे देशभर में जलसंकट की स्थिति बनी हुई है। देखा जाए तो बढ़ते तापमान के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हमारा ग्रह बड़ी तेजी से गर्म हो रहा है, जिसके प्रभाव भारत सहित पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। यही वजह है कि कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश पड़ रही है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है। कहीं सूखे के बाद अचानक से बाढ़ आ जाती है। भारत में तो यह समस्या किस कदर विकट हो चुकी है कि बसंत का पूरा सीजन ही लगभग गायब होने को है। इसी तरह यदि मई 2023 से अप्रैल 2024 के बीच पिछले 12 महीनों को देखें तो उस दौरान भी तापमान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस अवधि के दौरान दर्ज औसत तापमान समान अवधि में औद्योगिक काल से पहले के औसत तापमान से 1.61 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरह इसकी तुलना यदि 1991 से 2020 के बीच दर्ज औसत तापमान से करें तो वो 0.73 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। अब इस बात की 55 फीसदी आशंका जताई है कि 2024 जलवायु रिकॉर्ड का अब तक का सबसे गर्म साल होगा। वहीं इस बात की 99 फीसदी आशंका है कि 2024 अब तक के पांच सबसे गर्म वर्षों में शुमार होगा। अप्रैल 2024 के दौरान यूरोप में दौर औसत तापमान भी औद्योगिक काल से पहले के औसत तापमान की तुलना में 1.49 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जो इसे यूरोप का अब तक का दूसरा सबसे गर्म अप्रैल बनाता है। बढ़ते तापमान से जुड़े आंकड़ों को देखें तो इस साल अप्रैल में दर्ज तापमान औद्योगिक काल से पहले के औसत तापमान से 1.58 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं मई में भी गर्मी ने खूब तपाया है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर अप्रैल 2024 में सतह के पास हवा का औसत तापमान 15.03 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1991 से 2020 के बीच अप्रैल में दर्ज औसत तापमान से 0.67 डिग्री सेल्सियस अधिक है। देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान अपने साथ जाने-अनजाने खतरे भी ला रहा है, जो भारत सहित पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। मई में पड़ी गर्मी तो जानलेवा साबित हुई है। उत्तरी भारत के कई राज्यों में हीटवेव के कारण एक सैकड़ा से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक मौत राजस्थान में हुई है। गर्मी और मौत के ये आंकड़ें हमें सचेत करते हैं कि अगर जानलेवा गर्मी से बचना है तो प्रकृति को संरक्षित रखें और वनीकरण पर अधिक ध्यान दिया जाए।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 17, पृष्ठ-48, 1 से 15 जून, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

अच्छी पहल

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम में एकरूपता लाने के मद्देनजर मॉडल फायर एक्ट तैयार कराया है। इसमें जरूरी संशोधन कर लागू करने की तैयारी मप्र में 5 साल पहले से चल रही है। यह फायर एक्ट राज्यों के लिए एक अच्छी पहल है।

● **प्रकाश सिंह,** भोपाल (म.प्र.)

छात्रों को मिले सुविधाएं

देश में नई शिक्षा नीति के बारे में भले ही बढ़-चढ़कर बातें हो रही हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में कोई खास बदलाव नजर नहीं दिख रहा है। कम से कम मप्र में तो कोई असर नहीं दिख रहा है। सरकार को शिक्षा नीति में बदलाव कर छात्रों को सुविधाएं देनी चाहिए।

● **अजय नामदेव,** इंदौर (म.प्र.)

ठोस कदम उठाए सरकार

मप्र में देशी और विदेशी शराब दुकानों की नीलामी के जरिए सरकार को हर साल 12 से 13 हजार करोड़ का टैक्स मिलता है। इसके बावजूद प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर आबकारी अमला रोक लगा पाने में नाकामयाब है। इसको लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

● **पूनम मिश्रा,** सीहोर (म.प्र.)

जलसंकट से कब उबरेगा बुंदेलखंड ?

पानी की समस्या प्रदेश सहित पूरे देशभर में देखने को मिल रही है। खासकर बुंदेलखंड में गहरा जलसंकट है। चुनावी मंचों पर दावे और वादे करने वाले नेता हमेशा बुंदेलखंड के विकास की बातें कहते रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तब हर वर्ग के विकास की बात कही जाती है। इसी विश्वास के चलते लोगों ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में हर सांसद को भरपूर प्यार दिया। लेकिन, सांसदों ने चुनाव के बाद फिर क्षेत्र के लोगों को पलटकर नहीं देखा। पूरे बुंदेलखंड में गर्मियों के समय पानी की किल्लत रहती है। खासकर के अप्रैल-मई महीने से पीने के पानी का सबसे बड़ा संकट यहां देखने को मिलता है। यहां हर साल सूखे के हालात बनते हैं और फिर लोग कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाकर अपना गुजारा करते हैं।

● **शफीक कुरैशी,** जबलपुर (म.प्र.)

कब स्वच्छ होगी शिप्रा ?

दो दशक में शिप्रा की शुद्धि के लिए सरकार ने हजार करोड़ से अधिक रुपया खर्चा है। 402 करोड़ रुपए 2014 में प्राकृतिक प्रवाह से नर्मदा का शिप्रा से मिलन कराने पर खर्चे थे। इसके बाद 2016 में 99 करोड़ रुपए कान्ह डायवर्जन योजना पर खर्चे थे। इस योजना का उद्देश्य कान्ह का गंदा पानी शिप्रा के नहान क्षेत्र (त्रिवेणी घाट से कालियादेह महल तक) में मिलने से रोकना था। सरकार को शिक्षा को स्वच्छ रखने के लिए नई योजना बनानी चाहिए।

● **चंदन शिवहरे,** उज्जैन (म.प्र.)

प्रदेश के पॉवर प्लांट पर ध्यान दे सरकार

मप्र का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पॉवर प्लांट बिजली उत्पादन में पिछड़ रहा है। निर्धारित मात्रा में इस पॉवर प्रोजेक्ट से बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। सुपर पॉवर प्लांट कोयला भी ज्यादा खा रहा है। इससे मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके चलते अब इस पॉवर प्लांट की जांच कराए जाने की मांग उठने लगी है। मप्र के खंडवा जिले में स्थित श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पॉवर प्लांट प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

● **राम प्रजापति,** ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

भाजपा के समर्थन में क्यों आए धनंजय?

लोकसभा चुनाव में उप्र के जौनपुर से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह के भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने चुनाव में उतरने की हुंकार भरी थी। धनंजय के जेल जाने पर उनकी पत्नी श्रीकला ने बसपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भी किया। लेकिन अब वह चुनाव के बीच में बसपा छोड़कर खुद भाजपा के साथ हैं। सियासी गलियारों में हर कोई जानने को उत्सुक है कि आखिर वह क्या वजह है जिसके चलते धनंजय भाजपा के करीब आ गए? कहा जा रहा है कि कृपाशंकर सिंह का नाम भाजपा प्रत्याशी के रूप में घोषित होने के बाद धनंजय ने चुनाव मैदान में उतरने को लेकर जो घोषणा की थी, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी। सूत्रों के मुताबिक दो केंद्रीय एजेंसियों में चल रहे दो अलग-अलग मामलों की जांच की आंच धनंजय तक पहुंच सकती थी। धनंजय ने पहले बैकडोर से भाजपा से जुड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। धनंजय बिहार में भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू से जुड़े थे। वह प्रयासरत थे कि जौनपुर सीट एनडीए के सहयोगी जेडीयू के खाते में चली जाए और वह उसके टिकट पर चुनाव लड़ लें। लेकिन अचानक कृपाशंकर सिंह की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तस्वीर सामने आई और फिर जौनपुर प्रत्याशी के रूप में उनके नाम की घोषणा हो गई।

भारी पड़ सकती है वसुंधरा की अनदेखी

लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में इस बार भाजपा के मिशन 25 को झटका लग सकता है। राजनीतिक हल्कों में खबर है कि पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मान लिया है कि राजस्थान में इस बार भाजपा को सभी 25 सीटों पर जीत नहीं मिलेगी। शाह के इस बयान के बाद प्रदेश भाजपा में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। एक वर्ग का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अनदेखी इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी पड़ सकती है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे इस बार केवल अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए ही प्रचार करती हुई नजर आई हैं। प्रदेश की अन्य सीटों के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बनाई थी। इसी कारण भाजपा को नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे वर्ग का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अशोक गहलोत सरकार की लोक लुभावन योजना को बंद करने से भी भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इसका एक कारण प्रदेश में इस बार मतदान प्रतिशत का कम होना भी बताया जा रहा है।

मंत्री पद से इस्तीफे देंगे किरोड़ी लाल

लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच किरोड़ी लाल मीणा का एक बयान काफी सुर्खियों में है जिसमें उन्होंने दौसा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के हारने की स्थिति में मंत्री पद से इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी। उनके इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि 4 जून के चुनाव परिणाम के बाद कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा देना तय है? इसको लेकर राजनीतिक जानकार अलग-अलग मायने निकाल रहे हैं। जानकार कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की फितरत हमेशा धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करने की रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा अपना मंत्री पद त्यागकर फिर से धरना-प्रदर्शन की राह पकड़ेंगे? क्या मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर धरना-प्रदर्शन करेंगे? तमाम सवालों के ईद-गिर्द अभी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की सियासत देखी जा रही है। इधर राजस्थान भाजपा में भी हलचल मची हुई है। कांग्रेस के साथ भाजपा के नेता भी इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि क्या वाकई में किरोड़ी लाल मीणा अपने मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? असल में किरोड़ी लाल मीणा ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सात लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी थी।

डोटासरा को फिर कमान!

आम चुनाव के बाद क्या राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का चेहरा बदला जाएगा? इस बात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। वर्तमान में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें पार्टी से इशारा मिलने की चर्चा भी है। प्रदेश में नए सियासी संतुलन के लिहाज से बदलाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं। गौरतलब है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने 2020 में सियासी संकट के बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान संभाली थी। उनका तीन साल का कार्यकाल पिछले साल खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें बरकरार रखा गया। ऐसे में अब एक बार फिर इस बात को लेकर सुगबुहाट तेज है कि गोविंद सिंह डोटासरा को फिर मौका मिलेगा या प्रदेश कांग्रेस का चेहरा बदल जाएगा। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस के इतिहास में कई प्रदेशाध्यक्ष ऐसे रहे हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा बार राजस्थान कांग्रेस की कमान संभाली है।

साय मंत्रिमंडल विस्तार जल्द

छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव तीन चरणों में हुए हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने इस चुनाव के दौरान हर एक नेता का प्रदर्शन और वर्क ऑफ एरिया तय किया था। अब लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह देखा जाएगा कि किसके क्षेत्र में कितना बेहतर काम हो पाया है? जिन नेताओं को लोकसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारियां दी गई थीं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? भाजपा के रायपुर स्थित दफ्तर में तो चर्चाएं यहां तक हैं कि कैबिनेट में भी बदलाव देखा जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी का दौर गर्म है कि आम चुनाव के नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ-साथ निगम मंडल की नियुक्तियां भी की जा सकती हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो निगम और मंडल की नियुक्तियों में उन नेताओं को प्राथमिकता मिल सकती है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि साय सरकार बनने के बाद से ही माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निगम और मंडल में नियुक्तियां हो सकती हैं लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया था।

दोनों की विदाई तय...

विंध्य क्षेत्र के एक जिले में खनन माफिया इस कदर बेलगाम हो गया है कि उसमें शासन और प्रशासन का भय तक नहीं दिख रहा है। गत दिनों माफिया ने एक एएसआई की हत्या कर अपने दुस्साहस का परिचय दिया है। सूत्रों का कहना है कि जिले में पुलिस के साथ माफिया की ऐसी गठजोड़ है कि शासन-प्रशासन की सख्ती के बाद भी माफिया कोयला और रेत का अवैध खनन लगातार कर रहा है। आलम यह है कि एएसआई की हत्या के बाद शासन के निर्देश पर जिले में माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अवैध खनन की गतिविधियों पर विराम लगता नहीं दिख रहा है। सूत्र बताते हैं कि जोन आईजी और पुलिस कप्तान की मिलीभगत से रेत के अवैध खनन का गोरखधंधा फल-फूल रहा है। आरोप तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि दोनों ने 50-50 लाख रुपए के एवज में माफिया को फ्रीहैंड कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि दोनों अफसरों के गोरखधंधे की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों अफसरों पर मुख्यमंत्री का बुल्डोजर चल जाएगा। यानी दोनों की वहां से विदाई तय मानी जा रही है। यानी यह भी कहा जा सकता है कि रेत और कोयला के अवैध खनन से फल-फूल रहे इन दोनों अफसरों की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सरकार की पहली गाज इन दोनों पर गिरनी तय है।

...तो आईपीएस अवार्ड पर लग सकता है ग्रहण

राज्य पुलिस सेवा के एक अधिकारी आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं। साहब को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी लॉटरी लग सकती है। लेकिन साहब के पुराने गुनाह उनकी राह में रोड़ा बने हुए हैं। दरअसल, साहब तीन मामलों में फंसे हुए हैं। इनमें से एक मामले में उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। अगर उस जांच में साहब पर लगा दाग सही साबित होता है तो आईपीएस बनने के उनके सपने पर पानी भी फिर सकता है। गौरतलब है कि विगत दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें साहब का गुनाह शासन-प्रशासन के साथ ही आम लोगों तक पहुंच गया था। दरअसल, उस वीडियो में एक महिला द्वारा शराब बेचने का मामला दिखाया जा रहा है, जिसमें साहब यह कहते सुने जा रहे हैं कि यह महिला जो कर रही है, उसे करने दिया जाए। कोई भी इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छोड़ नहीं करेगा। अब यह मामला इस कदर गर्मा गया है कि साहब शासन और प्रशासन की नजर पर चढ़ गए हैं। साहब के खिलाफ पहले से कुछ मामले चल रहे थे, वहीं वे इस मामले में बुरी तरह फंस गए हैं। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। साहब के अतीत को देखते हुए प्रशासनिक वीथिका में कहा जा रहा है कि अब तो इनका आईपीएस बनने का सपना शायद ही पूरा हो पाए।

जल निगम के लिए जुगाड़

प्रदेश की नई सरकार को सुशासित रखने के लिए सरकार के मुखिया ने कुछ कायदे-कानून बना रखे हैं, जिन्हें पालन करने का निर्देश मंत्रियों को भी दिया गया है। इनमें से एक है मंत्रियों के स्टाफ को लेकर। सरकारी निर्देश के अनुसार कोई भी मंत्री ऐसे अफसरों को अपने स्टाफ में नहीं रखेगा, जो पूर्व में मंत्रियों के यहां पदस्थ रहे हों। लेकिन सरकार के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर मंत्रियों के स्टाफ में रहने के आदी हो चुके अधिकारी, कर्मचारी जुगाड़ लगाकर पदस्थ होने में सफल हो गए हैं या कवायद में जुटे हैं। इन्हीं में से एक शिक्षा विभाग के अधिकारी इन दिनों चर्चा में हैं। ये महाशय पूर्व में पुराने खनिज मंत्री के यहां ओएसडी की सेवाएं दे चुके हैं। अब शिक्षाविद् ये महाशय जल निगम में स्थायी पदस्थापना की जुगाड़ लगा रहे हैं। इसलिए महाशय ने एक महिला मंत्री की परिक्रमा शुरू कर दी है। बताया जाता है कि उन्होंने महिला मंत्री का ओएसडी बनने के लिए पूरा दमखम लगा रखा है। सूत्रों का कहना है कि भले ही उन्हें वैधानिक तरीके से महिला मंत्री का ओएसडी पदस्थ नहीं किया गया है, लेकिन वे चोरी-छिपे महिला मंत्री के यहां पदस्थ हो गए हैं। बताया जाता है कि राजधानी में जब भी महिला मंत्री रहती हैं, ये महाशय उनके बंगले पर जा डटते हैं, मैडम जब तक राजधानी में रहती हैं, वे उनका कामकाज करते रहते हैं। इसके पीछे उनकी मंशा यह है कि मंत्री उन्हें अपना ओएसडी बना ले और बाद में उन्हें जल निगम में स्थायी पदस्थापना मिल जाए।

बंगला बन रहा या किला ?

राजधानी में बाघ भ्रमण क्षेत्र का ग्रीन बेल्ट एरिया ब्यूरोक्रेट्स को इस कदर भाया है कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस क्षेत्र में हर अफसर अपना बंगला बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अधिकांश अफसरों के बंगले इसी क्षेत्र में बने हैं या बन रहे हैं। ऐसा ही एक बंगला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, यह बंगला एक एडीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी का है, जो निर्माणाधीन है। ये साहब हमेशा विवादों में रहे हैं। ऐसे में इनके बंगले पर हर किसी की नजर लगी हुई है। इसकी वजह यह है कि साहब के बंगले की दीवारें किलेनुमा ऊंची हैं। जिसके बारे में कहा जाता है कि बंगले का परिक्षेत्र मंत्रालय की एक विंग से भी बड़ा है। जिसे देखकर लगता है कि यह बंगला नहीं कोई किला है। लोग बंगले की भव्यता को देखकर उसके निर्माण में लगने वाली राशि का भी अपने-अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं। वहीं कुछ लोग तो किलानुमा इस बंगले को देखकर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इसकी सुरक्षा में नौकरी में रहते हुए पुलिस की एक बड़ी बटालियन तैनात करनी पड़ेगी। हर किसी को इस बंगले के पूरा होने का इंतजार है।

...तो इनका हटना तय

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता अभी भले ही हटी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था और आगामी योजनाओं को लेकर अभी से संवेदनशील नजर आने लगे हैं। इसी कड़ी में वे अफसरों की जमकर क्लास ले रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि एक तरफ जहां उन्होंने प्रदेश के सभी ब्यूरोक्रेट्स की कुंडली बनाने का निर्देश दिया है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी कुर्सियों पर बैठे अफसरों की कार्यप्रणाली पर भी नजर रखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि गत दिनों जहां उन्होंने अपने प्रमुख सचिव को जमकर फटकार लगाई, वहीं एक बैठक में अधिकारियों के सामने मुख्य सचिव से कह दिया कि फाइलें पढ़ना आपका काम है। लगता है, आपका ध्यान काम में नहीं लग रहा है। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर उन्होंने पुलिस महानिदेशक के साथ ही अन्य पुलिस अधिकारियों की जमकर क्लास ली। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने डीजीपी से कहा कि आप कानून व्यवस्था को क्या देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस सख्त रुख को देखकर कहा जा रहा है कि अब तो इन सबका जाना तय माना जा रहा है।

बिना विरोध हटाए गए धार्मिक स्थल

मप्र की धार्मिक नगरी उज्जैन ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। शहर के विकास में बाधा बन रहे 18 धार्मिक स्थलों को आपसी सहमति से हटा लिया है। धार्मिक स्थलों में 15 मंदिर, 2 मजिस्द और एक मजार है। सभी लोगों ने विकास के कार्य में प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। उज्जैन के इस सांप्रदायिक सद्भाव वाले कार्य की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि उज्जैन की जनता ने प्रदेश के लिए उदाहरण पेश किया। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक और उनकी टीम ने जिस तरह लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए उनसे बातचीत करके धार्मिक स्थलों को हटाया है, उसकी हर तरफ सराहना हो रही है।

दरअसल उज्जैन शहर के केडी मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। मार्ग में सभी धर्मों के 18 धार्मिक स्थल एवं निजी भवन विकास में बाधा बन रहे थे, जिन्हें नागरिकों के आपसी सामंजस्य, समन्वय व स्वेच्छा से शांतिपूर्वक हटाया गया है। धार्मिक स्थलों को लोगों द्वारा स्वेच्छा से हटाना विकास की दिशा में सांप्रदायिक सौहार्द का उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। उज्जैन जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा गत दिनों केडी गेट तिराहे से तीन इमली चौराहे के जद में आने वाले 18 धार्मिक स्थलों को जनसहयोग से शांतिपूर्वक ढंग से हटाने की कार्रवाई की गई हैं। जिसमें धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों, पुजारियों और लोगों द्वारा भी सहयोग किया गया। 18 धार्मिक स्थलों में 15 मंदिर, 2 मस्जिद, एक मजार है, जिन्हें पीछे करने और अन्यत्र स्थापित करने की कार्यवाही की गई है। हटाई गई प्रतिमाओं को प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों द्वारा बताए गए निर्धारित स्थान पर विधिविधान से स्थापित किया गया। साथ ही 20 से अधिक भवन जिनका गलियारा आगे बढ़ा लिया गया था। ऐसे भवनों के उस हिस्से को भी भवन स्वामियों द्वारा स्वेच्छा से तोड़ने की कार्यवाही की गई।

उज्जैन में चौड़ीकरण में आड़े आ रहे धार्मिक स्थलों और मकानों के अतिक्रमण को प्रशासन की टीम हटाने की कार्रवाई कर रही है। मुस्लिम समाज के लोग इसके विरोध में उतर आए। महिलाएं मस्जिद के सामने ही सड़क पर बैठ गईं। नगर निगम और पुलिस के अधिकारियों ने समझाया, तब समाज के लोगों ने खुद ही मस्जिद के हिस्से को गिराने का निर्णय लिया। इधर, लालबाई फूलबाई चौराहे पर दिग्विजय हनुमान मंदिर को शिफ्ट किया जाना है। इसके विरोध में हिंदू संगठनों के लोग धरने पर बैठ गए। कार्रवाई रोक दी गई है। निगम अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की। वहीं कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अपने मकान का अतिक्रमण वाला हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया है। केडी गेट से लेकर इमली तिराहा तक जून 2023 में चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ था। बीच में 13 मंदिर, 1 मजार, 2 मस्जिद, 2 जैन मंदिर जद में आ रहे हैं। 32 मकानों की गैलरी और आगे के हिस्से भी तोड़े जाने हैं। इसके बाद इस रास्ते पर पोल पर लाइन खींचते हुए सेंट्रल लाइट लगाई जाएगी और दूसरे अधूरे काम पूरे किए जाएंगे।

प्रभावित हिस्सों को हटाने के लिए सुबह 5 बजे नगर निगम की टीम, पुलिस बल के साथ पहुंची। मार्ग 15 मीटर चौड़ा किया जाना है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मार्ग से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। नगर निगम कमिश्नर आशीष पाठक, एडीएम अनुकूल जैन, एडिशनल एसपी जयंत राठौर सहित तीन सीएसपी और चार थानों के टीआई मौके पर पहुंचे। लालबाई फूलबाई मार्ग पर सड़क किनारे स्थित तीन छोटे प्राचीन मंदिरों को नगर निगम के कर्मचारियों ने सामने की ओर सड़क किनारे बने नए छोटे मंदिरों में शिफ्ट किया। स्थानीय लोगों की सहमति से नगर निगम की टीम ने छोटे मंदिरों के गुंबद हटाकर नए मंदिरों पर रखे। दो मंदिर में भगवान श्रीगणेश और एक मंदिर में हनुमानजी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मंदिर के गुंबद हटाने के पहले लोगों और नगर निगम के कर्मचारियों ने पूजन किया। इच्छामन गणेश मंदिर को जेसीबी से तोड़े जाने पर लोगों ने विरोध जताया तो एएसपी जयंत राठौड़ मौके पर पहुंचे। उन्होंने नगर निगम टीम को जेसीबी का उपयोग नहीं करने और कटर मशीन से दीवार और छत का हिस्सा गिराने के लिए कहा। इस सहमति के बाद लोग इच्छामन गणेश मंदिर से हटे।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

मंदिर-मस्जिद से हटाए लाउडस्पीकर

भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, रतलाम और शाजापुर समेत पूरे प्रदेश में गत दिनों धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का अभियान चला। पुलिस और प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद यह एक्शन हुआ है। भोपाल में कानून व्यवस्था की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था, खुले में मांस की बिक्री रोकने और लाउडस्पीकर-डीजे पर नियंत्रण का अभियान फिर चलाया जाए। भोपाल में धार्मिक स्थलों पर लगे 96 लाउडस्पीकर हटाए गए। पुलिस और प्रशासन ने सभी थाना क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों पर धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। जिसके बाद सभी की सहमति और सहयोग से लाउडस्पीकर हटाए गए। इंदौर में भी बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए। कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता नेतृत्व में अभियान चलाकर 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। छिंदवाड़ा शहर में रिसाला मस्जिद, इंदिरा नगर की मस्जिद और आसपास के मंदिरों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसे ने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शासन से निर्देश मिले हैं। निर्धारित क्षमता से अधिक होने पर लाउडस्पीकर हटवाए जा रहे हैं। रतलाम जिले में 636 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर निकाले गए। 125 स्थानों पर साउंड कम कराया गया। रतलाम शहर के रहमत नगर मस्जिद हसनैन, मिल्लत नगर मस्जिद राजा-ए-मुस्तफा, जावरा रोड गाजी खान की मस्जिद, मोहन नगर और सैलाना यार्ड से दो-दो लाउडस्पीकर उतरवाए गए। रतलाम शहर के गुरुद्वारा से भी लाउडस्पीकर निकाला गया। पूरे जिले के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की जा रही हैं।

सुशासन का रोडमैप तैयार...

दलित, आदिवासी, महिला उत्पीड़न, नर्सिंग घोटाले को लेकर सीएम सख्त

शासन-प्रशासन की सख्ती के बावजूद प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, खनन माफिया के दुस्साहसी जानलेवा कदम, गेहूं खरीदी में फर्जीवाड़ा, सागर की घटना, नर्सिंग घोटाला आदि को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव काफी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने आचार संहिता के बीच ही चुनाव आयोग से अनुमति लेकर विभागों की बैठकें कर अफसरों को सख्ती बरतने का निर्देश दे डाला है। इन बैठकों में मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर सुशासन का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि प्रदेश में अब अपराधियों, माफिया, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन उप्र की तर्ज पर काम करेंगे। उन्होंने अफसरों को संकेत दे दिया है कि तीन महीने में प्रदेश की तस्वीर बदलनी है। यानी हर हाल में सरकार को काम का परिणाम चाहिए।

गौरतलब है कि अपने अल्प समय के कार्यकाल में भूमिपुत्र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासन-प्रशासन और जनता में मन में सुशासन का ऐसा भाव भर दिया है कि हर कोई उन्हें नायक की भूमिका में देखना चाहता है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का नया रूप देखने को मिलेगा। यानी डॉ. मोहन उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर काम करते हुए दिखेंगे। इसकी झलक उन्होंने गत दिनों विभागों की समीक्षा के दौरान दिखा दी है। जिस तरह उन्होंने रेत के अवैध खनन, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर, कानून व्यवस्था, नर्सिंग घोटाले और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अपना सख्त रूख दिखाया है, उससे यह साफ हो गया है कि आचार संहिता हटने के बाद सरकार का हथौड़ा तेजी से चलेगा। सत्ता-संगठन के सूत्रों का कहना है कि आगामी दिनों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कार्यशैली में सख्ती और तत्परता नजर आएगी। ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह बनाने के लिए सरप्राइज विजिट भी होगी। गौरतलब है कि डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही अपनी आक्रामक शैली से यह दिखा दिया कि वे उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर मप्र में काम करेंगे। कुर्सी संभालने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कुछ निर्णय सुर्खियों में रहे। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर्स के साथ ही खुले में मांस बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी। बदसलूकी के मामलों में बड़े अफसरों पर कार्रवाई भी चर्चित रहीं। हालांकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण लगभग सबकुछ थम-सा गया है। लेकिन अब एक बार फिर मुख्यमंत्री अपनी प्रशासनिक सक्रियता बढ़ाएंगे।

लोकसभा चुनाव की व्यस्तताओं से निवृत्त होते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रशासनिक कामकाज में जुट गए हैं। गत दिनों उन्होंने मंत्रालय में संभाग स्तरीय बैठकों में हुए निर्णयों के पालन की स्थिति को लेकर समीक्षा के दौरान कहा कि केवल बैठकों से काम नहीं चलेगा। असर दिखना चाहिए। रेत का खनन नियमानुसार ही होना चाहिए। उत्खनन में अवैध रूप से लगाई गई मशीनों को जब्त करें। अवैध उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई हो। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध उत्खनन और परिवहन की घटनाएं सामने आती हैं। इसे रोकने के प्रयास में कई बार घटनाएं हो जाती हैं। इन पर कड़ाई से अंकुश लगाया जाए। रेत का उत्खनन नियम अनुसार ही होना चाहिए। कहीं भी अवैध उत्खनन न हो। अवैध रूप से इस काम में लगी मशीनों को जब्त किया जाए। केवल बैठकें नहीं एक्शन होना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद प्रदेशभर में रेत के अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। अपराधियों की धड़पकड़ तेज हो गई है। ये सब इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में प्रदेश में सुशासन पर सबसे अधिक जोर रहेगा और प्रदेश में शासन की नई कार्यप्रणाली देखने को मिलेगी।

गत दिनों संभागीय बैठकों के निर्णयों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों को बड़े शहरों से जोड़ने, परस्पर दूरी कम करने व तेज गति से विकास के लिए नए एक्सप्रेस-वे की कार्य योजना बनाई जाए। दूरस्थ ग्रामों को निकटतम जिला मुख्यालयों से जोड़ने, पुलिस कमिश्नरेट व जिला कलेक्टर की व्यवस्था में समन्वय, बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम के प्रस्तावित क्रियान्वयन को भी इस प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाए। मुख्यमंत्री ने जिलों में लैंड बैंक तैयार करने और हर जिले में स्टेडियम निर्माण कराने के लिए भी निर्देश जारी किए। उन्होंने रेत के अवैध खनन में लगी मशीनों को तत्काल जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं।

● **कुमार राजेंद्र**

मुख्यमंत्री के सामने ये हैं चुनौतियां

आचार संहिता समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आएंगे। इसके लिए अधिकारियों ने कार्ययोजना बनानी शुरू कर दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने कई चुनौतियां भी होंगी। इनमें से एक चुनौती है प्रशासनिक अधिकारियों की नई जमावट। इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है। उसके बाद पुलिस महकमे को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि प्रदेश में अपराधिक मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंटेलीजेंस को भी दुरुस्त करना होगा। क्योंकि प्रदेश में कई बार यह देखने को मिला है कि सरकार के खिलाफ बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और एजेंसियों को इसकी सुगबुगाहट भी नहीं लगती है। इसके साथ ही जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली भी दुरुस्त करनी होगी। जांच एजेंसियों के पास कई बड़े मामले लंबित पड़े हैं, जिन पर सालों से कोई निर्णय नहीं हो पाया है। वहीं जनसंपर्क विभाग को भी व्यवस्थित करना होगा। यह विभाग सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ ही मीडिया को भी मैनेज करता है। इन सबके अलावा मुख्यमंत्री को संगठन की कार्यप्रणाली पर भी ध्यान देना होगा। भाजपा संगठन में ऐसे लोगों को जगह देनी होगी, जो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर सकें। वहीं दिल्ली में भी अपनी राजनीतिक टीम तैयार करनी होगी। ताकि वहां पर प्रदेश सरकार की जरूरतों को केंद्र सरकार तक आसानी से पहुंचाया जा सके।

4 जून को जैसे ही लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे, मप्र के राजनीतिक परिदृश्य में भी बदलाव की कवायद शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में सक्रियता और प्रदर्शन को देखते हुए यह तो तय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सशक्त होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का कद भी बढ़ेगा।

परिणाम बदलेगा राजनीति

विधानसभा में मिली बंपर जीत के बाद मप्र भाजपा ने लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन 400 पार को पूरा करने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सबसे अधिक मेहनत की है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की हैट्रिक बनने के बाद मप्र के पार्टी नेताओं की बल्ले-बल्ले होने जा रही है। हालांकि ये वो नेता हैं जिनका डंका तो पूरे देश में पहले से ही बोल रहा है, लेकिन मोदी की ताजपोशी के साथ इनका कद और अधिक कद्दावर हो जाएगा। 4 जून को आने वाले परिणामों के साथ देश की सरकार और मप्र के दिग्गजों का भविष्य तय हो जाएगा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि करीब 2 महीने तक चले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान विधायकों की सक्रियता की रिपोर्ट भी तैयारी की गई है। भाजपा द्वारा नियुक्त लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह एवं सह-प्रभारी सतीश उपाध्याय मप्र में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं। जहां वे पार्टी आलाकमान को विधायकों की रिपोर्ट देंगे। चौथे चरण के मतदान के बाद डॉ. सिंह एवं उपाध्याय अब दिल्ली में आलाकमान को विधायकों की रिपोर्ट देंगे। माना जा रहा है कि डॉ. सिंह एवं उपाध्याय ने चुनाव के दौरान प्रदेश के जिन क्षेत्रों का दौरा किया वहां भाजपा विधायकों द्वारा चुनाव के संबंध में किए गए कार्य के साथ ही पार्टी प्रत्याशी के लिए जनता के बीच जाने से लेकर सभा एवं संवाद के कितने काम किए इस संबंध में रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में भाजपा को प्राप्त मत प्रतिशत और लोकसभा चुनाव में क्षेत्र में डाले गए मत प्रतिशत को लेकर भी रिपोर्ट दी जाएंगी। इस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी आलाकमान भविष्य में विधायकों की जवाबदारी को तय करेगा।

मप्र में चार चरणों में 29 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 197 सभाएं, 56 से अधिक रोड शो, 185 से अधिक विधानसभाओं में दस्तक और 13 जिलों में रात्रि विश्राम कर सबसे आगे रहे। लेकिन प्रदेश सरकार के दो उप मुख्यमंत्रियों समेत 30 मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय सबसे आगे रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कमल खिलाने के लिए सबसे अधिक मेहनत की है। वे लगातार संसदीय क्षेत्र में सक्रिय रहे। वहीं मालवा-निमाड़ के साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी जमकर चुनाव प्रचार किया। गौरतलब है कि इस बार भाजपा ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए भाजपा ने पूरा दमखम भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से लेकर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, नेताओं और मप्र के मंत्रियों ने रात-दिन एक किया है। चुनाव प्रचार में प्रदेश में सबसे अधिक सभा और रोड शो

मंत्री-विधायकों के प्रदर्शन पर नजर

मप्र की 29 लोकसभा सीटों के लिए हुए मतदान में जिन मंत्रियों और विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में कम वोट मिलेंगे, उन पर पार्टी संगठन कार्रवाई कर सकता है। पार्टी का स्पष्ट मत है मात्र छह महीने पहले चुने गए विधायक और मंत्री लक्ष्य के अनुरूप मतदान में वृद्धि भी नहीं करवा पाए और वोटों में कमी आई तो इसकी वजह उनकी लोकप्रियता या संवाद में कमी ही है। पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रत्याशी चयन में कई जगह संगठन को छोड़ विधायकों की पसंद का भी ध्यान रखा गया है, ऐसे में उन्हें जिताने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। हार-जीत के अंतर में उनकी भूमिका नजर आनी चाहिए। इस तरह लोकसभा चुनाव के परिणाम विधायकों के लिए भी अग्निपरीक्षा साबित होंगे। मंत्रियों का पद छिने जाने की आशंका है तो विधायकों को कड़ी चेतावनी मिल सकती है। इस लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर 66.87 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। पांच माह पूर्व हुए विधानसभा चुनाव में हजारों मतों के अंतर से जीतने वाले विधायक और मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान की तुलना हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से की जाए तो इसमें 22 प्रतिशत की कमी आई है।

करने में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले नंबर पर रहे हैं। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नाम आता है, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय ने दोनों उपमुख्यमंत्रियों जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को पीछे छोड़ दिया है। वैसे विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया था। इस कारण वहां उन्होंने ज्यादा समय दिया।

लोकसभा चुनाव में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने 62, राजेंद्र शुक्ल ने 61, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 64 जबकि पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने 60 जनसभाएं कीं और कार्यकर्ता बैठक तथा सम्मेलनों को संबोधित किया। इसके अलावा अन्य मंत्रियों और सीनियर विधायकों ने चुनाव प्रचार में भाग लिया, लेकिन दोनों उपमुख्यमंत्रियों से ज्यादा सभाओं में पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आए। वे कांग्रेस नेताओं को भाजपा में लाने के साथ ही चुनाव प्रचार में जुटे रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 72 जनसभा, 18 रोड शो, 16 रथ सभाएं और 65 सम्मेलन, बैठक और संवाद किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ताबड़तोड़ प्रचार किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा सहित 21 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर 66 जनसभाएं कीं। 16 रोड शो सहित कुल 3 लोकसभा क्षेत्रों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। 5 स्थानों पर रात्रि विश्राम किया।

अगर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बात करें तो मप्र में रिकॉर्ड सभाएं, रैली करने के बाद अब वे अन्य राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने जहां अपने 5 माह के कार्यकाल में अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवा दिया है, वहीं लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत करके सभी का मन मोह लिया है। प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटों के लिए मतदान पूर्ण हो चुका है। यहां हर चरण के मतदान के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं का अद्‌भुत आत्मविश्वास देखकर यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कुशल चुनावी रणनीति और नेतृत्व कौशल ने राज्य में भाजपा की शानदार जीत की इबारत लिख दी है। राज्य में पार्टी के चुनाव अभियान की बागडोर थामे मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह सहज दिखाई दिए वह भाजपा की शानदार जीत के पूर्वाभास की गवाही दे रहा था। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के जिस इलाके में गए वहां के लोगों ने उनके सामने दिल खोलकर भाजपा के लिए अपने समर्थन की अभिव्यक्ति करते हुए भरोसा दिलाया कि पिछले लोकसभा चुनावों की तरह ही इस चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने का फैसला तो वे पहले ही कर चुके हैं।

टीम मोदी में शामिल होंगे शिवराज-वीडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार के हैट्रिक बनाने पर मप्र के नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी मिलेगी। मप्र में चार चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। देश में सात चरणों में चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा। इन चुनावों में भाजपा की सरकार बनती है तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी केंद्र में अहम जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। शिवराज को केंद्र में बड़े मंत्रालय की कमान मिल सकती है। वहीं, वीडी को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रदेश के चार बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े नेता है। उन्होंने हमेशा शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों का पालन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री के राज्य से लेकर केंद्र के नेताओं से अच्छे संबंध हैं। उनकी लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजनाओं से प्रदेश में भाजपा ने महिलाओं के बीच में अच्छी पकड़ बनाई है। अब केंद्र में उनको बड़ी भूमिका देकर ईनाम दिया जा सकता है। चर्चा है कि शिवराज को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को प्रदेश की कमान मिलने के बाद से पार्टी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा चुनाव में करीब 18 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की।

मुख्यमंत्री ने चुनाव अभियान के दौरान प्रदेशभर में 139 चुनाव सभाओं को संबोधित किया और 49 रोड शो किए। 25 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में वे भाजपा प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करते वक्त मौजूद रहे। हर जगह मुख्यमंत्री के रोड शो और चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ उनकी अपार लोकप्रियता की गवाही दे रही थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अपार लोकप्रियता का जादू अब मप्र की सीमाओं के बाहर भी सिर चढ़कर बोल रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे दिल्ली, उप्र और बिहार जैसे बड़े राज्यों के प्रवास पर भी जा चुके हैं। मोहन यादव अपने मजबूत तर्कों और तथ्यों पर आधारित संबोधन से मतदाताओं को सहमत करने में सफल रहे। मुख्यमंत्री ने लोगों से जोर देकर कहा कि वे अपने प्रजातांत्रिक अधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपना बहुमूल्य मत उस दल के प्रत्याशी को दें जिसके पास देश को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे ले जाने की इच्छा शक्ति और जज्बा हो। प्रधानमंत्री मोदी के अंदर यह इच्छा मौजूद है इसलिए जनता उन्हें तीसरी बार भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है। मुख्यमंत्री ने चुनावी रैलियों में उन्नत राज्यों की कतार में मप्र का अग्रणी स्थान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी वहीं दूसरी ओर विरोधी दलों पर भी तीखे प्रहार किए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस को इस बात के लिए आड़े हाथों लिया कि उसने अयोध्या में नवनिर्मित भव्य मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव का हिस्सा न बनने का फैसला किया जबकि भगवान राम के चरणों में तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। वे जन-जन के आराध्य हैं। कांग्रेस ने जिस तरह अयोध्या में नवनिर्मित भव्य मंदिर में आयोजित प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव से दूरी बनाई उससे क्षुब्ध होकर तो कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इसीलिए जनता का भी कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बावजूद उनके पद न छोड़ने के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें नैतिकता के आधार पर तत्काल ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। केजरीवाल को यह समझना चाहिए कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दोषमुक्त नहीं किया है, बल्कि केवल अंतरिम जमानत दी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जिन कठोर शर्तों पर जमानत दी है उनका उन्हें पूरी तरह पालन करना चाहिए।

● **सुनील सिंह**

गैर-राप्रसे अफसरों के साथ भेदभाव!

कई सालों के अंतराल के बाद 2015 में जब चार गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों संजय गुप्ता, डॉ. मंजू शर्मा, डॉ. श्रीकांत पांडे और शमीम उद्दीन को आईएएस अवॉर्ड हुआ था, तक कहा गया था कि अब हर साल नॉन डिप्टी कलेक्टर्स का भी आईएएस अवॉर्ड होगा। लेकिन मामला वहीं अटक गया है। प्रदेश के गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बीते 10 साल से प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इस कारण करीब 200 से अधिक अधिकारी आईएएस बनने का सपना लिए ही रिटायर हो गए। साथ ही 100 से ज्यादा अधिकारी इस कतार में हैं। दरअसल, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मापदंडों के मुताबिक आईएएस संवर्ग के 439 में से 22 पदों पर इन अधिकारियों को प्रमोट किया जाना चाहिए। 2015 में इस नियम के तहत 4 अधिकारियों को आईएएस अवॉर्ड दिया गया था। उसके बाद से प्रक्रिया बंद है। जबकि दूसरे राज्य गैर राज्य प्रशासनिक अधिकारियों को हर साल प्रमोशन दे रहे हैं।

प्रदेश में आईएएस संवर्ग के 439 पद हैं। इनमें से 66 फीसदी यानि 293 पद सीधी भर्ती से और 146 पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। इनमें से 15 फीसदी यानि 22 पदों पर गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन मप्र में सभी पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही प्रमोशन दिया जा रहा है। जबकि मप्र के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, उप्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अधिकारियों को प्रमोशन मिल रहा है। मप्र में निर्धारित कोटे के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों को एक दशक से आईएएस अवॉर्ड नहीं मिल पाया है, जबकि डिप्टी कलेक्टरों के समान इन्हें भी इस अवॉर्ड से नवाजने का नियम है। जनवरी, 2024 में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मप्र शासन को पत्र लिखा था, उसके बाद भी राज्य से प्रस्ताव दिल्ली प्रेषित नहीं किया गया है। आईएएस अवॉर्ड देने का जो नियम है, उसके अनुसार प्रतिवर्ष भारत सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सभी राज्य सरकारों को एक पत्र लिखकर प्रस्ताव मांगता है। भारत सरकार ने 2 जनवरी, 2024 को मप्र सरकार को पत्र लिखा था। इसमें उल्लेख था कि 30 जनवरी तक प्रस्ताव भेजा जाए, लेकिन अब तक भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा गया। नॉन डिप्टी कलेक्टर्स यानी राजपत्रित अधिकारियों का कहना है कि आईएएस अवॉर्ड के लिए उपलब्ध पदों की संख्या 20 है। जिन पर करीब 10 वर्ष से किसी भी अधिकारी को लाभ नहीं मिल पाया है। राजपत्रित अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2015 से अवॉर्ड की प्रक्रिया ठप पड़ी है। इस वर्ष भी मप्र सरकार ने भारत शासन के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रस्ताव नहीं भेजा है, जबकि नियमानुसार प्रतिवर्ष जनवरी से मार्च के बीच यह प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को पहुंच जाना चाहिए, ताकि सभी दस्तावेजों का परीक्षण कर नॉन डिप्टी कलेक्टर्स को आईएएस अवॉर्ड से नवाजा जा सके। आईएएस अवॉर्ड की चाहत रखने वाले हर साल राजपत्रित अधिकारी रिटायर्ड हो रहे हैं। राजपत्रित अधिकारियों के लिए डिप्टी कलेक्टरों की तरह आईएएस अवॉर्ड देने के लिए सेवा आयु का निर्धारण है। जिन अधिकारियों ने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली अच्छी है, न्यायालयीन प्रकरण नहीं है। ऐसे अधिकारियों की सूची शासन तैयार करता है और प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाता है। विभिन्न विभागों में वर्ष 2015 से अभी तक लगभग 200 राजपत्रित अधिकारी रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग अमर सिंह परमार का कहना है कि मैं आईएएस अवॉर्ड की प्रतीक्षा में रिटायर्ड हो गया हूं, जबकि सभी राज्यों में राजपत्रित अधिकारियों को आईएएस अवॉर्ड देने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। राज्य शासन से मांग भी की गई, लेकिन भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा गया। मप्र राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष डीके यादव का कहना है कि आईएएस अवॉर्ड के लिए 2015 से कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा गया है। पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात की गई, लेकिन इस बार भी प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग सभी विभागों से उत्कृष्ट श्रेणी के अधिकारियों के नाम मांगता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी खाली पदों की तुलना में चार गुना प्लस 4 नाम तय करती है। इन नामों को संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाता है। यूपीएससी मेंबर की अध्यक्षता में कमेटी प्रमोशन पर फैसला करती है। इस कमेटी में प्रदेश के मुख्य सचिव, वरिष्ठतम आईएएस और केंद्र के सरकार के दो अधिकारी शामिल होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार प्रदेश से इस बार नॉन एसएएस के चार अफसर आईएएस बन सकते हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों से 20 नाम छांटे जाएंगे। नियम के मुताबिक एक पद के लिए पांच अफसरों के नाम पर विचार किया जाता है। यानी अफसरों को आईएएस अवॉर्ड देने के लिए 20 नामों का पैनल बनाया जाएगा। जीएडी से ही पैनल संघ लोक सेवा आयोग जाएगी। चारों पदों के लिए डीपीसी दिल्ली में होगी, जिसकी तारीख भी आयोग एवं कार्मिक मंत्रालय मिलकर तय करेंगे।

● **अरविंद नारद**

प्रमोशन में फंस रहा पेंच

विभागों से उत्कृष्ट श्रेणी के अधिकारियों की सूची मांगने का काम सामान्य प्रशासन विभाग की शाखा (1) करती है। आईएएस अवॉर्ड का इंतजार कर रहे अधिकारियों का कहना है कि इस शाखा के प्रमुख पदों पर जबसे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थ हुए हैं। तब से गैर-राप्रसे के नाम ही नहीं मांगे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से 15 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने चाहिए। लेकिन यह भी लिखा गया है कि यह सरकार पर निर्भर करेगा। उनका कहना है कि इससे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति के पद कम हो जाते हैं। सरकार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारी को प्रमोशन देने के लिए इस नियम का उपयोग करती है। गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस के पदों पर पदोन्नत करने के लिए आयु सीमा 56 साल निर्धारित है। ऐसे में लंबे समय से आवेदन नहीं मंगाने से कई योग्य अधिकारी आयु सीमा पूरी करने से अयोग्य हो गए हैं। पूर्व चीफ सेक्रेटरी केएस शर्मा कहते हैं कि सरकार ने जब आईएएस अवॉर्ड का नियम बनाया है तो दूसरी सेवा के प्रतिभावान अधिकारियों को भी मौके देने चाहिए। इससे सरकार को ही अच्छे अधिकारियों की सेवा मिलेगी। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का नुकसान न होने की तर्कों के साथ मौका नहीं देना उचित नहीं है। यह गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ न्याय नहीं होगा।

जल्द रिस्ट्रक्चर होगी मप्र कांग्रेस

विधानसभा चुनाव में हार के बाद और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर भाजपा जॉइन की। भगदड़ के बीच लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने की कवायद शुरू की है। मप्र में चार महीनों तक कांग्रेस के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए सभी बड़े नेता वर्कर्स के साथ मंथन करेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम के अगले ही दिन 5 जून से ही कांग्रेस का मंथन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त तक चलने वाले मंथन में सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर जिलास्तर तक कार्यकर्ताओं की बात सुनकर सुधार के लिए रिपोर्ट बनाएंगे।

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 66 सीटें मिलीं। इस करारी हार के बाद कई हारे हुए उम्मीदवारों ने बूथ पर संगठन को कमजोर बताया था। कई कैंडिडेट्स ने संगठन में पद लेकर काम ना करने वालों को जिम्मेदार ठहराया था। आगामी समय में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और परिसीमन के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बूथ से लेकर जिलास्तर तक संगठन को दुरुस्त करने की कोशिश में जुट गई है। मंथन कार्यक्रम के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर लीडर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, डॉ. गोविंद सिंह, विवेक तन्खा जैसे वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा का प्रभार दिया जाएगा। इसके बाद जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी बूथ स्तर से लेकर मंडलम, सेक्टर लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक लेवल पर बैठक करेंगे। बैठक में नेता भाषण देने के बजाय कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के निर्देश पर मंथन कार्यक्रम में ब्लॉक स्तर पर बैठक लेने वाले नेता कार्यकर्ताओं के बीच से ही चुनौतियों को चिन्हित करेंगे। कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए विषयों की पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके बाद जिला स्तर पर सभी नेताओं की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में जिलेभर में कांग्रेस की कमजोरी और चुनौतियों का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अब संगठन में व्यापक फेरबदल करने के संकेत दिए हैं। चुनाव निपटने के बाद उन्होंने कहा कि कभी भी संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक फेरबदल किया जा सकता है। इसमें इंदौर के ग्रामीण और शहर अध्यक्षों के नाम भी शामिल हैं, वहीं निष्क्रिय नेताओं को पद नहीं देकर सक्रिय युवाओं को पद देने पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग पड़ी हुई है और शहर की कमेटी को पुराने पदाधिकारियों से काम चलाया जा रहा है।

प्रदेश स्तर पर बनेगा कोर ग्रुप

प्रदेशभर में जिलाध्यक्ष जिला प्रभारी, लोकसभा प्रभारी और विधानसभा चुनाव लड़े उम्मीदवार हर ब्लॉक में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। यदि स्थानीय स्तर पर कोई समस्या है तो इसका समाधान लोकल लेवल पर क्या है? इस पर चर्चा होगी। मंथन कार्यक्रम के तहत ब्लॉक से शुरू होकर ये जिला स्तर पर बैठकें होगी। फिर प्रदेश स्तर पर बैठक होगी। प्रदेशभर से आई बातों का डॉक्यूमेंट बनेगा। फिर महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, एसटी कांग्रेस, एससी कांग्रेस को मिलाकर कोर ग्रुप बनाया जाएगा। प्रदेशभर में बैठकों के बाद सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कांग्रेस का तीन दिवसीय अधिवेशन होगा। ये पूरी प्रक्रिया चार महीने चलेगी। इस बीच पीसीसी का गठन हो जाएगा। जिला अध्यक्षों के खाली पद भर दिए जाएंगे। कार्यकर्ताओं को सुना जाएगा। उसके बाद फिर अधिवेशन में प्रस्ताव पास किए जाएंगे। कांग्रेस में अधिवेशन लंबे समय से नहीं हुआ है। इस साल होने वाले अधिवेशन में पीसीसी डेलीगेट, जिलाध्यक्ष विधायक, सांसद, हारे हुए उम्मीदवार, एआईसीसी डेलीगेट, लोकसभा प्रभारी, जिला प्रभारियों सहित करीब डेढ़ हजार नेता, पदाधिकारी शामिल होंगे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित तमाम नेशनल लेवल लीडर शामिल होंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते से ही पटवारी ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी संगठन में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव निपटे, पटवारी ने भोपाल में स्पष्ट कह दिया कि संगठन में व्यापक फेरबदल होगा। इसके पहले कमलनाथ के समय से प्रदेश कांग्रेस भंग पड़ी हुई है। पटवारी ने इसी कार्यकारिणी से काम चलाया और कुछ महत्वपूर्ण पदों पर चुनाव के पहले नियुक्तियां कीं, लेकिन अब बड़े स्तर पर उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव की नियुक्ति की जाना है। जिस तरह से प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चारों चरण के पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और विधायक भाजपा में शामिल हुए और स्थानीय संगठन कुछ नहीं कर पाया। इसको लेकर भी संगठन पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। फिलहाल पटवारी पुरानी कार्यकारिणी से ही काम चला रहे थे। 68 लोगों की कमेटी बनाकर प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह को अप्रूवल के लिए भेजी थी, लेकिन उस पर अभी विचार नहीं हो सका है। इसके साथ ही मीडिया विभाग में जरूर पटवारी ने अपने हिसाब से फेरबदल कर दिया था, जिसमें 32 प्रवक्ता बनाए गए थे। इंदौर शहर की बात की जाए तो यहां अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में गोलू अग्निहोत्री, अरविंद बागड़ी, अमन बजाज, देवेंद्र सिंह यादव, अंकित खड़ायता हैं, वहीं दो कार्यकारी अध्यक्ष लच्छू मिमरोट और टंटू शर्मा भाजपा में चले गए हैं। इसके अलावा शहर में प्रवक्ता भी हैं, जिनमें जौहर मानपुरवाला ही सक्रिय हैं। बाकी संजय बाकलीवाल और धर्मेंद्र गेंदर को भी प्रवक्ता बना रखा है। सनी राजपाल और विवेक खंडेलवाल जैसे नेताओं को संभागीय प्रवक्ता बनाया गया था। सुरजीत के पहले विनय बाकलीवाल, प्रमोद टंडन की कार्यकारिणी से ही काम चला रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने 1350 की कार्यकारिणी को छोटा कर करीब 700 नेताओं की कार्यकारिणी बनाकर तत्कालीन अध्यक्ष कमलनाथ को भेजी थी, जिसकी मंजूरी नहीं मिल सकी।

● **विकास दुबे**

लंबित आश्वासनों की होगी समीक्षा

विधानसभा में सबसे अधिक लंबित आश्वासन नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उपमुख्यमंत्री व लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ला से संबंधित हैं। विधानसभा के जुलाई में होने वाले बजट सत्र के पहले सरकार इसके जवाब भेजने की तैयारी में जुट गई है और इसको लेकर जल्दी ही मुख्य सचिव वीरा राणा संबंधित विभागों के साथ बैठकें भी करने वाली हैं। विधानसभा में आश्वासन, शून्यकाल, प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर और लोक लेखा समिति की सिफारिशों के मामले में कार्यवाही पेंडिंग होने से संबंधित 2438 प्रकरण हैं जिसके निराकरण पर इस बैठक के पहले जोर आजमाइश शुरू हो गई है। शून्यकाल के सबसे अधिक पेंडिंग मामले राजस्व तथा अपूर्ण उत्तर वाले प्रश्नों की कैटेगरी के प्रकरण जीएडी से संबंधित हैं।

संसदीय कार्य विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि विधानसभा के हर सत्र के पहले मुख्य सचिव द्वारा विधानसभा के लंबित कार्यों (शून्यकाल, अपूर्ण उत्तर वाले प्रश्न आश्वासन तथा लोक लेखा समिति की सिफारिशें) की समीक्षा की जाती है। विभाग के संज्ञान में आया है कि विभागों और संसदीय कार्य विभाग की लंबित कार्य निपटाने की संख्या में काफी भिन्नता है। इसलिए विधानसभा सचिवालय द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संसदीय कार्य विभाग पेंडिंग मामलों की सूची तैयार कराकर इसके निराकरण की वास्तविक अपडेट चाहता है। इसको लेकर विभाग वार बैठकें भी बुलाई गई हैं जिसकी तारीख तय कर दी गई है।

संसदीय कार्य विभाग ने कहा है कि विधानसभा में आश्वासन के पेंडिंग मामलों की कुल संख्या 1311 है। इसमें सबसे अधिक 164 नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से संबंधित हैं। इसके अलावा 141 लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री व उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, 129 स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और 108 राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के विभाग से संबंधित हैं। पेंडिंग आश्वासन प्रकरणों की कैटेगरी में गृहमंत्री डॉ. मोहन यादव के विभाग के 83, पंचायत और ग्रामीण विकास के मंत्री प्रहलाद पटेल के विभाग के 76, जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह के 70 केस हैं। साथ ही जीएडी के 40, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के 54, लोक निर्माण के 53, पीएचई और जल संसाधन के 52-52, उच्च शिक्षा के 28, सहकारिता के 23, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के 20, महिला और बाल विकास तथा वन के 19-19, आयुष के 18, अनुसूचित जाति कल्याण के 17, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास व श्रम के 14-14, खनिज साधन व परिवहन के 13-13, वित्त और नर्मदा घाटी विकास के 12-12, खेल और युवा कल्याण के 9, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन के 8, धार्मिक न्यास और धर्मस्व के 7, योजना, आर्थिक सांख्यिकी, सामाजिक न्याय और निशक्तजन के 6-6, वाणिज्यिक कर के 4 सवालों के आश्वासन के जवाब दिए जाने बाकी हैं। साथ ही संस्कृति, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास, एमएसएमई, पर्यटन विभाग के तीन-तीन, विमानन, पशुपालन एवं डेयरी, जनसंपर्क, जेल विभाग के दो-दो तथा पर्यावरण विभाग से संबंधित एक आश्वासन पेंडिंग है।

विधानसभा में शून्यकाल के पेंडिंग मामलों में सबसे अधिक दस मामले राजस्व विभाग से संबंधित हैं। इसके अलावा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के छह, स्कूल शिक्षा विभाग के पांच, जनजातीय कार्य विभाग के चार मामले पेंडिंग हैं। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग, गृह, सहकारिता, पीएचई, उच्च शिक्षा, परिवहन, महिला और बाल विकास, वन, खनिज साधन, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास, नर्मदा घाटी विकास, संस्कृति, पर्यटन विभाग के एक-एक, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, श्रम, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, लोक निर्माण विभाग के दो-दो, नगरीय विकास और आवास विभाग, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, जल संसाधन विभाग के तीन-तीन केस हैं जिसका जवाब भेजा जाना है। शून्यकाल के कुल पेंडिंग मामलों की संख्या 56 है।

● **जितेंद्र तिवारी**

सबसे अधिक 188 अपूर्ण उत्तर सामान्य प्रशासन विभाग के

विधायकों द्वारा किए जाने वाले सवालों के पूरे जवाब नहीं दिए जाने के चलते अपूर्ण उत्तर की कैटेगरी में शामिल किए गए सवालों में सबसे अधिक 188 सामान्य प्रशासन विभाग के हैं। इसके बाद किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के 166, गृह विभाग के 129, नगरीय विकास और आवास विभाग के 59, सहकारिता के 46, जनजातीय कार्य विभाग के 44, पंचायत और ग्रामीण विकास तथा वित्त विभाग के 37-37, स्कूल शिक्षा के 34, राजस्व के 32, योजना आर्थिक सांख्यिकी व धार्मिक न्यास और धर्मस्व के 26-26, जल संसाधन विभाग के 24 अपूर्ण उत्तर हैं जिनका जवाब भेजना बाकी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति कल्याण के 19, परिवहन के 18, वाणिज्यिक कर के 15, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के 14, उच्च शिक्षा के 13, महिला और बाल विकास व तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के 9-9, पीएचई, खनिज साधन, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, जनसंपर्क विभाग के छह-छह सवालों के पूर्ण उत्तर दिए जाना बाकी है। खेल और युवा कल्याण विभाग के तीन, लोक निर्माण के 2, विधि और विधायी कार्य, पर्यावरण, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, एमएसएमई, सामाजिक न्याय और निशक्तजन, संस्कृति, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा विभाग के एक-एक सवाल का भी जवाब अभी जाना है। अपूर्ण उत्तर की कैटेगरी वाले सवालों की कुल संख्या 994 है।

मप्र में 42.27 लाख परिवार प्यासे

मप्र में जिस तेजी से गर्मी बढ़ रही है उसी तेजी से जलाशयों के जल संग्रहण में गिरावट आई है। वहीं जलस्तर में गिरावट के कारण सरकार नलकूप योजनाओं की सांस फूलने लगी है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के 42.27 लाख परिवारों के सामने सबसे अधिक परेशानी खड़ी हो गई है, जिनके घरों में नल जल योजना का कनेक्शन नहीं है। प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पेयजल संकट बरकरार है। ग्रामीण रोजाना नालों, धारों और नदियों से पानी ढोकर अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं। सड़क से दूरी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना भी पूरी तरह धराशायी हो गई है। इन पेयजल योजनाओं से एक बूंद पानी नहीं टपक रहा है।

सीहोर जिले के पठारी क्षेत्र में पेयजल संकट दिन पर दिन गहरा रहा है। यहां की आठ वर्षीय संध्या हर रोज कुएं से एक-एक बाल्टी पानी के लिए जद्दोजहद करती है। ऐसे में उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। पानी के फेर में उसकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही। उसके गांव में अब तक नल कनेक्शन नहीं लगा है। प्रदेश में पानी के नाम की यह दर्दभरी कहानी अकेले संध्या की नहीं है बल्कि 42.27 लाख घरों को नल कनेक्शन का इंतजार है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से वर्ष 2026 तक प्रदेश के सभी 1.11 करोड़ से अधिक घरों में नल कनेक्शन से शुद्ध पानी देने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक 69.55 लाख घरों में ही नल कनेक्शन हुए हैं। आंकड़े बता रहे कि 52 में 2 जिले बुरहानपुर और निवाड़ी में ही हर घर नल कनेक्शन लगे हैं। प्रदेश के 50,997 ग्रामों में से 13,264 गांवों में हर घर कनेक्शन हुआ है जबकि 36 हजार से अधिक गांवों में काम चल रहा है। वहीं 900 गांवों में अब तक पानी पहुंचाने का काम ही शुरू नहीं हुआ है। जबकि सरकार पानी के नाम पर अब तक करीब 13 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। बुंदेलखंड के पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और सागर के कई गांवों में जलसंकट है। पन्ना के रैपुरा तहसील के एक दर्जन गांवों के हैंडपंप और कुएं सूख गए हैं। 70 वर्षीय रामबाई कहती है कि एक-एक डिब्बा पानी के लिए चिलचिलाती धूप में एक-एक किलोमीटर तक आना-जाना पड़ रहा है। रीवा में कलेक्टर को बैठक में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 मीटर तक जलस्तर नीचे चला गया है। अलीराजपुर, मंडला, बड़वानी, झाबुआ, देवास, अशोकनगर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गंभीर रूप ले रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल कनेक्शन देने में छतरपुर जिला सबसे पीछे है। यहां अब तक 37 प्रतिशत ही प्रगति है यानि 2.47 लाख में 92 हजार घरों में ही नल कनेक्शन हुए हैं।

एक तरफ जल निगम के एमडी केवीएस चौधरी का कहना है कि मार्च 2026 तक हर घर नल कनेक्शन देने का टारगेट है। दरअसल, डीआई पाइप की सप्लाई कम हो रही है, ओव्हरहेड टैंक बनाने वाले एक्सपर्ट भी कम हैं। फॉरेस्ट परमिशन मिलने का बड़ा चैलेंज रहता है। फिर भी हम तय समय में हर घर में नल कनेक्शन दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि कई क्षेत्रों में नल-जल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। कटनी जिले में नल-जल योजना के दो पंप हाउस पर ठेकेदार ने ताले लगवा दिए हैं। ऐसे में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। जिसकी शिकायत जनपद अध्यक्ष ने एसडीएम और कलेक्टर से की है। यह मामला ग्राम ढीमरखेड़ा का है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार नल-जल योजना का आधा अधूरा काम कर पंचायत को हैंडओवर करने के लिए दबाव बना रहा था। जिसके बाद ग्राम पंचायत ने मामले की जानकारी जनपद अध्यक्ष सुनीता दुबे को दी। इस मामले की शिकायत उन्होंने लिखित रूप से कलेक्टर अवि प्रसाद और एसडीएम विंकी सिंहमारे से की है। जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत ढीमरखेड़ा, खमतरा, कछार गांव में ठेकेदार मनमानी काम कर नल-जल योजना हैंडओवर लेने के लिए ग्राम पंचायत को दबाव बना रहा है। जनपद अध्यक्ष ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

पीएचई विभाग की वेबसाइट के अनुसार प्रदेश में कुल मिलाकर 18192 गांव में जल योजनाओं के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना सरकार ने बनाई थी। 2023-24 की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी आंकड़ों में 17900 गांवों में नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंच चुका है और केवल 292 गांव ऐसे हैं, जिनमें नल जल योजना के माध्यम से पानी नहीं पहुंचा। आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में मात्र 300 गांव ही ऐसे बचे हैं, जिनमें नल जल योजना के माध्यम से पानी नहीं पहुंचा। थोड़ी ठीक-ठाक स्थिति दमोह, पन्ना और सागर जिलों की है क्योंकि यहां भारत सरकार में जलशक्ति मंत्री रहे प्रहलाद पटेल सांसद थे। इसी दौरान उन्होंने इस पूरे इलाके में गांव-गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डलवा दी थी। इसलिए इस इलाके में पथरीली जमीन होने के बाद भी पाइपलाइन के जरिए आने वाले पानी से गर्मियों में पानी की समस्या नहीं होती।

● **प्रवीण सक्सेना**

2900 करोड़ में बने नलों के ढांचे, पानी एक बूंद भी नहीं पहुंचा

अशोकनगर जिले में सरकार जलसंकट को दूर करने के लिए 2900 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राजघाट डैम का पानी पाइपलाइन के जरिए अशोकनगर और गुना के गांव तक पहुंचेगा। 3 सालों से काम भी चल रहा है। पीएचई विभाग ने भी नल जल योजना के तहत 128 गांवों में नलों से पानी सप्लाई का दावा किया, लेकिन हकीकत इससे एकदम उलट है। जिन गांवों में नलों से पानी सप्लाई होना बताया जा रहा है वहां के लोगों को 1 से डेढ़ किमी दूर से खेतों से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। जिले में जल जीवन मिशन के तहत 196 योजनाएं संचालित हैं, जिसमें से 164 योजनाएं पूर्ण भी हो चुकी हैं। विभाग दावा कर रहा है कि 128 योजनाएं चालू हैं। गांवों में 1 लाख लीटर और 2 लाख लीटर की टंकियां क्रमशः 14 लाख एवं 18 लाख रुपए से तैयार तो कर दी हैं, लेकिन इनमें पानी भरने तक के स्त्रोत नहीं है।

लोकसभा चुनाव के चलते 1.45 लाख करोड़ रुपए के अंतरिम बजट से काम चला रही मप्र सरकार 1 जुलाई से शुरु होने वाले मानसून सत्र में चालू वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी। इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरु कर दी हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बार बजट में सरकार जहां जनता को कई सहूलियतें दे सकती है, वहीं संविदाकर्मियों और मजदूरों का मेहनताना बढ़ाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने खाका तैयार करना शुरु कर दिया है। गौरतलब है कि फरवरी में विधानसभा में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने नए वित्तीय वर्ष का अंतरिम बजट पेश किया था। यह बजट अप्रैल से जुलाई के लिए है।

लेखानुदान से काम चला रही प्रदेश सरकार 1 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। वित्त विभाग बजट की तैयारियों में जुट गया है। सरकार का 2024-25 का पूर्ण बजट का अनुमान 3.48 लाख करोड़ है। इसमें लेखानुदान के 1.45 लाख करोड़ रुपए भी शामिल होंगे। अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियां 2.52 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें राज्य कराधान से आय 96 हजार करोड़ रुपए है।

वित्त विभाग ने 2024-25 के बजट अनुमान और तैयारी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें विभाग ने वेतन-भत्ते, ऋण भुगतान और 15वें वित्त आयोग के लिए बजट अनुदान को प्राथमिकता में रखने को कहा है। प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी में पूर्ण बजट पेश नहीं किया था। सरकार लेखानुदान लेकर आई थी। इसमें तीन महीने का सरकार की योजनाओं और वेतन भत्तों के खर्च का बजट जारी किया गया था। इसमें किसी तरह के नए कर संबंधी नए प्रस्ताव और व्यय के नए मद शामिल नहीं किए गए थे। जानकारों का कहना है कि सरकार अब लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में अपना पूर्ण बजट लेकर आ सकती है। अब राज्य में चार से पांच साल बाद चुनाव हैं। ऐसे में सरकार कठोर निर्णय भी ले सकती है। यह समय सरकार के लिए सख्त निर्णय लेने के लिए आदर्श होता है। सरकार जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में बजट पेश कर सकती है।

वित्त विभाग ने विभागों से कहा है कि नई योजनाओं के प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति के बाद ही भेजें। इसमें उद्देश्य और लाभ की जानकारी का विवरण भी भेजने को कहा गया है। वहीं, जिन योजनाओं को बंद किया जा रहा है, उसकी जानकारी भी देने को कहा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उपयोजना के लिए पर्याप्त राशि रखने को कहा गया है। वित विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि आवश्यक व्यय के प्रावधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किए जाएं। केंद्र सरकार के अनुसार **महंगाई भत्ता** और राहत के लिए बजट स्थापना व्यय में रखें। इसकी गणना ठीक से कराएं, ताकि कोई परेशानी न आए। केंद्र सरकार की सभी परियोजनाओं के लिए राज्यांश पर्याप्त मात्रा में रहे। कोई ऐसी योजना, जो केंद्र सरकार द्वारा भी संचालित की जा रही है, तो उसके संविलियन का प्रस्ताव दें। जिन योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण हो चुके है, उन्हें बंद करने की प्रक्रिया करें। सभी विभागों को मई अंत तक प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।

मप्र सरकार के बजट में साल-दर-साल बढ़ोतरी हो रही है। पिछले तीन वर्षों में बजट में एक लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मप्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 लाख 31 हजार 375 करोड़ का बजट पेश किया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान 3 लाख 48 हजार 986 करोड़ रुपए का होगा। उल्लेखनीय है कि बजट तैयार करने की मानक प्रक्रिया यह है कि वित्त विभाग पहले सभी विभागों को अपनी मांगें भेजने के लिए लिखता है। दूसरे चरण में अधिकारियों की उप सचिव

बजट से पहले दूसरे राज्यों में मौजूद संपत्ति की बनेगी सूची

प्रदेश सरकार अब मप्र से बाहर मौजूद विभिन्न विभागों का डाटा जुटाएगी। इसी के चलते बजट की तैयारियों में जुटे वित्त विभाग ने प्रदेश के बाहर चल और अचल संपत्ति के रूप में मौजूद संपत्ति का ब्यौरा सभी विभागों से मांगा है। इसमें संपत्ति के मौजूदा स्वरूप के बारे में जानकारी देने के साथ उसकी कीमत की जानकारी भी चाही गई है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया है कि मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के बाहर मौजूद संपत्तियों की समीक्षा जल्द की जानी है। इसलिए विभाग प्रमुख राज्य के बाहर स्थित संपत्तियों और उनके रखरखाव की जानकारी 22 मई तक वित्त विभाग को उपलब्ध कराएं। वित्त विभाग के निर्देश के बाद अब विभाग प्रमुख प्रदेश के बाहर मौजूद प्रापर्टी के रिकार्ड तैयार कराने में जुट गए हैं। उधर प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि मप्र के विभिन्न विभागों से संबंधित प्रापर्टी 10 से 12 राज्यों में है। इसमें सबसे अधिक संपत्ति धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग से संबंधित है। यह संपत्ति दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत के राज्यों, उप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में है।

स्तर की बैठक होती है। विभिन्न विभागों के उप सचिव चर्चा कर सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी मांगों को सूचीबद्ध करते हैं। फिर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के प्रमुखों की बैठक होती है। इसमें बजट प्रस्ताव तैयार कर इसे वित्त मंत्री स्तर पर भेजा जाता है। इसके बाद सरकार बजट को अंतिम रूप देती है।

मप्र में संचालित ऐसी कॉमन स्कीम्स जिनका एक ही कार्य के लिए संचालन किया जा रहा है, उन योजनाओं को मर्ज किया जाएगा। वित्त विभाग ने विभागों से कहा है कि केंद्र की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं को मर्ज कर दिया जाए। विभागों को जो भी नई योजना शुरू करनी है, उसके लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति के साथ वित्त विभाग को भेजना होगा। जुलाई में विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट की तैयारियों में जुटे वित्त विभाग ने कहा है कि इस बार भी जेंडर बजट, चाइल्ड बजट और कृषि बजट वित्त मंत्री अलग से बताएंगे। वित्त विभाग की बजट तैयारियों को लेकर जारी निर्देश में कहा है कि **इन योजनाओं** के लिए बजट सीलिंग के अंतर्गत बजट तय किए जाएंगे। नई योजनाएं वित्त विभाग के स्तर पर ही खोली जाएंगी। भारत सरकार की नई योजनाओं के लिए केंद्र के बजट में प्रावधान होने पर ही राज्य के बजट में ऐसी नई योजना का प्रावधान किया जाएगा। जिन योजनाओं में कंटीन्यूटी की जरूरत नहीं होगी, उसमें बजट प्रस्ताव नहीं दिए जाएंगे। एक समान योजनाएं होने की स्थिति में ऐसी योजनाओं के संविलियन का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजना होगा। यह निर्देश भी दिए गए हैं कि पिछले वित्त वर्ष में जिन योजनाओं के प्रावधान किए गए हैं, उन सभी योजनाओं के प्रस्ताव विभाग वर्ष 2024-25 के बजट के लिए भेजेंगे और जिनमें बजट की जरूरत नहीं है, उसमें शून्य बजट की जानकारी दी जाएगी।

वाणिज्यिक कर, ऊर्जा, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के साथ एमएसएमई, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा तथा विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व और लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा नियमों के आधार पर पिछले

दो सालों से अगर कहीं छूट दी जा रही है और इससे विभाग के राजस्व पर प्रभाव पड़ रहा है तो इसकी जानकारी भी वित्त विभाग को ऐसे विभागों की ओर से देना होगी। यदि किसी विभाग में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी की अब तक पदस्थापना नहीं है लेकिन आने वाले समय में पदस्थापना संभावित हो तो विभाग के प्रस्ताव में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। जिन योजनाओं को आगामी वर्षों में संचालित नहीं किया जाना है उनका व्यय बजट सीलिंग में शामिल कर विभाग बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेंगे। नई नियुक्तियों और सेवानिवृत्ति के चलते आने वाले व्यय भार की जानकारी विभागों को अलग से भेजना है। विभाग ने कहा है कि महिलाओं की योजनाओं के मद्देनजर जेंडर बजट, बच्चों के सर्वांगीण विकास के चलते चाइल्ड बजट और कृषकों को लाभ दिलाने के लिए इनसे संबंधित बजट का प्रावधान बजट प्रस्ताव में अलग से देना होगा। जेंडर बजट और चाइल्ड बजट में उन योजनाओं का उल्लेख अलग से करना होगा जिसमें 100 प्रतिशत बजट लगेगा और उनकी अलग डिटेल देनी होगी जिसमें 30 प्रतिशत बजट खर्च प्रस्तावित होगा।

राज्य सरकार फरवरी में पूर्ण बजट लेकर नहीं आई। सरकार लेखानुदान लेकर आई। जानकारों ने बताया कि इसका कारण केंद्र की तरफ से योजनाओं और प्रोग्राम के लिए राज्य को मिलने वाले राज्यांश में देरी कारण रहा। केंद्र सरकार भी लोकसभा चुनाव के चलते लेखानुदान लेकर आई। अब वह भी जुलाई में पूर्ण बजट पेश कर सकती है। लेखानुदान में सरकार पूर्ण बजट पेश होने तक राज्य सरकार के खर्चों और योजनाओं के संचालन के लिए राशि को स्वीकृति देती है। गौरतलब है कि मप्र सरकार हर साल फरवरी-मार्च में विधानसभा में बजट पेश करती है। आम चुनाव के कारण इस साल सरकार ने पूर्ण बजट पेश नहीं किया और केंद्र सरकार की तर्ज पर विधानसभा में लेखानुदान (बोट ऑन अकाउंट) लाया गया था। चूंकि लेखानुदान केवल अप्रैल से 31 जुलाई तक चार महीनों के लिए था, इसलिए सरकार को 31 जुलाई से पहले पूर्ण बजट पेश करना है। लेखानुदान के जरिए मिलने वाला पैसा मुख्य बजट का हिस्सा होगा। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्ण बजट की बजाय लेखानुदान लाने का कारण यह था कि राज्य को केंद्र सरकार से हस्तांतरण और विभिन्न योजनाओं में सहायता और अनुदान के रूप में मिलने वाली धनराशि को मंजूरी नहीं दी गई थी।

● **कुमार विनोद**

अब पूर्ण बजट की तैयारी

लोकसभा चुनाव के बीच ही अब चालू वित्तीय वर्ष के नए बजट को लेकर वित्त विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत विभागों से बजट को लेकर चर्चा का दौर शुरू करने की भी तैयारी है, इधर वित्त विभाग ने सभी विभागों से नए बजट को लेकर प्रस्ताव मांगे हैं। यदि कोई विभाग नई योजना संचालित करना चाहता है, तो नई योजनाओं से संबंधी प्रस्ताव हर हाल में 17 जून तक वित्त विभाग को भेजना होगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों को ताकीद किया है कि वे बजट सीलिंग के दायरे में ही तैयार करेंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने जो निर्देश दिए हैं, उसके मुताबिक संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी के लिए 8 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान बजट प्रस्ताव में करना होगा, इसी तरह मजदूरी में भी कम से कम 5 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव विभागों को देना होगा। वहीं डीजल, पेट्रोल जैसे मद में 5 फीसदी बढ़ोतरी की जा सकेगी। लोकसभा चुनाव के कारण प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के लिए केवल लेखानुदान पेश किया गया था। जो 4 माह की अवधि के लिए था। 12 फरवरी को पेश लेखानुदान 1 लाख 45 हजार 229 करोड़ 55 लाख 56 हजार रुपए का था।

चंबल की स्वच्छता की होगी जांच

शासन, प्रशासन से लेकर आमजन में मान्यता है कि चंबल नदी मप्र ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में शुमार है। लेकिन चंबल का पानी कितना स्वच्छ है, यह इंसानों के पीने लायक है भी या नहीं? चंबल के पानी में क्या खूबियां और क्या कमियां हैं? यह तकनीकी तौर पर किसी को नहीं पता। यह पता लगाने के लिए पहली बार चंबल के पानी की जांच होगी। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) अगले महीने से यह जांच शुरू करने वाले हैं, इसके लिए अत्याधुनिक यंत्र व मशीनें लाई जा रही हैं।

चंबल नदी के पानी की जांच के नाम पर राजघाट क्षेत्र में कभी-कभी पानी के सैंपल लेकर जांच होती रही है, लेकिन राष्ट्रीय घड़ियाल सेंचुरी की जद में आने वाले चंबल नदी के 495 किलोमीटर के हिस्से (श्योपुर से लेकर उप्र के पचनदा तक) के पानी की गुणवत्ता जांच पहली बार होने जा रही है। इसके लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के रिसर्चर एवं विशेषज्ञ तीन दिन पहले चंबल घड़ियाल सेंचुरी के अफसरों से मिले हैं। पानी की जांच की प्लानिंग पर काम शुरू हो गया है और जून महीने के पहले सप्ताह से यह काम शुरू हो जाएगा। सेंचुरी प्रशासन के अनुसार 12 से 15 दिन तक सैंपल लेने और साथ ही साथ पानी की जांच का काम चलेगा। जांच परिणाम आने के बाद चंबल के पानी में पाई जाने वाली कमियों को दूर कर नदी को स्वच्छ बनाने के काम शुरू होंगे। चंबल का पानी आगामी साल में मुरैना, ग्वालियर में पेयजल सप्लाई में मिलेगा, इसलिए भी यह जांच बेहद अहम है। चंबल के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा तलहटी से लेकर ऊपर तल पर कितनी है, यह पता लगाने के लिए डिजाल्व ऑक्सीजन जांच होगी। स्वच्छ पेयजल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। चंबल के पानी में कौन-कौन से मिनरल्स कितनी मात्रा में मौजूद हैं, इसकी भी जांच होगी। चंबल नदी के किनारों पर, पानी में कई प्रजाति के छोटे-छोटे वनस्पति पौधे 12 महीने हरे-भरे रहते हैं, इन वनस्पति पौधों से पानी की गुणवत्ता पर क्या असर हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए प्लेंकन जांच होगी।

राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजर रही देश की सबसे साफ नदी में शुमार चंबल नदी में अब शहर का लाखों लीटर गंदा पानी घुल रहा है। जानकारी के मुताबिक, धौलपुर शहर का आधा गंदा पानी नालों के माध्यम से चंबल नदी में गिर रहा है। जिले के राजघाट गांव के पास तीन नालों से बेतहाशा गंदा पानी जाने से चंबल नदी के स्वच्छ पानी में गंदगी समा रही है। इससे जहां जलीय जीवों के जीवन पर संकट के बादल छाए हैं तो वहीं शहरवासियों में चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं। चंबल नदी से ही धौलपुर और भरतपुर तक पानी पहुंच रहा है। इससे शुद्ध पेयजल की बात कहना बेमानी साबित हो रही है। चंबल नदी में स्वच्छ पानी होने के कारण ही इसे घड़ियाल अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। घड़ियाल स्वच्छ पानी में ही निवास करते हैं लेकिन इस चंबल नदी को नगर परिषद ने गंदा कर रखा है। चंबल नदी स्थित राजघाट गांव के पास तीन नालों के माध्यम से शहर का पानी जा रहा है लेकिन इस ओर नगर परिषद, जिला प्रशासन और जलदाय विभाग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। गंदे पानी को चंबल नदी में जाने से रोकने के लिए किसी ने पहल नहीं की है। इससे चंबल दूषित होती जा रही है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय घड़ियाल चंबल सेंचुरी को बचाने के लिए चंबल नदी के तटों से बजरी का खनन रोकने के आदेश दे रखे हैं। जिला मुख्यालय पर करीब-करीब पूरे शहर में सीवर लाइन डाली गई है। जहां छोटी गलियां थीं वहां पर अमृत योजना के तहत सीवर लाइन डाली गई है। इससे करीब दस से बारह हजार मकानों में कनेक्शन दिए गए हैं। इसके बावजूद चंबल नदी में गंदा पानी नालों के माध्यम से जा रहा है। नमामि गंगे में शामिल चंबल नदी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है। इससे आसपास के स्थान को विकसित किया जाएगा, जिससे पानी भी स्वच्छ रहे लेकिन नगर परिषद को इसका ख्याल तक नहीं हैं।

चंबल को बचाने के लिए रेत उत्खनन पर भी प्रतिबंध है और उसी नदी में गंदा पानी छोड़ना इतना गंभीर विषय है। इस नदी में यदि इसी तरह गंदा पानी मिलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इस नदी में रहने वाले जलीय जीवों का तो नामोनिशान मिट ही जाएगा। साथ ही लोगों को मिल रहा पीने का स्वच्छ पानी का स्रोत भी समाप्त हो जाएगा। चंबल नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ अच्छी संख्या में हैं। उनकी संख्या में और वृद्धि करने के प्रयास चल रहे हैं। धौलपुर के नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि हमारे यहां पर चंबल नदी नमामि गंगे प्रोजेक्ट में सम्मलित है। इसमें वर्षों से नालों का गंदा पानी जाता रहा है लेकिन राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण शहर में अमृत योजना और आरयूआईडीपी के द्वारा सीवर लाइन डाली गई है। सीवर लाइन डालने से 80 प्रतिशत तक जो गंदा पानी जाता था वो अब रुक गया है। हमारे यहां दो स्टोपी (गंदे पानी को रोकने के लिए) भी बने हुए हैं। सागरपाड़ा और तगावली में इसका परिशोधन और शुद्धिकरण होता है लेकिन इसके अलावा कुछ पानी सीधे नालों के द्वारा चंबल में जा रहा है। इसके लिए नगर परिषद डब्ल्यूटीपी प्लांट की एक डीपीआर तैयार कर रहा है। वो डीपीआर तैयार होते ही राज्य सरकार को बजट के लिए भेजी जाएगी। बजट स्वीकृत होते ही तुरंत कार्य कराया जाएगा।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

पूर्व की सूक्ष्म जांचों में ऑक्सीजन कम

वैसे तो चंबल के पानी की जांच यदा-कदा होती रही है। साल 2012 और फिर साल 2013 में चंबल घड़ियाल सेंचुरी ने पानी की जांच करवाई थी, जो केवल राजघाट और चंबल नदी पर बने रेलवे पुल के आसपास के पानी की हुई थी। साल 2012 में चंबल के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 7 फीसदी थी, जो साल 2013 की जांच में घटकर 3.4 फीसदी रह गई थी। इसके अलावा पानी में अपशिष्टों की जांच हुई थी, जिसमें साल 2012 में 249 मिलीग्राम प्रति लीटर बताई गई और 2013 में यह बढ़कर 374 मिलीग्राम तक पहुंच गई थी। पेयजल में अपशिष्ट की मात्रा शून्य होनी चाहिए, इस हिसाब से पूर्व में हुई जांच में चंबल के पानी को पीने योग्य नहीं माना गया, लेकिन यह जांच बेहद छोटे स्तर पर हुई थी, पहली बार चंबल घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र के पूरे पानी की जांच हो रही है। डीएफओ चंबल घड़ियाल सेंचुरी मुरैना स्वरूप दीक्षित का कहना है कि चंबल के पानी की जांच पहले बहुत छोटे स्तर पर एक-दो जगहों पर ही हुई है, पहली बार पूरे सेंचुरी क्षेत्र के पानी की जांच डब्ल्यूआईआई के साथ मिलकर करवा रहे हैं, जो जून के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। जांच के परिणाम में जो कमियां मिलेंगी उन्हें दूर कर नदी को स्वच्छ बनाने के काम शुरू होंगे।

बीज के लिए जान की बाजी

मप्र में तकरीबन 7.5 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती होती है। प्रदेश में कुल उत्पादन का 80 फीसदी 4 जिलों में होता है। इनमें से एक जिला है खरगौन। यहां कपास की खेती करने वाले किसान बीज की कमी के कारण परेशान हैं। 17 मई को सुबह करीब साढ़े नौ बजे खरगोन से गुजरने वाले भुसावल चित्तौड़गढ़ हाईवे पर किसानों ने चक्काजाम कर दिया। कुछ ही देर में हाईवे पर वाहनों की कतारें लग गईं। किसानों का आरोप था कि कपास के एक विशेष किस्म के बीज की कालाबाजारी की जा रही है। उन्हें बीज नहीं मिल रहा। खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने किसानों को समझाया और चक्काजाम खत्म करवाया। इसके बाद प्रशासन को बीज वितरण के लिए टोकन व्यवस्था लागू करनी पड़ी।

खरगौन में हर साल कपास के बीज के लिए ऐसी ही मारामारी होती है। दरअसल, बाजार में कपास के बीज की 100 से ज्यादा किस्म हैं, लेकिन किसान केवल दो किस्म रासी 659 और नुजीवुडू के आशा-1 के बीज की ही डिमांड करते हैं। इसके लिए किसान 40 डिग्री तापमान में भी लंबी लाइन लगाने के लिए तैयार हैं। आखिर निमाड़ में इस विशेष किस्म की डिमांड क्यों है, बीज की इतनी किल्लत क्यों है। वहां के एक किसान निमेश का कहना है कि वह रात में ही खरगौन आ गया था। सुबह चार बजे मंडी पहुंचा तो यहां उससे पहले भी कई लोग पहुंचकर लाइन लगा चुके थे। निमेश के पास 10 एकड़ खेत है। इसमें खरीफ का कपास लगाने के लिए उसे कम से कम 10 पैकेट बीज की जरूरत है। वह जिस ब्रांड का बीज चाहता है वह बाजार में नहीं है। निमेश इस बात से नाराज दिखे कि प्रशासन एक किसान अधिकार पत्र पर दो पैकेट बीज उपलब्ध करा रहा है। निमेश का कहना है कि उसके परिवार का भविष्य अच्छी फसल पर निर्भर है। अगर उसका मनचाहा बीज नहीं मिला तो पर्याप्त उत्पादन नहीं होगा, इससे उसकी आय प्रभावित होगी। निमेश जैसे कई किसान इस समय इसी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। किसान नेता गोपाल पाटीदार कहते हैं कि वैसे तो बाजार में 100 से ज्यादा किस्म के कपास के बीज मौजूद हैं, लेकिन किसानों के बीच रासी सीड्स के रासी 659 और नुजीवुडू के आशा-1 की ही मांग है। इसके पीछे किसानों का अपना गणित है।

दरअसल, इस किस्म के बीज से एक एकड़ क्षेत्र में करीब 12 क्विंटल कपास का उत्पादन होता है। यह पूरा उत्पादन दो बार की तुड़ाई में निकल आता है। इनमें कपास का बीज भी अधिक निकलता है। कपास चुनने वाले मजदूर 6 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मजदूरी लेते हैं। इन किस्मों का वजन अधिक है, इसलिए मजदूर आसानी से मिलते हैं। वहीं, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक खेत खाली हो जाता है। इससे किसान गेहूं-चने की अगली फसल लगाकर दोहरा फायदा ले पाता है। जो दूसरी किस्म के बीज हैं उनका उत्पादन 5-6 क्विंटल प्रति एकड़ ही है। वहीं उनकी चुनाई पांच से छह बार करनी पड़ती है। ऐसे में मजदूरों को कम भाव मिलता है और मेहनत अधिक करनी पड़ती है। इसका खेत भी दिसंबर तक खाली होता है, ऐसे में गेहूं की बुवाई भी देर से होती है। खरगौन के कृषि विभाग के उप संचालक एमएल चौहान का कहना है कि जिले में खरीफ का एरिया 4 लाख 16 हजार हेक्टेयर है। उसमें से 2 लाख 25 हजार हेक्टेयर में कपास की फसल लगेगी। इतने खेतों के लिए 9 लाख 78 हजार 891 पैकेट बीज की जरूरत होगी। अभी तक 4 लाख 68 हजार पैकेट आ भी चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिस विशेष किस्म के बीज की मांग किसान कर रहे हैं, उसकी उपलब्धता 37 हजार पैकेट ही है। संबंधित कंपनी के अधिकारियों से प्रशासन संपर्क में है। उनसे और माल मंगाया जा रहा है। उसकी दूसरी खेप भी जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन कितनी भी मशक्कत की जाए, ये कंपनियां लाख-डेढ़ लाख पैकेट से अधिक की सप्लाई नहीं कर पाएंगी।

वहीं, कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि कपास की बुवाई का सही समय 25 मई के बाद है, लेकिन ग्रामीण परंपरा में अक्षय तृतीया से खेती का काम शुरू हो जाता है। इस बार 10 मई को अक्षय तृतीया थी। किसानों ने बुवाई का मुहूर्त तय कर उसी दिन बीज मांगना शुरू कर दिया। तब पता चला कि बाजार में इतना बीज तो है ही नहीं। बीज की कमी को लेकर कंपनी के प्रतिनिधि कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। हालांकि उनका कहना है कि बीज का उत्पादन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में होता है। पिछले सीजन में तूफानी बरसात की वजह से फसलों को नुकसान हुआ था। जो उत्पादन हुआ उसका बड़ा हिस्सा टेस्टिंग में फेल हो गया। इसकी वजह से बीज कम मात्रा में आए। कृषि विभाग के उपसंचालक एमएल चौहान ने भी कंपनी के इस दावे की पुष्टि की। कृषि विभाग के अधिकारी एक-दो किस्मों पर निर्भरता को खतरनाक बता रहे हैं। किसान नेता कमलेश पाटीदार कहते हैं कि इन बीजों में सबसे अधिक पीलेपन और कम जर्मिनेशन की समस्या आती है, लेकिन किसानों के मन में ज्यादा उत्पादन की बात बैठ गई है तो उन्हें किसी भी कीमत पर वही बीज चाहिए। कृषि विभाग के उपसंचालक एमएल चौहान का कहना है कि एक ही किस्म के बीजों पर निर्भरता के अपने जोखिम हैं।

● **अक्स ब्यूरो**

कंपनियों ने खुद किया किल्लत का प्रचार

भारतीय किसान संघ के कमलेश पाटीदार का कहना है कि कंपनियों ने ही बीज की किल्लत को प्रचारित किया है। कंपनियां अपनी मोनोपोली स्थापित करना चाहती हैं। पाटीदार कहते हैं कि जब किसान मंडी आता है तो इन कंपनियों के प्रतिनिधि किसानों के साथ फोटो सेशन करवाते हैं। कंपनियां किसानों से कहती हैं कि उनके बीज की वजह से इतनी अच्छी फसल हुई है। सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। इस तरह किसान उनके झांसे में आते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक वे गांव-गांव में जाकर किसानों से कहते हुए देखे गए कि इस बार उनका बीज कम आ रहा है। इस तरह से उन्होंने किसानों को बीज की कमी बताकर उन्हें चिंता में डाल दिया। किसानों, अधिकारियों और बीज कंपनियों से बातचीत के बाद एक तस्वीर यह भी निकलकर आई कि निमाड़ क्षेत्र के किसान ज्यादा उत्पादन चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में इन बीजों की किल्लत नहीं देखी गई। इसके पीछे गुजरात से अवैध बीटी कॉटन के बीज की सप्लाई रही है। गुजरात के कुछ किसानों ने निजी स्तर पर प्रयोग कर कपास के बीज की नई किस्में विकसित की हैं। स्थानीय स्तर पर इसे 4जी कहा जाता है। यह बीज गुजरात से चोरी-छिपे बड़वानी, खरगोन, खंडवा के ग्रामीण बाजारों तक पहुंच जाता है।

अवैध कॉलोनियां होंगी अधिग्रहित

मप्र सरकार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जल्द एक्शन लेगी। प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनी का अधिग्रहण कर सर्वे करेगी। सर्वे के बाद कई क्षेत्रों में रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगाई जाएगी। प्रशासक नियुक्त कर जिला प्रशासन खाली प्लॉट बेचेगा। जमीन बेचकर वहां विकास कराएगा। संबंधित कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मप्र में 2500 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं।

राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने कई अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री और नामांतरण को रोक लगा दी है। इसके बाद मप्र के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्राधिकार में सभी कॉलोनियों का अधिग्रहण करेंगे और जिला प्रशासन द्वारा उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। विक्रय से बचे प्लॉट शासन की संपत्ति होंगे। कॉलोनाइजर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जिले स्तर पर कॉलोनाइजर को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। जरूरी अनुमति प्रस्तुत नहीं करने पर शहर में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन जमीन को कब्जे में लेगी। फिर प्रशासक नियुक्त कर वहां के खाली प्लॉट बेचेगा। इससे आए पैसे से उस कॉलोनी में विकास कार्य किया जाएगा। इसमें संबंधित कॉलोनाइजर पर एफआईआर भी कराई जाएगी। सर्वे में नई बनने वाली और पुरानी कॉलोनी को जोड़ा गया है। इसमें वह कॉलोनी भी शामिल हैं, जिन पर पहले एफआईआर हो चुकी है। कॉलोनी की जमीन बेचने से मिले पैसों से वहां बिजली, पानी, सड़क, नाली और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसी सिलसिले में अभी भोपाल के सिंकदराबाद, पिपलिया जाहिरपीर, अरेड़ी, सेवनिया ओंकारा और छावनी पठार में रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगाई गई है।

अवैध कॉलोनी के खिलाफ अब तक एक साथ कभी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन शिकायत मिलने पर कॉलोनाइजर को नोटिस देता था। उसके बाद वहां पर सिर्फ सड़क और बाउंड्रीवॉल तोड़ दी जाती थी। अब प्रशासन जमीन पर कब्जा लेकर उसे विकसित करेगा। साल 2016 के बाद पूरे प्रदेश में बनीं 2500 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध नहीं किया जाएगा। पूर्व में 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की चर्चा थी, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और नई सरकार ने अवैध कॉलोनियों को बनने से रोक कर शहरों का विकास उनकी प्लानिंग के अनुसार करने का निर्णय लिया है। सरकारी रिकॉर्ड में भोपाल में अवैध कॉलोनियों की संख्या 576 है। इनमें से 2016 के पहले बनी 320 कॉलोनियों को वैध किया जा चुका है। 2016 के बाद बनी 255 कॉलोनियों को पूरी तरह अवैध माना गया है। साल 2023 के अंत तक सभी 255 कॉलोनियों पर एफआईआर हो चुकी है। नए सर्वे में एफआईआर होने वाली कॉलोनी को भी शामिल किया जाएगा। आयुक्त नगरीय विकास विभाग भरत यादव का कहना है कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण रोकने और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में कार्रवाई शुरू हो रही है। किसी भी स्थिति में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का कोई भी विकल्प अब नहीं है। वहीं भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि शहर की सभी तरह की अवैध कॉलोनियों का सर्वे किया जाएगा। पहले नोटिस, फिर नियमानुसार एफआईआर, उसके बाद जमीन को कब्जे में लेकर वहां प्रशासक के माध्यम से जरूरी काम कराए जाएंगे।

बता दें कि शहर में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनी बन चुकी है और नई कॉलोनी में प्लॉट काट रहे हैं। सीवेज से लेकर रोड पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। अब ऐसी नई अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी शुरुआत हुजूर से होगी, ऐसी 15 कॉलोनी चिन्हित हो चुकी हैं। इसमें अयोध्या नगर से लगी हुई अरेडी की सबसे ज्यादा कॉलोनी शामिल है। यहां पर कृष्ण धाम कॉलोनी में लगातार क्रेशर बस्ती के पास अवैध तरीके से कॉलोनी काटी जा रही है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि सबसे पहले उन कॉलोनी पर कार्रवाई होगी, जहां अभी तक सिर्फ कॉलोनी के नाम पर रोड बनाकर प्लॉट काटे जा रहे हैं। उसके बाद ऐसी कॉलोनियों को बुलडोजर से नष्ट किया जाएगा। उसके बाद ऐसी कॉलोनियां, जहां कुछ निर्माण हो गया है। वहां सर्वे के अनुसार कॉलोनाइजर के बाकी प्लाटों को अपने अंडर में लेकर निगम मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अवैध कॉलोनी में निर्माण को छोड़कर खाली प्लॉट नगर निगम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। निगम प्लॉट बेचकर उस कॉलोनी में विकास काम करेगी, किसी घर को नहीं तोड़ा जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि सभी एसडीएम को शहर में सर्वे करने को कहा है। सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अवैध कॉलोनियों का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्हें नगर निगम को दिया जाएगा।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

6 महीने में कट गईं 600 से अधिक अवैध कॉलोनियां

अवैध कॉलोनियों पर सरकार ने भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। राजधानी भोपाल में ही बीते 6 महीने में शहरी सीमा और उससे लगे ग्रामीण क्षेत्रों में 600 से अधिक अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई हैं, जिनमें सिर्फ कॉलोनाइजर द्वारा डायवर्जन लेकर मनमाने दाम पर प्लाट बेचे जा रहे हैं। दरअसल, विधानसभा चुनाव के पहले तो कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई तो उसके साथ ही कार्रवाई पर भी विराम लग गया। अधिकारी चुनाव में व्यस्त रहे, दूसरी तरफ कॉलोनाइजरों द्वारा जमीन मालिकों के साथ मिलकर प्लॉटिंग शुरू कर दी गई। बता दें कि मप्र सरकार ने मई में दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। साथ ही यह भी आदेश दिए थे कि नई अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर की नगर निगम सीमा और उससे लगे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अवैध प्लाटिंग की जा रही है, उनमें बैरसिया, लांबाखेड़ा, ईंटखेड़ी, अचारपुरा, अरवलिया, परवलिया, दुपड़िया, गोलखेड़ी, भैरोपुरा, खामखेड़ा, मस्तीपुरा, श्यामसेमरा, देवलखेड़ी, जगदीशपुर, पुरामनभावन, इमलिया, मालीखेड़ी, दामखेड़ा, कोलुआ, परवलिया सड़क, खजूरी कलां, ईटखेड़ी छाप, मुगालिया छाप, रातीबड़, नीलबड़, सूरजनगर, सिंकदराबाद, बिलखिरिया, बंगरसिया, जाटखेड़ी, सलैया, कोलार, सूखीसेवनिया, भानपुर, आनंद नगर क्षेत्र शामिल हैं।

साइबर अपराधियों का आतंक

2024 के शुरुआती चार महीनों में ही साइबर अपराधियों ने भारतीयों को 1750 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया! ये जानकारी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 7 लाख 40 हजार से ज्यादा शिकायतों से मिली है, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा मैनेज किया जाता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बताया है कि मई 2024 में औसतन रोजाना 7,000 साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की गईं। ये आंकड़ा 2021 से 2023 के बीच दर्ज शिकायतों से 113.7 फीसदी ज्यादा है और 2022 से 2023 की तुलना में 60.9 फीसदी ज्यादा है। इन शिकायतों में से 85 प्रतिशत ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी थीं। गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर साइबर अपराध से लड़ने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक रूपरेखा का काम करता है। रिपोर्ट किए गए मामलों में 2019 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिसमें 2019 में 26,049 शिकायतें दर्ज की गईं, 2020 में 2,57,777 शिकायतें, 2021 में 4,52,414 शिकायतें, 2022 में 9,66,790 शिकायतें, 2023 में 15,56,218 और अकेले 2024 के पहले चार महीनों में 7,40,957 शिकायतें दर्ज की गईं।

ज्यादातर शिकार ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, गेमिंग ऐप्स, फर्जी अल्गोरिथम, अवैध लोन ऐप्स, सेक्सटॉर्शन और ओटीपी स्कैम के जाल में फंसे। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बताया कि 2023 में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की 1 लाख से ज्यादा घटनाएं सामने आईं। 2024 के शुरुआती चार महीनों में 4,599 मामलों में डिजिटल धोखाधड़ी के कारण 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी अवधि में ट्रेडिंग घोटालों के 20,043 मामले सामने आए, जिससे साइबर अपराधियों को 1,420 करोड़ रुपए का चूना लगा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक इन्वेस्टमेंट स्कैम के चलते 62,687 शिकायतों में 222 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वहीं डेटिंग ऐप्स के कारण 1,725 शिकायतों में 13.23 करोड़ रुपए का चूना लगा। जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच साइबर अपराधियों ने भारतीयों को कुल 1750 करोड़ रुपए का चूना लगाया। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बताया कि वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फिनटेक कंपनियों जैसी नियामक संस्थाओं के साथ मिलकर साइबर अपराधियों द्वारा मनी ट्रांसफर (म्यूल अकाउंट) और दूरसंचार बुनियादी ढांचे के दुरुपयोग के मुद्दों को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा वे स्काइप अकाउंट, गूगल और मेटा के विज्ञापन, एसएमएस हेडर, सिम कार्ड और बैंक खातों को ब्लॉक करने सहित साइबर अपराधों की निगरानी और उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं।

ये हैं ऑनलाइन फ्रॉड के प्रमुख तरीके

बैंक अकाउंट होल्ड के नाम पर फ्रॉड, आयुष्मान कार्ड, बजाज फिनसर्व लोन एप, बॉयोमेट्रिक, बिटक्वाइन, सिविल, कोरियर फ्रॉड, क्रिप्टो करेंसी, डाटा एंट्री, डाटा चोरी, धानी लोन, बिजली बिल, पिलपकार्ट, गुड्स इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, जिओ फाइबर, आसान लोन एप, नटराज पेंसिल फ्रॉड, क्विकर एप एड, सर्वर हैकिंग, स्नेपचैट, स्विफ्ट कैश लोन, ट्विटर, वैलेट, एपीके एप फ्रॉड, कैश एडवांस लोन एप, क्रेडिट स्टार लोन एप, डिजिटल अरेस्ट, फ्रेंचाइजी, घर में बंधक, आईसीजेएस से संबंधित, इंटरनेट बैंकिंग, ओला बुकिंग, पेपर लीक, पाइंट ऑफ सेल, यूएसडीटी आदि तरीके जालसाज अपना रहे हैं। इसके अलावा योनो अपडेट, बैंक अकाउंट, फास्टैग, मेट्रिमोनियल, वेबसाइट, लॉटरी, एनईएफटी, क्यूनेट, रिवार्ड पाइंट, आधार कार्ड, केवायसी, एलआईसी, लोस्ट सेल, क्यूआर कोड स्कैन, यूट्यूब, आईएमपीएस, एनी डेस्क, खरीदी/बिक्री, इंश्योरेंस, ब्लैकमेलिंग, न्यूड कॉल, डेबिट कार्ड, उत्पीड़न, लोन फ्रॉड, शेयर मार्केट, गूगल प्ले, टिपलाइन, ओएलएक्स, जीमेल, ट्रेडिंग, एटीएम कार्ड, इन्वेस्टमेंट, पेटीएम, मिरर एप, पार्सल, सेना का जवान, कॉल प्रताड़ना, गूगल सर्च, कार्ड फ्रॉड, ओटीपी, वाट्सएप, जॉब फ्रॉड, सोशल मीडिया, लिंक फ्रॉड, लोन एप, टास्क फ्रॉड, टेलीग्राम, बुकिंग, रिश्तेदार बनकर, फोनपे, क्रेडिट कार्ड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अनजान ट्रांजक्शन और यूपीआई फ्रॉड जैसे झांसे भी देते हैं।

डिजिटल जमाने में अपराध के नित नए रूप सामने आ रहे हैं। साइबर पुलिस के सामने ऐसे मामले आ रहे हैं कि अपराध के तरीके को जानकर पुलिसवाले भी हैरान हैं। मप्र में लगातार डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर साइबर ठग आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यही कारण है कि साइबर क्राइम पुलिस को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। साइबर क्राइम पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है कि यह साइबर अपराध का नया तरीका है। इसको लेकर सावधान रहने की जरूरत है। साइबर क्राइम पुलिस के अनुसार ऑनलाइन ठगों ने अब लोगों के साथ ठगी का नया तरीका निकाला है। यह ठग कोरियर पैकेट में मिले सिम, इंक्स, आधार कार्ड का दुरुपयोग करके, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट कन्वर्जन में नागरिकों का मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कई ट्रिक से ठग नागरिकों को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद ठगों द्वारा पुलिस स्टेशन जैसे सेटअप दिखाकर वीडियो कॉल करके डराया जाता हैं। पूछताछ के नाम पर वेबकैम, स्काइप मोबाइल से वीडियो कॉल पर आमने-सामने बैठाकर रखते हैं। इस दौरान नकली पुलिस अफसरों से भी अलग-अलग नंबरों पर बात कराई जाती है। फिर जमानत के नाम पर ओटीपी मांग लिया जाता है। नागरिक डर जाते हैं और अपने बैंक खातों संबंधी जानकारी ठग को दे देते हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने सलाह दी है कि नागरिक सतर्क रहें। जांच एजेंसियों के नाम से आ रहे फोन पर बात नहीं करें। जमानत के नाम पर डरकर अपना ओटीपी न दें। किसी भी खाते में रुपए जमा न कराएं। साथ ही जालसाजों के कहने पर कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करें। पुलिस के अनुसार जब व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट के झांसे में आ जाता है तो यह ठग व्हाट्सएप नंबर पर रोजाना हाजिरी भी लगवाते हैं। इसमें व्यक्ति को रोजाना प्रजेंट सर लिखकर ग्रुप पर भेजना होता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नागरिकों के पास इस प्रकार का कोई फोन आए तो तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क करना चाहिए। नागरिक 1930 नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं।

● **ब्रजेश साहू**

लागू होगा नया जेल कानून!

गृह मंत्रालय ने 130 वर्ष पुराने जेल अधिनियम में बदलाव कर व्यापक मॉडल जेल अधिनियम-2023 तैयार कर लिया है। नए जेल अधिनियम में पुराने जेल अधिनियमों के प्रासंगिक प्रविधानों को भी शामिल किया गया है। यह राज्यों और उनके कानूनी क्षेत्र में मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करने में सहायक होगा। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश पर मप्र के जेल विभाग ने मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक-2024 बनाया है। इसके नियम तैयार कर लिए गए हैं। आचार संहिता हटने के बाद इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 11 केंद्रीय जेल हैं। वहीं 42 जिला जेल, 72 उप जेल, 7 ओपन जेल हैं। इन जेलों की बंदी क्षमता 30 हजार है। जबकि इनमें 48 हजार बंदी रखे गए हैं।

सूत्रों का का कहना है कि प्रमुख सचिव जेल मनीष रस्तोगी, अपर सचिव ललित दाहिमा, डीजी जेल जीपी सिंह और जेल मुख्यालय के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मॉडल जेल अधिनियम-2023 के ड्राफ्ट पर चर्चा कर मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक-2024 के नियमों को अंतिम रूप देकर प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। जल्द ही यह प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा जाएगा। वहां से यह प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सीनियर सेक्रेट्रीज की कमेटी में जाएगा। फिर इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 130 साल बाद ब्रिटिश युग के 1894 के जेल अधिनियम में व्यापक स्तर पर संशोधन कर मॉडल जेल अधिनियम-2023 तैयार किया है। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को इसका ड्राफ्ट भेजा है। इस ड्राफ्ट में राज्य सरकारों से स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जरूरी संशोधन करने को कहा गया है। इसी तारतम्य में मप्र का जेल विभाग मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक-2024 ला रहा है। इसके नियम तैयार कर लिए गए हैं। जेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विधेयक में सबसे ज्यादा जोर जेलों में क्षमता से अधिक बंदी नहीं रखे जाने पर दिया गया है। जेलों में भीड़भाड़ के कारण रहने की स्थिति खराब होती है। इससे कई संचारी रोगों के संचरण का जोखिम बना रहता है। इससे निपटने के लिए मप्र में नए जेलों का निर्माण किया जा रहा है। नए जेल सागर, भिंड, दमोह, छतरपुर, रतलाम, मंदसौर व बैतूल में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जेलों में नए बैरकों का निर्माण किया जा रहा है।

जेल अधिनियम-1894 आजादी से पहले के काल का अधिनियम था। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों को हिरासत में रखना और जेल में अनुशासन व व्यवस्था बनाना था। मौजूदा अधिनियम में कैदियों के सुधार और पुनर्वास का कोई प्रविधान नहीं है। आज जेलों को प्रतिशोधात्मक निवारक के रूप में नहीं देखा जाता है अपितु इन्हें शोधनालय एवं सुधारात्मक संस्थानों के रूप में देखा जाता है, जहां कैदी बदलकर एवं पुनर्वासित होकर कानून का पालन करने वाले नागरिक की भांति समाज में लौटे।

गृह मंत्रालय ने महसूस किया कि मौजूदा कारागार अधिनियम में कई खामियां हैं। मौजूदा अधिनियम में आज की आवश्यकताओं और जेल प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने का संशोधन करने की आवश्यकता थी। आधुनिक दिनों की आवश्यकता और सुधारात्मक विचारधारा के साथ गृह मंत्रालय ने जेल अधिनियम-1984 को संशोधित करने का काम पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को सौंपा। मालूम हो कि ब्यूरो ने राज्य जेल अधिकारियों और सुधारात्मक विशेषज्ञों से बातचीत के बाद जेल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग, अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए पैरोल, फरलो, कैदियों को छूट देने के लिए प्रविधान करना, महिलाओं व ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए विशेष प्रविधान करने आदि को शामिल कर ड्राफ्ट तैयार किया। गृह मंत्रालय ने जेल अधिनियम-1894, कैदी अधिनियम-1900 और कैदियों के स्थानांतरण अधिनियम-1950 की भी समीक्षा की है। इन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रविधानों को मॉडल जेल अधिनियम-2023 में शामिल किया गया है।

वहीं अब केंद्र सरकार निर्धन कैदियों का अर्थदंड भरेगी। अर्थदंड न भरने के कारण जेल में बंद निर्धन कैदियों को रिहा करने के लिए केंद्र सरकार बजट उपलब्ध कराएगी। गरीब विचाराधीन कैदियों की जमानत राशि और दोष सिद्ध कैदियों के जुर्माना राशि आदि का भुगतान न होने का डाटा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे कैदियों की संख्या मांगी है कि जो आर्थिक तंगी के कारण उन पर लगाए गए अर्थदंड न भर पाने अथवा जमानत राशि वहन न कर पाने के कारण जेल में बंद हैं। केंद्र सरकार ने अर्थदंड की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। ऐसे निर्धन कैदियों की पात्रता का निर्धारण राज्य स्तरीय समिति करेगी। निर्धन कैदियों के अर्थदंड भरे जाने के लिए मप्र सरकार ने प्रमुख सचिव जेल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय राज्य स्तरीय निगरानी समिति भी गठित की हुई है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा पर जोर

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए एक्ट में महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा पर अधिक जोर दिया गया है, इससे जेल मैनेजमेंट में पारदर्शिता आएगी। साथ ही इसमें कैदियों के बर्ताव में सुधार और रिहैब का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि मौजूदा कारागार अधिनियम 1894 आजादी से पहले का है। यह मुख्य रूप से अपराधियों को हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन तथा व्यवस्था लागू करने पर केंद्रित है। इसमें कैदियों के सुधार और पुनर्वास का प्रावधान नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा कारागार अधिनियम में कई खामियां हैं। लिहाजा आधुनिक समय की जरूरतों तथा जेल मैनेजमेंट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके बाद मंत्रालय ने कारागार अधिनियम 1894 में संशोधन की सिफारिशों की जिम्मेदारी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को सौंपी। इसके बाद ब्यूरो ने राज्य कारागार प्रशासन और कुछ एक्सपर्ट से विचार-विमर्श के बाद इसका प्रारूप तैयार किया।

भारत में रोज 1263 हादसे, 461 मौतें

महाराष्ट्र में पुणे के कल्याणीनगर में हुई दुर्घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। गत दिनों लगभग ढाई करोड़ रुपए की महंगी कार से हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को 7500 रुपए के बॉन्ड और सड़क सुरक्षा पर एक निबंध लिखने की सजा देते हुए जमानत दे दी थी। जब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो आरोपी और उसके पिता पर कार्रवाई की गई। भारत में हर रोज 1263 सड़क हादसे हो रहे हैं। अगर 24 घंटे की बात करें, तो इस छोटी सी अवधि में 461 लोगों की मौत हो जाती है। देश में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि अब सड़क हादसों में कमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी तरफ, अमेरिका में 365 दिन में 19 लाख सड़क हादसे हो जाते हैं, लेकिन उनमें मारे जाने वाले लोगों की संख्या 36,560 रहती है।

महाराष्ट्र की घटना में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले पर जब लोगों का गुस्सा फूटा, तो सरकार भी सक्रिय हो उठी। नतीजा, दोबारा से मामले की सुनवाई हुई। आरोपी की आयु 17 साल 8 महीने बताई गई है। बोर्ड ने आरोपी को 5 जून तक किशोर सुधार गृह में भेज दिया है। आरोपी के पिता भी पुलिस हिरासत में है। वजह, उन्होंने जानते हुए भी कि उनका बेटा नाबालिग है, इसके बावजूद उसे वाहन दिया। देश में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद भी सड़क हादसों में गिरावट नहीं आ रही है। 5 साल पहले लागू हुए नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई थी। मकसद था, सड़क हादसों में कमी लाना। देश में प्रतिवर्ष चार लाख से ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, जर्मनी और जापान सहित 19 देश शामिल हैं। विकसित देशों में भारत के मुकाबले कानून कठोर हैं। साथ ही इन देशों में वाहन से लेकर रोड इंजीनियरिंग तक, इन सभी बातों पर गहराई से काम होता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत में सड़क दुर्घटनाएं-2022 शीर्षक से जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में 4,61,312 सड़क हादसे हुए थे। इन हादसों में 1,68,491 लोगों की जान गई थी, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए थे। पिछले वर्ष की तुलना में सड़क हादसों में 11.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। इन हादसों में होने वाली मौतों में 9.4 फीसदी और घायलों की संख्या में 15.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। एक्सप्रेस-वे सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1,51,997 (32.9 फीसदी) सड़क हादसे हुए। राज्य मार्गों पर 1,06,682 (23.1 फीसदी) हादसे और अन्य मार्गों पर 2,02,633 (43.9 फीसदी) सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलीं। साल 2022 के दौरान सड़क हादसों के 66.5 फीसदी पीड़ितों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच थी। अधिकांश पीड़ित युवा थे। लगभग 68 फीसदी मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुईं थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में 32 फीसदी मौतें हुईं।

2022 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं, तमिलनाडु में दर्ज की गई हैं। इस प्रदेश में 64,105 सड़क हादसे हुए थे। इसके बाद मप्र का नंबर आता है। यहां 54,432 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। अगर सड़क-उपयोगकर्ता श्रेणी की बात करें, तो 2022 में हुई मौतों में दोपहिया सवार सबसे ज्यादा रहे। यह प्रतिशत 44.5 फीसदी था। इसके बाद पैदल यात्रियों का नंबर आता है। यह प्रतिशत 19.5 रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या उप्र में रही है। इस राज्य में 22,595 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो गई। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 17,884 रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, भारत में 2021 के दौरान हुए 4,12,432 सड़क हादसों में 1,53,972 लोग मारे गए, जबकि 3,84,448 लोग घायल हुए थे। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, कद्दावर नेता राजेश पायलट, केंद्रीय मंत्री रहे गोपीनाथ मुंडे और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा से लेकर टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री तक अनेक लोग सड़क हादसों का शिकार हुए हैं। देश में सितंबर 2019 से लागू हुए नए मोटर वाहन अधिनियम में चालान राशि में कई गुना इजाफा किया गया। इसके बाद उम्मीद बंधी थी कि अब वाहन चालक संभलकर चलेंगे और सड़क हादसों में कमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

● **लोकेश शर्मा**

भारत में स्पीड बढ़ी तो हादसों की भयावहता भी बढ़ी

हमारे देश में वाहनों की रफ्तार बढ़ रही है। इसके साथ ही हादसों की भयावहता भी बढ़ रही है। देश में इमरजेंसी केयर जैसी सुविधाओं में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले सड़क हादसों में चोट गंभीर नहीं होती थी, लेकिन अस्पताल तक पहुंचने में देरी की वजह से मौत हो जाती थी। अब चोट ज्यादा गंभीर हो गई है। ऐसे में जान बचाना एक बड़ी चुनौती है। अस्पतालों में जान बचाने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। सरकार को ट्रॉमा केयर पर फोकस करना होगा। सड़क हादसे तो हर देश में होते हैं, लेकिन मौतें उतनी नहीं होतीं। अमेरिका में भारत से कई गुना ज्यादा हादसे होते हैं, लेकिन मौत एक चौथाई भी नहीं होती। भारत में 2020 के दौरान 4,32,957 सड़क हादसे हुए थे। इनमें 1,51,417 लोग मारे गए थे। चीन में 2,44,937 हादसों में 63,194 लोग मारे गए। रूसी फेडरेशन में 1,68,099 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 18,214 लोग मारे गए। दक्षिण अफ्रीका में 1,46,773 सड़क हादसे हुए। इनमें 14,500 लोगों की मौत हो गई। ईरान में हुए 3,37,891 सड़क हादसों में 16,540 लोग मारे गए। तुर्की में 1,86,532 सड़क हादसों में 6,675 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में 19,27,654 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 36,560 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 3,08,721 सड़क हादसे हुए, इनमें 3,275 लोग मारे गए। जापान में 4,30,601 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 4,166 लोगों की जान चली गई।

कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार जब कोतवाल ही चोर?

फर्जीवाड़े में माफिया, नेताओं और अफसरों का गठजोड़ सामने आया

छात्रों का भविष्य खराब करने वालों पर सीएम डॉ. मोहन का चाबुक

मप्र में हुआ नर्सिंग कॉलेज घोटाला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। कैसे सालों तक फर्जी नर्सिंग कॉलेज प्रदेश में संचालित होते रहे और छात्रों का भविष्य दांव पर लगाते रहे, इसकी परतें अब खुलनी शुरू हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि घोटाला उजागर हुआ और सीबीआई को जांच सौंपी गई, लेकिन जांच करने वाले अधिकारी ही बिक गए। यह नर्सिंग घोटाला प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाला जैसा ही है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फर्जीवाड़े को गंभीरता से लिया है।

● राजेंद्र आगाल

मप्र में जबसे डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, तबसे शासन और प्रशासन का पूरा जोर सुशासन पर है। सरकार ने सुशासन के लिए अभी तक जो कदम उठाया है, उससे प्रदेश के साथ ही देश की जांच एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की सतर्कता से मप्र में चल रहे नर्सिंग कॉलेज घोटाले का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिसमें यह बात सामने आई है कि सीबीआई के जिन अफसरों को इस फर्जीवाड़े की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वे खुद फर्जीवाड़े में जुट गए। जिन कॉलेजों पर फर्जीवाड़े का संदेह था, उनमें से कईयों को जांच अधिकारियों ने क्लीन चिट दे दी। हालांकि खुद सीबीआई के अफसरों ने अपने अधिकारियों की काली करतूत का भंडाफोड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन इस फर्जीवाड़े में जिस तरह की धांधली सामने आई है, उससे यही कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, जब कोतवाल ही चोर निकलेगा?

मप्र में व्यापमं फर्जीवाड़े के बाद सरकार की साख पर लगे दाग को धोने के लिए कई कदम उठाए गए। लेकिन कोरोनाकाल में नर्सिंग कॉलेजों के खोले जाने और परीक्षाओं को लेकर संगठित तरीके से ऐसा फर्जीवाड़ा किया गया कि लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में पड़ गया है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगाने वाले इस घोटाले में माफिया, नेताओं और अफसरों का गठजोड़ सामने आया है। जब यह घोटाला सामने आया था, तब तत्कालीन सरकार तक शिकायत पहुंची, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे रहे और घोटाला होता गया। अब मामला उजागर होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को कठोर एक्शन लेने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुरानी फाइलें खंगाली जा रही हैं। वहीं प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को बंद किया जा रहा है।

2021 में सामने आया घोटाला

गौरतलब है कि प्रदेश में नर्सिंग घोटाला वर्ष 2021 में सामने आया। शिकायत के आधार पर इसकी जांच हुई। आरोप लगे कि नियमों को ताक में रखकर कॉलेजों को मान्यता दी गई। दो-तीन कमरों में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। न तो कॉलेज में लैब है और न ही 100 बिस्तर का अस्पताल है। कई कॉलेजों में तो फैकल्टी का ही पता नहीं है। सबकुछ कागजी है। ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद 364 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई जांच के आदेश होने के बाद लगा कि शायद बड़े खुलासे होंगे लेकिन जांच अफसर ही भ्रष्ट निकले, वे भी बिक गए। सीबीआई अफसरों ने ही अपने अफसरों को घूस लेते पकड़ा। ये अनसूटेबल कॉलेजों को सूटेबल रिपोर्ट दे रहे थे। ये अफसर नर्सिंग कॉलेजों को क्लीनचिट देने के लिए रिश्वत ले रहे थे। इसमें सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज 10 लाख की रिश्वत लेते धरा गया। इसे बर्खास्त कर दिया गया है। अन्य अफसरों पर भी गाज गिरी है। कॉलेज संचालक, प्राचार्य, दलाल भी पकड़े गए।

नर्सिंग घोटाले में शिक्षा माफिया, नेताओं और अफसरों का गठजोड़ ऐसा रहा कि जिनकी मान्यता खतरे में आई, उन्होंने मोटी रकम देकर क्लीनचिट ले ली। अब एक-एक नर्सिंग कॉलेज की जांच दोबारा होगी। पूर्व में हुई जांच में 169 कॉलेजों को सूटेबल, 73 नर्सिंग कॉलेजों को डिफिसेंट और 66 को अनसूटेबल बताया गया था। सूटेबल कॉलेजों की सूची उजागर होते ही इसकी पड़ताल की गई। एनएसयूआई नेता एवं विसिल ब्लोअर रवि परमार ने सीबीआई को कॉलेजों की ग्राउंड रियलिटी भेजी। प्रमाण सहित भेजी गई जानकारी पर सीबीआई हरकत में आई और कार्रवाई शुरू की गई। जांच अधिकारी घेरे में आए। कहा जा रहा है कि नर्सिंग घोटाला भी

घोटाले की जांच में गिरोह बनाकर खाई रिश्वत

मप्र के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच में घूसखोरी के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अभी तक अपने ही दो इंस्पेक्टर, कॉलेज संचालक समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। घोटाले की सीबीआई मुख्यालय में शिकायत करने वाले विसिल ब्लोअर एवं एनएसयूआई के नेता रवि परमार का दावा है कि जांच की जांच हुई तो सीबीआई के अन्य अधिकारी और कॉलेज संचालक फंसेंगे। जांच के नाम पर सही रिपोर्ट बनाने के लिए सभी ने घूसखोरी के लिए सिंडिकेट बना लिया था। आरोपियों से पूछताछ में अन्य छिपे हुए बड़े नाम सामने आ सकते हैं। परमार का दावा है कि जांच में बड़े नाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत पर ही सीबीआई मुख्यालय ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वे दिल्ली सीबीआई को जल्द ही अन्य भ्रष्टाचारी निरीक्षकों और नर्सिंग फर्जीवाड़े में शामिल नर्सिंग कालेज संचालकों और दलालों की जानकारी सौंपेंगे। ग्वालियर उच्च न्यायालय ने 364 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इनमें से 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रिपोर्ट सौंपी। जांच रिपोर्ट में 169 नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल (उपयुक्त), 73 नर्सिंग कॉलेजों को डिफिसेंट और 66 नर्सिंग कॉलेज को अनसूटेबल (अनुपयुक्त) बताया गया। सीबीआई ने जांच में कई ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को भी क्लीन चिट दे दी थी जो मान्यताओं पर खरे नहीं उतरे थे।

प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाले जैसा है और व्यापमं पार्ट-2 भी इसे कहा जा रहा है। बता दें कि व्यापमं घोटाला उजागर होने से मप्र की खूब किरकिरी हुई थी। वर्ष 2013 में एसटीएफ ने व्यापमं घोटाले की जांच शुरू की थी। वर्ष 2014 में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को निगरानी सौंपी गई थी। वर्ष 2015 में 212 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जिसके बाद 1242 लोगों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पेश की गई। अगस्त 2023 में तीन को 7 साल की जेल हुई और सुनवाई अभी भी जारी है। व्यापमं घोटाले में तत्कालीन मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सहित अन्य रसूखदारों को जेल की हवा खानी पड़ी थी और इसकी आंच राजभवन तक पहुंची थी।

जांच में भी घोटाला

मप्र में नर्सिंग के करीब एक लाख छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बहुचर्चित व्यापमं घोटाले के बाद अब नर्सिंग कॉलेज घोटाला भी सरकार के लिए किरकिरी का विषय बन चुका है। नियम-कायदों को दरकिनार करते हुए नर्सिंग कॉलेज संचालित होते रहे। न तो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत महसूस की गई और न ही पढ़ाने के लिए फैकल्टी की। कई कॉलेज तो बिना फेकल्टी के भी सर्टिफिकेट बांटते रहे। सीबीआई ने जांच की तो उसके अफसर भी भ्रष्टाचार में शामिल हो गए और अब उनकी ही जांच उनकी एजेंसी कर रही है। सीबीआई की नई टीम को जांच दी जा सकती है। इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भी एंट्री हो सकती है। वह पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीबीआई के अधिकारियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई की टीम दिल्ली में पूछताछ कर रही है। इनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। प्रदेश सरकार नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने संबंधी आयोग गठन करने पर काम कर रही है। साथ ही छात्रों के लिए राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा लेने पर भी विचार किया जा रहा है। आइए, जानते हैं कि व्यापमं के बाद प्रदेश के अब तक के सबसे चर्चित घोटाले में कब क्या हुआ?

470 नर्सिंग कॉलेजों की जांच करेगी सीबीआई

भोपाल सहित पूरे प्रदेश में नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स संचालित करने वाले 470 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई करेगी। इसके लिए मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने सीबीआई को डिप्लोमा कोर्स वाले 470 कॉलेजों की लिस्ट सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने इन कॉलेजों की जांच करने 7 अलग-अलग टीमें बनाई हैं। यह टीमें जल्द ही डिप्लोमा कोर्सेस वाले नर्सिंग कॉलेजों की जांच शुरू करेगी। दूसरी ओर, नर्सिंग कॉलेज रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद आरोपी सीबीआई इंस्पेक्टर सुशील कुमार मजोका, अनिल भास्करन, तनवीर खान, राधारमण शर्मा, सचिन जैन, वेद प्रकाश शर्मा, प्रीति तिलकवार, सुमा अनिल भास्करन, जल्पना अधिकारी को जेल भेज दिया गया। वहीं, 4 आरोपी ओम गोस्वामी, रवि भदौरिया और जुगल किशोर शर्मा अभी भी रिमांड पर है। बता दें, सीबीआई ने इंस्पेक्टर सुशील मजोका को बर्खास्त किया था।

प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता संबंधी शिकायत पर यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। इसके बाद राज्य नर्सिंग काउंसिल ने डेढ़ दर्जन से ज्यादा कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी। वहीं, हाईकोर्ट ने सीबीआई को अक्टूबर 2022 में मामले की जांच सौंप दी। कॉलेजों की प्राथमिक जांच में अनियमितताएं सामने आईं। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 364 कॉलेजों की जांच के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 7 जांच दल बनाए। इनमें सीबीआई अधिकारियों के साथ-साथ नर्सिंग कॉलेजों के नामित अधिकारी और पटवारियों को भी रखा गया। सीबीआई ने 169 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट सौंपी। अधिकतर कॉलेजों को योग्यता सूची में शामिल किया। 73 कॉलेजों में कमियां और 66 को अयोग्य बताया गया। लिस्ट के सामने आने के बाद उन कॉलेजों को सूटेबल लिस्ट में शामिल कर लिया, जिनमें कमियां बताई गई थीं। सूटेबल लिस्ट में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर व फैकल्टी वाले कॉलेजों के नाम जब शामिल हो गए तब अधिकारियों की मिलीभगत की शिकायत सीबीआई को मिली। चार अधिकारियों समेत 23 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए। सीबीआई के दो इंस्पेक्टर मप्र पुलिस के हैं। वहीं, सीबीआई के एक अधिकारी राहुल राज को बर्खास्त कर दिया गया है।

सीबीआई के अधिकारियों को पकड़ने के बाद भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। सीबीआई के अधिकारियों ने दलालों के साथ मिलकर पैसों के बदले कॉलेजों को सूटेबल रिपोर्ट दी। सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज, सुशील कुमार मोजोका और ऋषिकांत असाठे को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। डिप्टी एसपी आशीष प्रसाद को आरोपी बनाया है। सीबीआई के अधिकारियों के लिए दलाल कॉलेज संचालकों से संपर्क करते थे। फिर उन्हें सूटेबल लिस्ट में शामिल कराने के लिए पैसा तय होता था। सीबीआई की एफआईआर में कई दलालों के नाम लिखे हैं। सीबीआई अधिकारी को रिश्वत के रूप में 2 से 10 लाख रुपए देना तय

66 कॉलेजों की मान्यता निरस्त

- **अलीराजपुर**- साई स्कूल ऑफ नर्सिंग, अलीराजपुर
- **अनुपपुर**- शारदा स्कल ऑफ नर्सिंग, अनुपपुर
- **बड़वानी**- बड़वानी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, बड़वानी
- **बैतूल**- विजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मारुति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, श्री अग्रसेन महाराज स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मां मालती देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज, श्री गोवर्धन कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, वेंदास कॉलेज ऑफ नर्सिंग
- **भिंड**- आयुष्मान स्कूल ऑफ नर्सिंग, मां कृष्णा नर्सिंग कॉलेज
- **भोपाल**- सविता कॉलेज ऑफ नर्सिंग, विनस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड नर्सिंग, राम राजा सरकार कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रोशन हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सांई आसरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, द होली फेथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग
- **बुरहानपुर**- ऑल इज वेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग
- **छतरपुर**- आधार नर्सिंग कॉलेज, जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, खजुराहो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, एसआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग
- **छिंदवाड़ा**- ओरियंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रितू कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस
- **देवास**- ओरियंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रितू कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस
- **धार**- श्री वेंकटेंस नर्सिंग, रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नवरतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, प्रयागराज कॉलेज ऑफ नर्सिंग
- **ग्वालियर**- जय मा भगवती नर्सिंग कॉलेज
- **इंदौर**- देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल, हरीतुंजय स्कूल ऑफ नर्सिंग, वर्मा यूनियन नर्सिंग कॉलेज, जगदगुरु दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राय एकेडमी नर्सिंग कॉलेज
- **जबलपुर**- कोठारी नर्सिंग कॉलेज, प्रीति इंस्टीट्यूटी ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस
- **झाबुआ**- मां पदमावटी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, अक्षर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, झाबुआ
- **खंडवा**- प्रतिभा कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज
- **खरगौन**- श्री रीवा गुर्जर मेडिकल साइंस ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर
- **मंडला**- केयर स्कूल ऑफ नर्सिंग, शक्ति विद्या मंदिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग
- **मुरैना**- बोस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग
- **नर्मदापुरम**- शांति निकेतन नर्सिंग स्कूल, नर्मदा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, दयाल एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस कॉलेज
- **पन्ना**- छत्रसाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग
- **रीवा**- गर्वमेंट नर्सिंग कॉलेज, स्वातिक नर्सिंग कॉलेज
- **सागर**- डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग
- **सीहोर**- हिंदूजा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मां पीताम्बरा नर्सिंग कॉलेज, निशा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च सेंटर, सुशीला नर्सिंग कॉलेज
- **सिवनी**- केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बरापठार, सिवनी, रिनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग
- **शहडोल**- पंचशील इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, शारदा देवी नर्सिंग कॉलेज
- **टीकमगढ़**- दाउ सरदार सिंह नर्सिंग इंस्टीट्यूट
- **उज्जैन**- जेके कॉलेज ऑफ नर्सिंग
- **उमरिया**- टीडी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर उमरिया
- **विदिशा**- बीएम स्कूल ऑफ नर्सिंग
- **श्योपुर**- जेएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बागवाज, श्योपुर

किया था। नर्सिंग स्टाफ को 25 से 50 हजार रुपए और पटवारी को 5 से 20 हजार रुपए मिलते थे। सीबीआई का एक अधिकारी रिश्वत की राशि जयपुर में अपने दोस्त को भिजवाता था। रिश्वत की राशि लेने से अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग लोग शामिल थे। इसके बाद नर्सिंग कॉलेज के नियमों में फेरबदल किए गए। क्षेत्रफल 23 हजार वर्गफुट चाहिए था, लेकिन नए नियमों में इसे घटाकर 8 हजार वर्गफुट कर दिया। फैकल्टी में 10 छात्रों पर एक शिक्षक के अनुपात को बदलकर 20 पर एक कर दिया गया। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों को भी सूटेबल लिस्ट में डाल दिया गया। कई जगह कॉलेज में शिक्षक नहीं होने के बावजूद सर्टिफिकेट बांटे जाते रहे। प्रदेश में अभी हाल ही में 2020-21 सत्र के नर्सिंग की छात्रों की परीक्षा संपन्न हुई है। 2021-22, 2022-23 की परीक्षा का समय अभी निर्धारित ही नहीं है। 2023-24 के लिए कॉलेजों की मान्यता नहीं हुई है। वहीं, एनएसयूआई के प्रदेश समन्वयक रवि परमार का कहना है कि नर्सिंग घोटाले की वजह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिन छात्र-छात्राओं की अभी परीक्षा रुकी हुई है, उस पर सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। इससे एक लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हैं।

हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

इस जांच में 169 कॉलेजों को सूटेबल, 73 नर्सिंग कॉलेजों को डिफिसेंट और 66 को अनसूटेबल बताया गया। सूटेबल कॉलेजों की लिस्ट सार्वजनिक होते ही इसकी पड़ताल की गई। विसिल ब्लोअर और एनएसयूआई के अध्यक्ष रवि परमार ने शिकायत की, कि जिन कॉलेजों को सीबीआई ने सूटेबल घोषित किया है, वो नियमों के खिलाफ हैं। फिर मामले में जांच हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मामले की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी ही भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए। घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के अफसर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। नर्सिंग घोटाले के विसिल ब्लोअर रवि परमार की शिकायत पर सीबीआई दिल्ली की टीम ने अधिकारी को पकड़ा था।

रिश्वतखोर सीबीआई इंस्पेक्टर ने की थी तगड़ी वसूली

मप्र के नर्सिंग कॉलेज मामले की जांच कर रहे जिस सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को सीबीआई की ही विजिलेंस टीम ने रिश्वत के 7 लाख रुपए और सोने के दो बिस्किट के साथ पकड़ा था, उसने जांच के घेरे में आए इंदौर और आसपास के नर्सिंग कॉलेज संचालकों से तगड़ी वसूली की थी। एक-एक कॉलेज संचालक को धमकाकर रिश्वतखोर इंस्पेक्टर ने 10-10 लाख रुपए वसूले थे। कुछ से तो इससे भी ज्यादा राशि वसूली गई थी। इस रिश्वत के एवज में अपात्र कॉलेज को पात्र बताकर हाईकोर्ट में गलत रिपोर्ट पेश की गई। रिश्वतखोरी के इस काम में मंदसौर के भाजपा नेता मुकेश गिरि गोस्वामी का भाई ओम गिरि गोस्वामी मध्यस्थ बना था। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर मप्र के 364 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी। प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेज संचालक भी अभी सीबीआई की हिरासत में हैं। इनसे पूछताछ में महत्वपूर्ण सूत्र मिले हैं। इस मामले में जल्दी ही कुछ और गिरफ्तारी भी होंगी। रिश्वतखोर राहुल राज के पास इंदौर-उज्जैन क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों की जांच का जिम्मा था। उसने सबसे पहले उन नर्सिंग कॉलेजों को निशाने पर लिया, जो किसी भी आर्हता को पूरा नहीं कर रहे थे और इन्हें सीबीआई जांच में भी कॉलेज संचालन के लिए अनसूटेबल पाया गया था। इनके पक्ष में रिपोर्ट देने के नाम पर किसी से 10 लाख तो किसी से 25 लाख रुपए तक लिए गए। राहुल और कॉलेज संचालकों के बीच लेन-देन में ओम गिरि गोस्वामी मध्यस्थ बना था। वही कॉलेज संचालकों को राहुल से मिलवाता था। सूत्रों के मुताबिक राहुल एक महिला के साथ इंदौर आता था। वह जहां ठहरता था, वहीं कॉलेज संचालकों को तलब करता और उनसे बहुत बदतमीजी से बात करते हुए डराता-धमकाता था। उसने पहले जांच के नाम पर कॉलेज संचालकों पर दबाव बनाया, उनसे दस्तावेज मांगे और कुछ जगह मुआयना करने भी पहुंचा। बाद में उसने इनसे पैसा ऐंठना शुरू किया और गोस्वामी की मध्यस्थता में एक-एक कॉलेज से 10-10 लाख रुपए वसूले गए। इसके एवज में उन्हें क्लीन चिट देने की बात भी कही गई थी।

आज भी फर्स्ट ईयर में

मामले में सीबीआई की ओर से सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराई गई कि 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ सीबीआई के अफसर भी शामिल हैं। मामले में विभाग की ओर से चुप्पी साध ली गई है। वहीं सरकार का कहना है कि सीबीआई अपनी जांच कर रही है। किसने घोटाला किया और कब किया ये सब जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है, जिसका मतलब है कि अपराधी जो भी हो, सलाखों के पीछे जरूर जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि ये तो व्यापमं से भी बड़ा घोटाला है। जांच सबसे पहले इस बात की होनी चाहिए कि आखिर इन फर्जी कॉलेजों को अनुमति किसने दी। अब उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, जिन्होंने तीन साल से परीक्षा ही नहीं दी है। इस घोटाले में सवाल उन एक लाख स्टूडेंट्स का है, जो नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तीन वर्षों से परीक्षा नहीं होने के कारण आज भी वो फर्स्ट ईयर में ही हैं। तीन वर्ष पहले भी फर्स्ट ईयर में थे और आज भी फर्स्ट ईयर में ही हैं। किसी के पिता किसान हैं तो किसी के मजदूर। घर वाले समझ रहे हैं कि अब चौथे साल में डिग्री पूरी हो जाएगी। कई स्टूडेंट्स तो पार्ट टाइम जॉब करने लगे हैं। कई घरवालों से ही पैसे मंगवा रहे हैं। इन्हें तो तीन वर्ष से छात्रवृति भी नहीं मिली है। सबसे बड़ा सवाल क्या चार साल की डिग्री सात साल में होगी ? सरकार के पास इसका जवाब नहीं है।

भले ही विभाग मामले को दबाने में लगा हो, लेकिन सीबीआई के अधिकारियों पर सीबीआई के ही अधिकारियों की कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि दाल में बहुत कुछ काला है। अगर सही तरह से जांच हो गई तो कई परतें खुल सकती हैं और कई रसूखदार बेपर्दा हो सकते हैं। हैरानी की बात ये है कि हाईकोर्ट के आदेश और सीबीआई की इन्क्वायरी के बावजूद ये फर्जीवाड़ा धड़ल्ले से चल रहा है। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। आदेश के अनुसार मप्र के 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों

को बंद किया जाएगा। यह कार्रवाई इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर सीबीआई जांच में अनफिट निकले नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ की गई है। राज्य सरकार ने यह कार्रवाई मप्र हाईकोर्ट के निर्देश पर की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने संबंधित नर्सिंग कॉलेजों को सील करने की कार्रवाई के निर्देश संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को दिए हैं। इसके लिए आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने कलेक्टरों को अनफिट नर्सिंग कॉलेजों की सूची भेज दी है। ताकि संबंधित नर्सिंग कॉलेजों को सील करने की कार्रवाई की जा सके। बता दें कि इंदौर सहित कई जिलों में गत दिनों कार्रवाई हो चुकी है। कमिश्नर, मेडिकल एजुकेशन ने कलेक्टर्स को अनसूटेबल नर्सिंग कॉलेजों की सूची दी है। हाईकोर्ट को सौंपी गई सीबीआई की रिपोर्ट में 66 कॉलेज अनसूटेबल पाए गए हैं। ये कॉलेज सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहे थे।

परीक्षा दे सकेंगे विद्यार्थी

हालांकि, सरकार ने विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए कार्रवाई में राहत दी है। इस आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के पुराने विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे। विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। जानकारी के अनुसार कमिश्नर, मेडिकल एजुकेशन ने कलेक्टर्स को सूची दी है और कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करें। नर्सिंग काउंसिल ने सभी 66 अनसूटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की सभी सत्रों और पाठ्यक्रमों की मान्यता निरस्त कर दी है। मप्र नर्सिंग घोटाला मामले में 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमें से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में सीबीआई के अधिकारी भी हैं। जिसमें से एक को बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इस आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के पुराने विद्यार्थी प्रभावित नहीं हो सकेंगे। उनके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

ऐसे कॉलेजों को बताया उपयुक्त

सीबीआई ने मप्र में जिन नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी, अब वही सवालों के घेरे में हैं। सीबीआई ने जिन कॉलेजों को उपयुक्त बताते हुए हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी, उनमें से कहीं मैरिज गार्डन खुला है तो कहीं स्टाफ ही नहीं है। ग्वालियर में एक परिसर में दो कॉलेज और दो अस्पताल हैं। सिटी अस्पताल और श्रीराम अस्पताल बंद मिले। वहीं, कॉलेज में स्टाफ के नाम पर केवल दो कर्मचारी मिले। उन्होंने बताया कि कुछ माह पूर्व नर्सिंग कॉलेज बंद करने के लिए मेडिकल विवि और मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को पत्र लिखा है। वर्तमान में एक कॉलेज में 10 से 12 तो दूसरे में बीएससी नर्सिंग के 8 छात्र हैं।

नर्सिंग घोटाले की क्रॉनोलॉजी

12 जनवरी 2022: हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि 2020-21 सेशन में खासतौर पर आदिवासी इलाकों में ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई है, जो शर्तें पूरी नहीं करते। ऐसे 55 कॉलेजों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की गई। इस सेशन में 670 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी थी।

19 अप्रैल 2022: हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल ऑफ मप्र को आदेश दिया कि कॉलेजों का पूरा रिकॉर्ड पेश करें।

12 मई 2022: हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन से कहा कि वे इन कॉलेजों का रिकॉर्ड चेक करके बताएं कि कितने कॉलेजों को गलत मान्यता दी गई है।

4 मई 2023: रिपोर्ट पढ़कर हाईकोर्ट जस्टिस इतने नाराज हुए कि उन्होंने नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार सुनीता शीजु को हटाने के आदेश दिए। ये भी कहा कि अगले आदेश तक काउंसिल का काम प्रशासक देखेंगे।

जुलाई 2023: हाईकोर्ट के आदेश पर नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े सभी 50 केस को हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया।

सितंबर 2023: हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिए कि सभी कॉलेजों की जांच करके तीन कैटेगरी में रिपोर्ट दें। इसमें सूटेबल, डिफिशिएंट और अनसूटेबल कॉलेजों की अलग-अलग जानकारी मांगी।

22 फरवरी 2024: सीबीआई ने 169 सूटेबल कॉलेज, 74 डिफिशिएंट और 65 अनसूटेबल कॉलेजों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की।

फरवरी 2024: हाईकोर्ट ने पहले सूटेबल कॉलेजों में परीक्षा के आदेश दिए। इसके कुछ दिन बाद सभी कॉलेजों के बच्चों को परीक्षा देने की अनुमति दी। लेकिन, कहा कि रिजल्ट हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगे।

मार्च 2024: हाईकोर्ट ने बचे हुए कॉलेजों की मान्यता के लिए सीबीआई से रिपोर्ट मांगी। सीबीआई इसी काम में लगी थी। इसी काम में सीबीआई अफसरों ने दलालों के जरिए कॉलेज संचालकों से रिश्वत लेने का काम शुरू कर दिया।

नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल बताने सीबीआई का रेट 10 लाख रुपए

मप्र हाईकोर्ट ने देश की सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली जांच एजेंसियों में से सीबीआई को नर्सिंग घोटाले की जांच का जिम्मा सौंपा। भोपाल के सीबीआई अफसरों ने हाईकोर्ट के भरोसे को तोड़ते हुए नर्सिंग कॉलेजों की जांच के नाम पर भ्रष्टाचार की दुकान खोल ली। नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने वाली हर टीम का सदस्य इस भ्रष्टाचार में शामिल था। सभी का रेट फिक्स था। सीबीआई की एफआईआर में खुलासा हुआ है कि कॉलेजों को सूटेबल बताने के लिए भोपाल सीबीआई अधिकारियों ने 2 से 10 लाख रुपए तक का रेट फिक्स कर रखा था। जांच टीम में शामिल नर्सिंग ऑफिसर के 50 हजार और पटवारी को 20 हजार रुपए तक के रेट तय थे। अलग-अलग दलालों को मप्र के अलग-अलग हिस्सों का जिम्मा सौंपा गया था। दिल्ली सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारियों ने अब तक इस केस में सीबीआई के डीएसपी और 3 इंस्पेक्टर सहित 23 लोगों को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने भोपाल ब्रांच में पदस्थ डीएसपी आशीष प्रसाद और इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाठे को भी नामजद कर लिया है।

लू लील लेता है हजारों जिंदगियां

गर्मियों की शुरुआत के साथ ही देश में लू का कहर धीरे-धीरे चरम पर पहुंच रहा है। भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) बढ़ते तापमान और बदलती जलवायु के साथ पहले से कहीं ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है। लू किस कदर घातक हो सकती है इसका खुलासा मोनाश विश्वविद्यालय ने अपनी एक नई रिसर्च में किया है, जिसके मुताबिक लू और गर्म हवाएं दुनियाभर में हर साल होने वाली 1,53,078 मौतों के लिए जिम्मेवार है। इससे ज्यादा परेशान करने वाला क्या हो सकता है कि इनमें से हर पांचवी मौत भारत में हो रही है। यदि आंकड़ों की मानें तो भारत में लू की वजह से हर साल औसतन 31,748 मौतें हो रही हैं। ऐसे में बढ़ती गर्मी और लू से बचाव के लिए कहीं ज्यादा संजीदा रहने की जरूरत है।

ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय द्वारा किया गया यह अध्ययन 1990 से 2019 के दौरान पिछले 30 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित है। बता दें कि होने वाली मौतों और मौसमी परिस्थितियों से जुड़े यह आंकड़े ब्रिटेन स्थित मल्टी-कंट्री मल्टी-सिटी (एमसीसी) रिसर्च नेटवर्क द्वारा जुटाए गए थे। इनमें 43 देशों की 750 जगहों पर हर दिन होने वाली मौतों को शामिल किया गया है। इस अध्ययन के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्लोस मेडिसिन में प्रकाशित हुए हैं। इस अध्ययन में मोनाश विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं के साथ-साथ चीन के शेडोंग विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ-साथ अन्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों ने भी सहयोग दिया है।

गौरतलब है कि लू से होने वाली इन अतिरिक्त मौतों के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष पर है। आंकड़ों से पता चला है कि दुनिया में सालाना लू से होने वाली डेढ़ लाख अतिरिक्त मौतों में से करीब 20.7 फीसदी भारत में हो रही हैं। वहीं 13.8 फीसदी के साथ चीन दूसरे, जबकि 7.89 फीसदी मौतों के साथ रूस तीसरे स्थान पर है। वहीं यदि क्षेत्रीय तौर पर देखें तो दुनिया में लू की वजह से होने वाली इन अतिरिक्त मौतों में से करीब 49 फीसदी एशिया में दर्ज की गई। वहीं इनमें से करीब 31.6 फीसदी यूरोप, 13.8 फीसदी अफ्रीका में दर्ज की गई। वहीं यदि अमेरिका की बात करें तो यह आंकड़ा 5.4 फीसदी जबकि ओशिनिया में सबसे कम 0.28 फीसदी दर्ज किया गया। गौरतलब है कि अध्ययन के 30 वर्षों के दौरान दुनियाभर में लू की वजह से करीब 45,92,326 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि सबसे ज्यादा अनुमानित मृत्यु दर शुष्क जलवायु और निम्न एवं मध्यम आय वाले क्षेत्रों में दर्ज की गई।

आंकड़ों की मानें तो 1990 से 2019 के बीच पिछले तीन दशकों में गर्म मौसम के दौरान होने वाली सभी मौतों में से करीब एक फीसदी के पीछे की वजह लू रही। मतलब, हर एक करोड़ की आबादी पर 236 मौतों के लिए लू जिम्मेवार रही। इस दौरान यूरोप में जितनी मौतें हुए हैं उनमें लू की हिस्सेदारी करीब 1.96 फीसदी रही। मतलब, तीन दशकों में यूरोप में हर एक करोड़ लोगों पर 655 की मौत की वजह लू रही। जो स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि लू यूरोप के लिए कितना बड़ा खतरा है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो तीन दशकों में सभी वजहों से होने वाली मौतों के मामले में लू की हिस्सेदारी अन्य देशों की तुलना में ग्रीस, माल्टा, और इटली में सबसे ज्यादा रही। जहां यह 2.47 से 2.59 फीसदी के बीच रही। वहीं यदि मृत्यु दर को समायोजित न करें तो यूक्रेन, बुल्गारिया और हंगरी में लू से जुड़ी मृत्यु दर सबसे अधिक दर्ज की गई। वहीं इसके समायोजन के बाद, नाइजर, चाड और यूक्रेन में मृत्युदर सबसे अधिक थी। रिसर्च में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि दुनिया में लू का कहर पहले से बढ़ रहा है। दुनिया में न केवल लू के दिनों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही लू पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी है।

● **रजनीकांत पारे**

भारत में योजनाओं पर गंभीरता से देना होगा ध्यान

भारतीय मौसम विभाग ने भी जानकारी दी है कि 1901 के बाद से पूर्वी भारत के लिए यह अब तक का सबसे गर्म अप्रैल का महीना था, जब तापमान 28.12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 वर्षों के दौरान अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा लू वाले दिन दर्ज किए थे। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने नए अध्ययन में आगाह किया था कि बढ़ते तापमान और जलवायु में आते बदलावों के चलते भारत के कई हिस्सों में स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खराब हो सकती है। उनका अनुमान है कि सदी के अंत तक भारत में लू का खतरा 10 गुना तक बढ़ सकता है। उनके मुताबिक आने वाले वर्षों में भारत के दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में लू के कहर में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। वहीं जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में लू पर प्रकाशित एक अन्य शोध से पता चला है कि तापमान में हर दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ लोगों के लू की चपेट में आने का जोखिम करीब तीन गुना बढ़ जाएगा। वहीं यदि वेट बल्ब तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस तापमान को इंसान के लिए खतरनाक माना जाता है जबकि 35 डिग्री सेल्सियस पर इंसान का शरीर स्वयं अपने आप को ठंडा नहीं रख पाता। हालांकि देखा जाए तो दुनियाभर में ऐसे दिनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। हीटवेव के लिए बनाए एक्शन प्लान इसमें काफी हद तक मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा कहर उस कमजोर तबके पर पड़ता है जो खुले में काम करने को मजबूर हैं। इनमें किसान, श्रमिक, पुलिस कर्मी, ट्रैफिक कर्मी जैसे लोगों शामिल हैं। यही वजह है कि लू से बचने के लिए बनाई नीतियों में उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देखा जाए तो कृषि और मेहनत मजदूरी करने वालों का एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए एयर कंडीशन तो दूर की बात, पंखा भी किसी लग्जरी से कम नहीं है।

चुनाव के मौसम में वायदों और प्रलोभनों की भरमार है। कोई राजनीतिक दल कर्ज माफी और सबको लखपति बनाने की बात कर रहा है तो कोई मुफ्त लैपटॉप और महिलाओं को मुफ्त परिवहन के वायदे के साथ मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहा है। सत्तापक्ष भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज जारी रखने और गरीबों को पक्का मकान, बिजली, गैस और स्वास्थ्य बीमा की दुहाई देकर वोट मांग रहा है।

अजब-गजब चुनावी वादे

पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाला है, जिसमें वह कहते हैं कि उनकी सरकार केंद्र की कुर्सी पर जैसे ही काबिज होगी, उसी दिन से हर गरीब परिवार की महिला के बैंक खाते में हर महीने साढ़े आठ हजार रुपए मिलने वाले हैं, खटाखट-खटाखट, खटाखट-खटाखट। एक अन्य वीडियो में राहुल गांधी वादा करते हैं कि सरकार बनते ही वे देश में करोड़ों लखपति पैदा करने वाले हैं। यह तो रही कांग्रेस के राहुल गांधी की बात। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कम नहीं हैं। 84 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक 5 किलो मुफ्त राशन के साथ-साथ सार्वजनिक मंचों से लगातार लखपति दीदियों की पूरी की पूरी फौज तैयार करने का वायदा करते आ रहे हैं।

मोटे तौर पर चुनावी सभाओं में अगर प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस और मुसलमानों पर उल्टे-सीधे आरोप नहीं लगा रहे होते हैं तो सच मानिए दिल खोलकर वादे लुटाने में लगे रहते हैं। वे डंके की चोट पर कहते हैं कि तीसरी बार जीतने के बाद जनता के लिए एक से बढ़कर एक अनोखी अद्भुत लाभकारी योजनाएं लेकर आएंगे। वे लगातार याद भी दिला रहे हैं कि पिछले 10 सालों से यथासंभव गैस के चूल्हे, पीने का पानी, शौचालयों के लिए धन, आयुष्मान कार्ड और मुफ्त राशन तो पहले से ही दे रहे हैं, आगे इसकी फेहरिस्त और लंबी होने वाली है।

देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बताने वाले मोदी साहब की शर्त बस इतनी है कि तीसरी बार भी जनता उन्हें चुनकर दिल्ली भेज दे। इस चुनाव का यही वह दिलचस्प पहलू है जहां सभी राजनेताओं ने मतदाताओं को उनके वोट के बदले में उन्हें अधिक से अधिक खैरात दिए जाने का वचन दिया है। पर सवाल यह है कि समाज कल्याण की आड़ में दोनों हाथ से लुटाने का वादा करने वाले साहेब या शहजादे इसके लिए भारी भरकम राशि कहां से लाएंगे? देने के दावे तो इस अंदाज में किए जा रहे हैं जैसे सारा का सारा माल इनका निजी धन हो। अगर नहीं तो निश्चित रूप से चुनाव के बाद वादा पूरा करने के क्रम में यह राशि देश के खाते कमाते लोगों से वसूली जाएगी। उन पर कई तरह के अतिरिक्त कर थोपे जाएंगे।

चुनाव प्रारंभ होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत बनाने पर खास फोकस कर रहे थे। भारत के जल्द ही

कांग्रेस सत्ता में आई तो भाग जाएगी गरीबी...

कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार राहुल गांधी ने कहा है कि उनके सत्ता में आते ही देश से गरीबी भाग जाएगी, क्योंकि वह 30 करोड़ गरीबों को एक-एक लाख रुपए देने जा रहे हैं। राहुल गांधी का वादा शानदार है और लोग उन्हें 2024 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनने की मांग कर रहे हैं। जाहिर है राहुल के पास इस बात का जवाब नहीं होगा कि कांग्रेस के 55 वर्ष से भी अधिक समय तक शासन में रहने के बाद भी भारत क्यों एक अत्यंत गरीब देश बना रहा? फिर भी इस बार इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाता है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो सबको लखपति बनाने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे? क्या देश के मिडिल क्लास से इसे वसूल करेंगे या कर्ज लेंगे? क्या एक जेब से दूसरे की जेब में पैसा डालने से गरीबी खत्म हो जाएगी? गरीबी हटाने के लिए किसी भी देश के पास कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल तेज विकास और भ्रष्टाचार खत्म करके ही लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है। राहुल गांधी ने कहा है कि वह हर गरीब परिवार की एक महिला को प्रतिवर्ष एक लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से वह भारत से गरीबी को एक झटके में खत्म कर देंगे।

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तथा आजादी के 100 साल पूरा होने पर दुनिया में अव्वल बनाने का दावा कर रहे थे। लेकिन अब जैसे-जैसे चुनाव अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है वैसे-वैसे प्राथमिकताएं भी बदलती जा रही हैं। अधिक से अधिक मतदाताओं को लुभाने के लिए खैरात का पिटारा तो खुल ही चुका है, दिन प्रतिदिन भाषा भी सतही हो चली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खटाखट-खटाखट को अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हर भाषण में तकिया कलाम बना लिया है। प्रधानमंत्री के तंज की एक बानगी देखिए, चार जून के बाद इंडी गठबंधन विदेश में आराम फरमाने निकल लेगा खटाखट-खटाखट। विपक्षी दल के नेता भी पीछे नहीं हैं। सपा के अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के खटाखट का जवाब फटाफट, गटागट और सटासट की अर्धाली मिलाकर दे रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी पहले संविधान को खतरे में बताकर सत्ता परिवर्तन के लिए समान विचार वाले दलों का गठबंधन तैयार कर नीतियों के आधार पर बदलाव की बात कर रही थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सत्ताधारी दल भव्य विरासत को रेखांकित करते हुए विकसित भारत का दावा कर रहा था। लेकिन तीन हिस्सा चुनाव बीतने के साथ दोनों पक्ष एक ही धरातल पर आ खड़ा हुए हैं। अब दोनों ओर से ताल ठोक कर कहा जा रहा है कि जनता हमारे दल को जिताएगी तो हम जनता को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, अनाज सबकुछ मुफ्त में मुहैया कराएंगे। भाजपानीत एनडीए की सरकार ने अगले 5 साल तक 5 किलो मुफ्त राशन का वादा किया है तो अब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने पर 10 किलो मुफ्त राशन का लॉलीपॉप दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की लखपति दीदी योजना की नकल करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में करोड़ों लखपति पैदा करने का दावा किया है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जनता को अपने पाले में करने के लिए ऑफर दर ऑफर पेश किए जा रहे हैं। कहने को देश में लोकतंत्र है, लेकिन नेतागण चुनाव में अपनी नीतियों के आधार पर समर्थन मांगने की जगह मतदाताओं के हाथ में भीख का कटोरा थमा रहे हैं। कोई कटोरे में 10 रुपए डालने को कह रहा है तो कोई कह रहा है कि अगर हमें जिताओगे तो हम 100 रुपए डालेंगे। कोई 5 किलो राशन दे रहा है तो कोई 10 किलो देने का वादा कर रहा है।

किसी भी देश का विकास वहां के लोगों के विकास पर निर्भर करता है। जिन देशों के लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं, वहां की सरकारें भी उसी अनुपात में देश को आगे ले जाने का काम करती है। ऐसा कोई उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता है जहां जनता को कमजोर करके देश को मजबूती प्रदान की गई हो। हमारे देश में सबकुछ मुफ्त में देने की आदत डाली जा रही है। कल्याणकारी राज्य बताकर समाजवादी आर्थिक नीतियों के नाम पर हमारा शासक वर्ग सेंत-मेंत में चीजों को मुहैया कराने का हिमायती रहा है। जनता में पहले यह विश्वास पैदा किया गया कि सबकुछ सरकार ही देती है, यहां तक कि रोजी-रोटी भी। उदारीकरण के बाद स्थितियां थोड़ी बदलीं। आम आदमी सरकार के भरोसे कम, अपनी मेहनत के बदौलत आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल हुआ। कोटा परमिट का राज खत्म होने के बाद विकास ने रफ्तार पकड़ी और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। भूमंडलीकरण के बाद भारतीय मेधा का पूरी दुनिया में डंका बजने लगा। विशेष रूप से आईटी के क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की। लेकिन वर्तमान चुनाव में जो बातें पक्ष और विपक्ष द्वारा उठाई जा रही हैं, जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं उनसे अच्छे भविष्य के संकेत नहीं मिलते। एक दल कह रहा है कि अगर सत्ताधारी फिर चुनकर आए तो संविधान को मिटा देंगे तो दूसरा दल कह रहा है कि अगर विपक्षी चुने गए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। एक तरफ से कहा जा रहा है कि वोट के लालच में धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है तो दूसरे का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए तुष्टिकरण की नीति अपनाई जा रही है। लेकिन जब मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात आती है तो दोनों ही दल फटाफट अधिक से अधिक देने का दावा करने लगते हैं। अब तक जनता को मिलने वाले लाभों को गटागट डकार जाने वाले भी चुनाव जीतने पर अधिक से अधिक सुविधाएं सटासट उड़ेल देने की बात कर रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि राजनेता देश की अधिकांश जनता को मुफ्त के जाल में फंसाकर सदैव के लिए परजीवी बनाकर रखना चाहते हैं ताकि हर मौके पर उनकी पौ बारह रहे।

मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) की समीक्षा करने और 11.8 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मुफ्त खाद्यान्न सब्सिडी योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का ऐलान भी इसी चुनाव को देखकर किया था। मुफ्त की योजना और स्कीम लाने वाला कोई भी दल जनता को यह नहीं बताता कि ये वायदे कैसे पूरे होते हैं और इनका खर्च कौन उठाता है? जबकि सब जानते हैं कि पैसा अंततः करदाता की जेब से ही निकलता है।

● **विपिन कंधारी**

महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या

इस चुनाव में विपक्ष की तरफ से जो दो मुद्दे काफी प्रभावी ढंग से उठाए गए हैं, वे है महंगाई और बेरोजगारी। इन दोनों समस्याओं का मूल है जनसंख्या वृद्धि। उतना अनाज नहीं, जितनी जरूरत है, इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है। उतने रोजगार नहीं है, जितनी आबादी बढ़ती जा रही है, तो इसका निदान भी है जनसंख्या नियंत्रण। भारत में हर रोज 86 हजार बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब चीन नहीं भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, 2022-23 में भारत की आबादी 1,428,627,663 पहुंच गई है, जबकि चीन की आबादी 1,425,671,352 है। भारत के पास 3,287,263 वर्ग किलोमीटर जमीन है, जो विश्व का सिर्फ 2.4 प्रतिशत भूभाग है, लेकिन भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17 प्रतिशत से ज्यादा है। चीन के पास भारत से लगभग तीन गुना 9,598,094 वर्ग किलोमीटर जमीन है, लेकिन आबादी अब हम से कम हो गई है। पिछले दिनों जब जनसंख्या कानून की बात उठी थी, तो उसका यह कहकर विरोध किया गया था कि स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या पर नियंत्रण हो चुका है, इसलिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। लेकिन बिहार में यह 2.98, मेघालय में 2.91, उप्र में 2.35 और झारखंड में 2.26 है।

18वीं लोकसभा में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है। पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वह इस बार 400 सीटें हासिल कर लेगी। लेकिन अब तक हुए 6 चरणों के मतदान में जिस तरह कम वोटिंग हुई है, उससे तो अब भाजपा को पूर्ण बहुमत की दरकार है। गौरतलब है कि इस बार भाजपा वाली एनडीए और कांग्रेस वाली इंडिया गठबंधन में जोरदार मुकाबला है। दोनों गठबंधन अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है। उससे फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

अब पूर्ण बहुमत की दरकार...

भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत 400 पार के नारे के साथ की थी। लेकिन जैसे-जैसे मतदान होता जा रहा है भाजपा का लक्ष्य भी सिकुड़ता जा रहा है। 400 पार की जगह अब भाजपा ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार को अपना नारा बना लिया है। असल में देश में चल रहे आम चुनाव में मतदान के हर चरण के बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भाजपा को मिलने वाली सीटों का आंतरिक आंकलन कर रहे हैं। अमित शाह हर चरण के मतदान के बाद देर रात सभी प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों से बात करते हैं और मतदान के बाद की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। अभी तक अमित शाह 6 चरणों के मतदान की जानकारी मोदी के पास पहुंचा चुके हैं। भाजपा हाईकमान का आंकलन है कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटें भाजपा जीत रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में भाजपा 3 सीटों का नुकसान मानकर चल रही है। 2014 में भाजपा ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीत ली थीं। 2019 में भाजपा ने 24 और नागौर की एक सीट गठबंधन सहयोगी आरएलपी ने जीती थी। दक्षिण के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु जहां से 29 सीटें आती हैं वहां भाजपा एक सीट पर जीत निश्चित मानकर चल रही है और वह सीट है प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की सीट कोयम्बटूर। इसके अलावा अन्नामलाई ने दो और सीटें भाजपा के पक्ष में आने का भरोसा केंद्रीय नेतृत्व को दिया है।

दक्षिण भारत के राज्य केरल में जहां की सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ था, वहां से भाजपा को दो सीट पर जीत की उम्मीद नजर आ रही है। दक्षिण से ही आने वाले राज्य और भाजपा का मजबूत गढ़ रहे कर्नाटक राज्य में भाजपा को भरोसा है कि उसने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। कर्नाटक में मतदान पूरा हो चुका है और भाजपा का अनुमान है कि वह कर्नाटक की 28 सीटों में 21-22 सीटें जीत रही है। भाजपा का यहां पर जेडीएस से गठबंधन है। उत्तर पूर्व से आने वाली 25 सीटों पर पहले दो चरणों में मतदान हो चुका है। भाजपा को उम्मीद है कि वह यहां से 20 सीटें जीतने जा रही है। 2019 में इन 25 सीटों में से भाजपा को 15 सीटें मिली थीं। नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेवारी इस बार पूरी तरह से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के कंधों पर थी। पहले चार चरणों में मप्र की 29 सीटों पर हुए मतदान में भाजपा का आंकलन है कि मप्र में उसे 29 में से 28 सीटें मिलने जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि भाजपा ने 2019 के अपने प्रदर्शन को इस राज्य में बरकरार रखा है। मध्य भारत के एक और राज्य छत्तीसगढ़ में जहां भाजपा ने कुछ माह पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया है, इस राज्य की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है।

भाजपा जिन राज्यों को लेकर सबसे ज्यादा

भाजपा के लिए 370 का टारगेट

दो बिल बनकर तैयार रखे हुए हैं, लेकिन उनके लिए दो तिहाई सीटें चाहिए। वैसे लोकसभा में 362 सीटों के साथ दो तिहाई बहुमत बन जाता है। इसीलिए मोदी ने भाजपा के लिए 370 का टारगेट रखा है। वैसे मोदी को इतना समर्थन तो सत्रहवीं लोकसभा में भी हासिल था। जिसका जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में किया भी है। एनडीए के 353 सदस्यों के अलावा उन्हें लगभग हर बिल पर बीजू जनता दल के 12 और वाईएसआर कांग्रेस के 22 सदस्यों का समर्थन मिल रहा था। सवाल पैदा होता है कि फिर उन्होंने वे दो बिल पास क्यों नहीं करवाए, और वे दो बिल हैं कौन से? पहला बिल है जनसंख्या नियंत्रण का, और दूसरा बिल है समान नागरिक संहिता का। ये दोनों ही संविधान संशोधन बिल हैं। इन दोनों बिलों पर विपक्ष का तो कड़ा विरोध सर्वविदित है, क्योंकि दोनों बिलों का मुसलमान विरोध करते हैं। इन दोनों बिलों के खिलाफ मौलवियों के फतवे भी जारी हो चुके हैं।

भ्रम में है, उन राज्यों में महाराष्ट्र की 48, बिहार की 40, पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के साथ हरियाणा की 10 सीटें भी शामिल हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर, बिहार की 32 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 33 सीटों पर मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र में 20 मई को पांचवे चरण की 13 सीटों पर मतदान होने के साथ ही महाराष्ट्र में मतदान पूरा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल से आने वाली 130 सीटों पर भारी नुकसान से बचने की हरसंभव कोशिश कर रही है। बंद दरवाजे के पीछे भाजपा के शीर्ष रणनीतिकार इस बात को मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में उसे नुकसान हो रहा है और उसके सहयोगी दल भी उसके नुकसान को बढ़ा ही रहे हैं। इसी तरह इस बार बिहार में नीतीश को साथ लेना भाजपा को भारी पड़ रहा है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि नीतीश को साथ लेना एक भारी भूल साबित हुई। नीतीश के बिना हम ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाते।

पश्चिम बंगाल में भाजपा को भरोसा था कि संदेशखाली और सीएए उसके पक्ष में भारी बढ़त लेकर आएगा लेकिन जमीनी स्तर से आ रही खबरों ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में ममता का दुर्ग ढहाने की भाजपा की इच्छा पूरी होती नजर नहीं आ रही है। बंगाल में अभी तक 6 चरणों में कुल मिलाकर 33 सीटों पर मतदान हो चुका है। ध्रुवीकरण की कोशिशों के बाद भी यहां भाजपा अपने 2019 के प्रदर्शन के आसपास ही पहुंचती दिख रही है जब उसने राज्य में 18 सीटें जीती थीं। इस बार पश्चिम बंगाल से 25 सीटें जीतने का भाजपा का सपना शायद सपना ही रह जाएगा। उप्र में 6 चरणों में मिलाकर अभी तक 67 सीटों पर मतदान हो चुका है। मतलब उप्र की 80 सीटों में लगभग 67 सीटों पर मतदान हो चुका है। उप्र में भाजपा को मायावती और अखिलेश के साथ न होने का फायदा मिल रहा है। भाजपा देश के सबसे बड़े राज्य से इस बार 80 में से 75 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

दिल्ली से सटे हरियाणा में 2019 में भाजपा ने सभी 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार हरियाणा की राजनीतिक उठापटक के कारण उसे नुकसान हो रहा है। हरियाणा में टिकट वितरण ने भी भाजपा की अंदरूनी कलह को बढ़ा दिया है। ऐसे में छठे चरण में 25 मई को हुए हरियाणा के चुनाव में भाजपा को 3 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आने के बाद भी भाजपा का आंकलन है कि दिल्ली की सभी 7 सीटें वह जीत रही है। पंजाब से भाजपा को कोई खास उम्मीद नहीं है। 2019 में भाजपा ने दो सीटें जीती थीं। अकाली दल से अलग होकर और ज्यादातर सीटों पर दूसरे दलों से आए दलबदलुओं को टिकट देकर भाजपा रेस में बने रहने की कोशिश कर रही है। लेकिन पंजाब में आप पार्टी सब पर भारी पड़ रही है। भाजपा पंजाब में अपनी दो सीटें बचाने से ज्यादा कांग्रेस की 2019 में जीती 8 सीटों पर हार सुनिश्चित करना चाहती है। पंजाब में कांग्रेस की बुरी हार ही भाजपा की जीत होगी। कारण स्पष्ट है अगर कांग्रेस को तीसरी बार विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें नहीं मिलने देना है तो ऐसे में कांग्रेस की पंजाब में हार भाजपा के लिए जरूरी है। बहरहाल, 6 चरणों के मतदान के बाद भाजपा 400 पार के नारे को सार्वजनिक रूप से बोलने से बच रही है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आंकलन है कि अबकी बार 400 पार नहीं बल्कि 2014 और 2019 में जीती सीटों के बीच कहीं जाकर आंकड़ा रुक सकता है। फिर भी भाजपा किसी भी हालत में अपने प्रदर्शन को 282 से नीचे आते हुए नहीं देखना चाहती। यही कारण है कि 6 चरण मतदान के बाद भाजपा ने 370 की जिद छोड़ दी है। अब भाजपा लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार नारे पर फोकस कर रही है। इस नारे की शुरुआत अमित शाह बिहार और बंगाल से कर चुके हैं।

राज्यसभा में भी मजबूती जरुरी

किसी भी बिल को पास कराने के लिए भाजपा को राज्यसभा में भी मजबूती की जरूरत है। राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत के लिए 164 सांसद चाहिए। आज की तारीख में राज्यसभा में भाजपा के खुद के सांसदों की संख्या 97 और एनडीए के सांसदों की संख्या 120 है। इसलिए मोदी सरकार ने कुछ बिल भविष्य के लिए छोड़ दिए थे। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य घोषित किया था। अब अगर लोकसभा में एनडीए को 406 सीटें मिल जाती हैं, तो यह दो तिहाई से 44 सीटें ज्यादा होंगी। जो राज्यसभा में दो तिहाई की कमी पूरी करेंगी। विपक्ष के कड़े विरोध के चलते बिल क्योंकि राज्यसभा में पास नहीं होंगे, इसलिए मोदी सरकार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर बिल पास करवा सकती है। वैसे इन दोनों बिलों पर अगर एनडीए का एक भी घटक दल ऐतराज करता है, तो इंडी अलायंस में भी फूट पड़ने की प्रबल संभावना बनेगी। जैसे उद्धव ठाकरे इन दोनों बिलों का समर्थन कर सकते हैं।

नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा चुनाव में चर्चा का विषय बना चुका है। हालांकि जबसे विपक्ष ने यह कहना शुरू किया कि मोदी इस जनादेश से आरक्षण खत्म कर देंगे तो मोदी ने 400 पार का नारा लगवाना बंद कर दिया। अब उसकी जगह पर तीसरी बार मोदी सरकार का नारा लगवाते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें खुद यह टारगेट असंभव लगने लगा हो। या विपक्ष के आरक्षण खत्म करने वाले नैरेटिव की वजह से ट्रैक चेंज किया हो। वैसे मोदी और अमित शाह सफाई देते घूम रहे हैं कि आरक्षण हम तो क्या बाबा साहेब अंबेडकर भी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष भ्रम पैदा करने में काफी हद तक कामयाब होता दिख रहा है, खासकर कम पढ़े-लिखे लोगों में और ग्रामीण इलाकों में।

दलित और ओबीसी परिवारों में चिंता बनी है कि क्या विपक्ष की आशंका सही है। क्या मोदी सचमुच जाति आधारित आरक्षण खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं? मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण लागू करके पहल की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज ठहरा दिया है। मोदी और अमित शाह के स्पष्टीकरणों के बावजूद जमीन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को इन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। जिसका भाजपा को हिंदी बेल्ट में थोड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि मोदी या भाजपा का आरक्षण का स्वरूप बदलने का कोई इरादा नहीं है। उनका लक्ष्य ऊंचा है, जिसके लिए उन्हें 400 नहीं बल्कि 406 सीटें चाहिए।

● **इन्द्र कुमार**

नक्सल पुनर्वास नीति में बदलाव

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार नक्सल पुनर्वास नीति में बदलाव करने जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आत्मसमर्पितों को निवास के लिए मनचाहे शहर या गांव का विकल्प दिया जाएगा। मकान ऐसा होगा जिसमें उनका पूरा परिवार एक साथ रह सके। रोजगार के लिए कौशल विकास की योजनाएं चलाई जाएंगी। इसके तहत उन्हें प्रशिक्षण मिलेगा। स्वरोजगार चाहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। इसके अलावा पुलिस उनके न्यायालयीन प्रकरणों को सुलझाने में भी मदद करेगी। मौजूदा पुनर्वास के प्रावधान के अंतर्गत आत्मसमर्पितों को किराए का मकान दिया जाता है। पुनर्वास की राशि, उनके रोजगार, बच्चों की शिक्षा समेत अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें देरी की शिकायतें हैं। अब कोई हत्या या लूट के आरोपी आत्मसमर्पित नक्सली पर कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस उसके न्यायालयीन प्रकरणों को सुलझाने में मदद करेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यह कहकर संकेत दे चुके हैं कि हमारी पुनर्वास नीति के कारण नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस नीति में और क्या नया बेहतर हो सकता है, साथ ही नई पुनर्वास नीति लाने पर विचार किया जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार संशोधित पुनर्वास नीति लागू कर सकती है। चार महीने की विष्णुदेव सरकार में अब तक 112 नक्सली ढेर हुए हैं। तीन वर्ष के भीतर नक्सलियों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जिस रोडमैप को हरी झंडी दी है, उसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा आगे बढ़ा रहे हैं। दावा है कि चार महीने के भीतर 375 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, वहीं 153 गिरफ्तार किए गए। नक्सल क्षेत्र में 28 सुरक्षा कैंप खुले और 143 आईडी बरामद किए गए हैं। प्रदेश के नक्सल क्षेत्र में अभी 400 सुरक्षा कैंप हैं। इनमें 28 कैंप भाजपा सरकार में खोले गए हैं। अभी 50 कैंप और खोले जाएंगे। जहां सुरक्षा कैंप खुलता है वहां से सुरक्षा बल के जवान 25-30 किलोमीटर के दायरे में सर्चिंग करते हैं। पिछले चार महीने में जवान नक्सलियों के कैंप तक घुसने में कामयाब हुए हैं। सुकमा जिले के अतिसंवेदनशील क्षेत्र में मौजूद पूर्वर्तीय गांव मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा का पैतृक गांव है। सुरक्षाबल के जवानों के द्वारा यहां भी पुलिस कैंप खोला गया। इसी तरह सिलगेर, टेकलगुड़ा, जोनागुड़ा जैसे संवेदनशील गांवों तक सरकार की योजनाएं पहुंची हैं। यहां इस बार लोकतंत्र भी जीता, चुनाव आयोग ने भी मतदान करवाने में सफलता पाई।

वर्तमान नीति में नक्सल व्यक्तियों या परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का प्रावधान है। पुनर्व्यस्थापन में कठिनाई होने पर राज्य स्तर पर अपर मुख्य या प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति गठित है। पुनर्वास के लिए विभिन्न विभागों को अनेक प्रकार के लाभ और सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ प्रकरणों में देरी की भी शिकायत है, अब तत्काल सुविधा मिलेगी। प्रत्येक नक्सली को समर्पण पर प्रोत्साहन के लिए 25 हजार रुपए की राशि देने का नियम है। नक्सल पीड़ित के समान ही आत्मसमर्पित नक्सलियों को सुविधाएं देने का प्रावधान है। सक्रिय, पांच लाख या अधिक के ईनामी नक्सली को आत्मसमर्पण पर 10 लाख की राशि पृथक से देने, समर्पित हथियार के बदले देय मुआवजा राशि का प्रावधान है। यह राशि बैंक में सावधि जमा की जाती है और इसका ब्याज समर्पित नक्सली को मिलता है। तीन साल बाद चाल चलन की समीक्षा उपरांत यह राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यदि समर्पित नक्सली द्वारा तीन वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय की जाती है तब दो एकड़ तक भूमि पर स्टांप ड्यूटी व पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट देने का प्रावधान है। अभी नक्सल पीड़ित या आत्मसमर्पित नक्सली जिसके द्वारा नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया जाता है और जिसे इस कारण स्वयं की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया हो, ऐसे प्रकरणों में पुलिस महानिरीक्षक रेंज उसे पुलिस विभाग में निम्नतम पदों पर भर्ती करते हैं।

गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार के आने के बाद यहां नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई के दौरान मिल रही अभूतपूर्व सफलताओं के लिए सरकार की पीठ थपथपाई है। गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद मात्र साढ़े चार महीने के अंदर 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 375 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 5 महीने में अभियान को जबरदस्ती सफलता मिली है। शाह ने कहा कि अब प्रदेश के 3-4 जिलों में ही नक्सली बचे हैं और आगामी 2-3 वर्षों में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा इसे फेक एनकाउंटर कहे जाने पर अमित शाह ने गोस्वामी तुलसीदास के एक दोहे का उदाहरण देते हुए कहा कि जिसका बुरा समय आता है, भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ यही हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका आभार जताया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा है कि, हम नक्सल समस्या के स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के पश्चात नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में तेजी आई है। मात्र साढ़े चार महीने की सरकार में नक्सली लगातार मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं या सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

बंदूक और विकास से नक्सलवाद पर वार

विष्णुदेव सरकार ने बंदूक और विकास से नक्सलवाद के खिलाफ समानांतर लड़ाई लड़ने की कार्य योजना बनाई है। नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों तक नियद नेल्लानार योजना के तहत बुनियादी सुविधा पहुंचाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इन परिवारों का सर्वे किया जा रहा है। सुरक्षा कैंप के माध्यम से नक्सलियों को खदेड़ने के बाद यहां प्रशासन की टीम गांव में पहुंचकर लोगों को बुनियादी सुविधा मुहैया कराएगी। यह कार्यक्रम निरंतर चलाने की योजना बनी है। उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि राज्य में नक्सल पुनर्वास नीति में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। हम खून-खराबा नहीं चाहते। मैंने तो नक्सलियों से हाथ जोड़कर अपील की है कि वह मुख्यधारा में लौटें और हम वार्ता के लिए तैयार हैं।

मराठा गौरव का चुनावी दांव

महाराष्ट्र में इस बार एनडीए के लिए राह 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव जितनी आसान नहीं होगी। 2019 में एनडीए ने 48 में से 41 लोकसभा सीटें जीती थीं। एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का कहना है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में सहानुभूति की लहर है। उन्होंने नासिक लोकसभा सीट पर विवाद के बाद हटने के अपने फैसले पर भी बात की। भुजबल ने इस बात पर भी अपने विचार साझा किए कि क्या 400 सीटें जीतने के लिए एनडीए का नारा- अबकी बार 400 पार... मतदाताओं को ये विश्वास दिलाने के लिए है कि संविधान में संशोधन किया जाएगा। महाराष्ट्र की पहले से ही दिलचस्प रही राजनीति 2022 में और अधिक उलझ गई। एकनाथ शिंदे और विधायकों के एक समूह ने शिवसेना में विद्रोह कर दिया, जिसके कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। शिंदे ने फिर भाजपा के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना दो भागों में बंट गई।

बारामती की रैली में उद्धव ठाकरे जैसे मंच पर आए तो देर रात में उंघती भीड़ में जैसे बिजली-सी दौड़ गई। पवार कुनबे की यह पारंपरिक सीट महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल की मानो प्रतीक और प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। शरद पवार और उद्धव इसे मराठा गौरव से जोड़ते हैं। उद्धव लोगों से कहते हैं कि क्या मराठा स्वाभिमान को आहत करने वालों को माफ करेंगे और भीड़ में गर्जना उठती है- गद्दार मुर्दाबाद। दरअसल यहां की सांसद, पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अजित पवार की पत्नी को खड़ा किया गया है। ठाकरे लोगों से कहते हैं कि अजित दादा से बड़े दोषी वे लोग हैं जो परिवार को बांटना चाहते हैं, जिन्हें मराठा संस्कृति, मर्यादा का ख्याल नहीं है।

दरअसल ज्यादातर चुनाव विशेषज्ञों का अनुमान है कि भाजपा ने जिस तरह शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट करवाई, वह लोगों को शायद नहीं सुहाया। शायद यह भावना न सिर्फ राकांपा के अजित गुट और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट पर ही भारी पड़ेगी, बल्कि भाजपा को भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा किसानों, युवाओं के मुद्दे भी गरमी पैदा कर रहे हैं। संकेत ये भी हैं कि संविधान बदलने का मुद्दा भी दलितों को प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि विदर्भ और मराठवाड़ा की जिन सीटों पर पहले, दूसरे, तीसरे चरण में वोट पड़े हैं, उनमें हवा भाजपा और एनडीए के विपरीत बहती नजर आ रही है। मसलन, कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण को भाजपा ने इस उम्मीद में पाला बदलवाकर राज्यसभा सदस्य बनाया हो सकता है कि नांदेड में उनके असर का फायदा उठाया जा सके। लेकिन वहां से आ रही खबरों से पता चलता है कि कई जगह लोगों ने सरेआम विरोध किया। वैसे भी मराठा कुनबी, दलित और अल्पसंख्यकों के वोट विपक्ष की ओर गए तो भाजपा को मुश्किल हो सकती है। विदर्भ और कुछ आदिवासी सीटों पर भी हवा भाजपा के विपरीत बहती लगती है। अब यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है कि वे इस हवा को कितना बदल पाते हैं। उनकी रैलियां भी वहां लगातार हो रही हैं।

बहरहाल, इस जंग में भाजपा से ज्यादा ठाकरे और पवार की परीक्षा होनी है। मोदी के उन्हें नकली राकांपा और नकली शिवसेना कहने का क्या असर होता है, यह देखना होगा। हाल में उन्होंने पवार को भटकती आत्मा कहा। उधर से भी मराठी-गुजराती विवाद उठाने की कोशिश हो रही है। यानी जंग तीखी होती जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पाटी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल के दिनों में अपनाया गया रुख विभिन्न समुदायों को पास लाने के बजाय देश में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा सकता है। पवार महाराष्ट्र के डिंडोरी (सुरक्षित) लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार भास्कर भगारे के पक्ष में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। भगारे का मुकाबला भाजपा सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती पवार से है। पवार ने कहा, नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके रुख से विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ सकता है। मैंने नासिक में उनका भाषण सुना, और यह मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप था। उनका रुख ऐसा होना चाहिए था जिससे विभिन्न समुदाय और धार्मिक समूह करीब आते। पवार ने क्षेत्र में पानी की कमी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, नासिक जिले में पानी की उपलब्धता और उसका वितरण मुद्दा है। उपलब्ध पानी का कुछ हिस्सा गुजरात की ओर भेज दिया जाता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा ने अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ी गई 25 सीटों में से 23 पर जीत हासिल की। उप्र के बाद महाराष्ट्र दूसरे सबसे अधिक संख्या में सांसद भेजता है। 2022 में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो हिस्सों में बंटने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति जटिल हो गई है।

● **बिन्दु माथुर**

पवार के कारण मोदी की आत्मा बेचैन

पवार की बातों में लोग इसलिए वजन मान रहे हैं क्योंकि मोदी अपनी रैलियों में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जिस किस्म के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, उससे लगता है कि शायद भाजपा, और खुद मोदी को भी, महाराष्ट्र के हाथ से फिसलने का आभास होने लगा है। इसे ही कहते हैं दांव उलटा पड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे की जनसभा में शरद पवार को भटकती आत्मा कहा था। इसे लेकर पवार ने कहा कि मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए प्रधानमंत्री सही ही कह रहे होंगे क्योंकि मैं किसानों का दर्द, महंगाई से परेशान आम आदमी का दर्द बताने के लिए भटकता हूं। लेकिन पवार मौके पर सही चोट करने वाले माने जाते हैं और उन्होंने अब जो कहा है, उससे मोदी-अमित शाह समेत पूरी भाजपा हड़बड़ा गई है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि शिवसेना और एनसीपी में विभाजन को लेकर लोगों में भाजपा के खिलाफ गुस्सा तो है ही, आरएसएस का एक गुट भी मोदी के एकाधिकार को पसंद नहीं करता है और बदलाव चाहता है इसलिए पुणे और शिरूर में ज्यादातर स्वयंसेवक वोटिंग के लिए घर से बाहर ही नहीं निकले।

कांग्रेस की तीसरी शक्ति डोटासरा!

राजस्थान को राजनीतिक खबरों के लिहाज से देशभर में सूखे प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन बीते 5 वर्षों में राजस्थान की राजनीति ने वो रंग दिखाए जो किसी भी राज्य की राजनीति में अब तक नजर नहीं आए। चाहे फिर वो सत्ता के लिए अपनों से बगावत की बात हो, या फिर दबाव में दिया गया इस्तीफा प्रकरण हो। विधायकों की खरीद-फरोख्त से लेकर उनके दल-बदल जैसे कई राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रदेश की राजनीति ने देशभर में सुर्खियां बटोरी। लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस को सत्ता गवांकर भुगतना पड़ा। वर्तमान में प्रदेश में भाजपा का शासन है। ऐसे में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और फिलहाल देशभर में लोकसभा चुनाव जारी हैं। इस बार राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है। आखिर क्या वजह है कि जो कांग्रेस लगातार दो बार से 25 सीटें हारती आई है वो इस बार अच्छी खासी स्थिति में नजर आ रही है?

वैसे तो कांग्रेस के सत्ता में रहने के बाद चुनावी परिणाम हमेशा से ही अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन वर्ष 2020 में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और उनके नेतृत्व में हुए उपचुनाव व निकाय चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करके उभरती है। डोटासरा के नेतृत्व में लड़े गए दरियाबाद के उपचुनाव में भाजपा की जमानत जप्त हो जाती है और इसके बाद अखबारों की सुर्खियों से लेकर चाय की थडियों तक, गहलोत और पायलट के अलावा डोटासरा का नाम भी लिया जाने लगता है। लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। क्योंकि बीते 26 सालों में अब तक जो नहीं हुआ था, वह गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में हुआ। पूर्व अध्यक्षों की बात करें तो 1998 के चुनाव में कांग्रेस 156 सीटें जीतकर सरकार बनाती है। लेकिन इसके बाद 2003 के चुनाव के समय कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गिरिजा व्यास होती है और कांग्रेस केवल 56 सीटों पर सिमट जाती है। ऐसे में करीब 100 सीटों का नुकसान कांग्रेस को होता है। इसके बाद 2008 से 2013 तक कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है और डॉ. चंद्रभान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। इनके नेतृत्व में 2013 का चुनाव लड़ा जाता है, जहां कांग्रेस केवल 21 सीटों पर सिमट जाती है। वर्ष 2013 के बाद सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है और इस दौरान पायलट के सामने वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव आ जाता है, जहां कांग्रेस 25 की 25 लोकसभा सीटें हार जाती है। लेकिन सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस वर्ष 2018 में सत्ता में तो आ जाती है, लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पायलट के अध्यक्ष रहते फिर से कांग्रेस 25 सीटें गंवा देती है। सचिन पायलट वर्ष 2018 से 2020 तक उपमुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन जुलाई 2020 में हुए मानेसर कांड के बाद गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है।

गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस के उदयपुर संकल्प पत्र को धरातल पर उतारने का काम किया। इसे लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। वहीं पूरे प्रदेश में 2200 नए मंडल स्थापित किए, जिससे कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस से नए कार्यकर्ता जुड़े। लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए पदाधिकारी को बदलकर नए लोगों को मौका दिया। कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी को पीसीसी में नई जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस के महिला मोर्चा को मजबूती देने का काम किया। महिलाओं के माध्यम से कांग्रेस ने डोर-टू-डोर कैंपेनिंग की। और भी ऐसे कई काम डोटासरा ने किए जिससे राजस्थान में कांग्रेस संगठन को मजबूती मिली। डोटासरा को जुलाई 2020 में सियासी संकट के समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हें इस पद पर करीब चार साल का वक्त हो गया है। विधानसभा चुनाव के बाद से उनके बदले जाने को लेकर चर्चाएं थीं लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें कंटिन्यू किया गया अब उन्हें आगे वक्त मिलेगा या नहीं यह सब कुछ आलाकमान पर निर्भर करता है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये भी है कि इस बार पीसीसी चीफ के पद के लिए अशोक गहलोत के नाम की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि अगर केंद्र में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो अशोक गहलोत राजस्थान की सियासत में ही बने रहना चाहेंगे और राजस्थान में संगठन पर पकड़ बनी रहे इसके लिए उनके खेमे की ओर से पीसीसी चीफ के पद को लेकर लॉबिंग की जा रही है। गहलोत मुख्यमंत्री बनने से पहले पीसीसी चीफ रह चुके हैं। लेकिन इस बार इस पद के लिए उनका नाम चर्चाओं में होना सबके लिए चौंकाने वाला है। अगर अशोक गहलोत खुद नहीं बने तो फिर अपने खेमे के किसी युवा नेता को यह जिम्मेदारी दिला सकते हैं ताकि राजस्थान में कांग्रेस की सियासत पर उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का है। सचिन पायलट पहले भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और 2018 में कांग्रेस सत्ता में भी आई थी। इस बार भी विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा थी। कहा गया था कि सचिन पायलट की ओर से दिलचस्पी नहीं दिखाए जाने पर ही डोटासरा को कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया था।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

डोटासरा के आते ही बदल गए आंकड़े

कांग्रेस ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा, जहां कांग्रेस ने बीते 26 सालों में जो नहीं हुआ वो परिपाटी कांग्रेस ने इस चुनाव में तोड़ी। बीते कई चुनाव में कांग्रेस सत्ता में रहने के बाद 70 विधायक अब से पहले कभी जीतकर नहीं आए। ऐसे में इन 26 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी पीसीसी चीफ के नेतृत्व में 70 विधायक जीतकर आए हों। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पूरे प्रदेश की 25 सीटों पर चुनाव प्रचार में पहुंचे और संगठन के साथ-साथ स्थानीय नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करके पार्टी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस करीब एक दर्जन सीटों पर मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अगर कांग्रेस जहां दो बार से 25 की 25 लोकसभा सीटें हारती आ रही है, तो इस बार अगर 5 से 8 सीटें भी जीतकर आती है तो कहीं ना कहीं डोटासरा का राजनीतिक कद और बढ़ जाएगा।

पूर्वांचल पर टिकी है सबकी नजर

उप्र में छह चरण के मतदान के बाद अब सातवें चरण पर सभी की नजर है। छठवें चरण में पूर्वांचल की 15 सीटों पर मतदान के बाद अब सातवें चरण में पूर्वांचल की 12 सीटों पर मतदान होना है जहां से खुद नरेंद्र मोदी बतौर उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी दल या गठबंधन पूर्वांचल में बढ़त हासिल करता है, उसकी सरकार बनने की संभावना मजबूत होती है। यह वर्ष 2014 के बाद पहला चुनाव है, जिसमें कोई भी लहर नजर नहीं आ रही है। इसी इलाके में राम मंदिर निर्माण के बाद भी ध्रुवीकरण जैसा उद्वेग कहीं नजर नहीं आ रहा है। मतदाता भी चुनाव को लेकर उत्साहित नहीं हैं, इसलिए पूर्वांचल में कोई बड़ा उलटफेर हो जाएगा, इसकी संभावना नहीं है।

उप्र में हुए अब तक के मतदान में दोनों गठबंधन अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उप्र में हुए अब तक के मतदान के समीकरण और ट्रेंड को देखें तो भाजपा बढ़त पर है, लेकिन उसे 2019 के मुकाबले कई सीटों पर स्थानीय प्रत्याशियों से नाराजगी के चलते नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि यह नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि सत्ता का समीकरण बदल दे, लेकिन ऐसा लगता है कि जनता मोदी के नाम पर अब किसी को भी जिताने के लिए तैयार नहीं है। यह मतदान प्रतिशत से स्पष्ट दिख रहा है।

मोदी और अमित शाह भी स्थिति को भांप चुके हैं, लिहाजा दोनों नेताओं ने पूर्वांचल में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पूर्वांचल के दो चरणों में भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी, सुभासपा और अपना दल की क्षमता का भी टेस्ट होना है। पूर्वांचल की 27 सीटों पर पिछड़े मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, जिसमें यादव, कुर्मी, राजभर जैसी जातियां शामिल हैं। भाजपा को केशवदेव मौर्य की पार्टी महान दल ने भी समर्थन दे दिया है, जो भाजपा के लिए राहत की बात है। पूर्वांचल में 50 फीसदी से ज्यादा पिछड़े मतदाता हैं, जो दोनों गठबंधनों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बार भी भाजपा के लिए पूर्वांचल को साध पाना आसान नहीं है। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा झटका पूर्वांचल में ही लगा था। अंबेडकरनगर, आजमगढ़, श्रावस्ती, जौनपुर, गाजीपुर, लालगंज तथा घोसी में उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस बार इन सीटों के अलावा पूर्वांचल की आधा दर्जन से ज्यादा अन्य सीटें हैं, जिन पर भाजपा को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। चंदौली, भदोही, बस्ती, देवरिया, प्रतापगढ़, मछलीशहर और कौशांबी में इंडिया गठबंधन से कांटे की लड़ाई है। इन सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों से जनता में भारी नाराजगी है।

पश्चिमी उप्र में क्षत्रिय मतदाताओं के विरोध के बावजूद भाजपा को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उप्र में कई जनसभाएं करके भाजपा के खिलाफ माहौल को पूरी तरह बिगड़ने नहीं दिया। हालांकि जिन प्रत्याशियों को लेकर विरोध हो रहा था, वहां की सीट फंस जरूर गई है। धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूर्वांचल में भी समीकरण बिगड़ने लगे थे, लेकिन इसे सुलझाने की बागडोर अमित शाह ने खुद अपने हाथ में ले ली। जौनपुर में भाजपा तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अचानक बसपा ने श्रीकला सिंह का टिकट काटकर भाजपा को लड़ाई में ला दिया है। जौनपुर सीट से बसपा ने श्याम सिंह यादव को टिकट देकर इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को होगा। इधर, बसपा से किनारे लगाए गए धनंजय सिंह ने किस दबाव और लाभ के चलते भाजपा को समर्थन देने की बात कही है, वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन धनंजय की अपील के बाद भाजपा जौनपुर में मजबूत स्थिति में आ गई है। भदोही में भी लड़ाई कांटे की है। ब्राह्मण, मुस्लिम एवं बिंद बाहुल्य इस सीट पर भाजपा की लड़ाई गठबंधन कोटे से उतरे पूर्व विधायक एवं तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ललितेशपति त्रिपाठी से है। पिछली बार यह सीट भाजपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार भदोही का ब्राह्मण वोटर दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे पंडित कमलापति त्रिपाठी के पड़पोते की तरफ झुक सकता है।

घोसी सीट पर भी राजभर नेताओं के बड़बोलेपन के चलते मतदाताओं में गुस्सा है। पिछली बार हार का सामना करने वाली भाजपा ने इस सीट को सुभासपा को दे दिया था, लेकिन स्थिति अब भी नहीं बदली है। सपा उम्मीदवार राजीव राय बढ़त पर हैं। स्थानीय एवं बाहरी का मुद्दा भी इस सीट पर हावी है। चंदौली सीट पर भी केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय को लेकर जनता में नाराजगी रही है, जिसका लाभ सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह को मिलता दिख रहा है। हालांकि सपा की आतंरिक लड़ाई का लाभ डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय को मिलता है, तो लड़ाई नजदीकी है। बस्ती सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी को लेकर जनता में नाराजगी है। माना जा रहा था कि भाजपा यहां से प्रत्याशी बदल देगी, लेकिन बिहार-झारखंड के संगठन मंत्री नागेंद्रनाथ त्रिपाठी की कृपा से हरीश तीसरी बार टिकट पा गए। बसपा यहां से दयाशंकर मिश्र को प्रत्याशी बनाकर भाजपा के वोट में सेंधमारी कर रही थी। अचानक मायावती ने इस सीट पर भी प्रत्याशी बदलकर कुर्मी समाज के लवकुश पटेल को उम्मीदवार बना दिया। लवकुश सपा के कुर्मी उम्मीदवार राम प्रसाद चौधरी के वोटों में सेंधमारी करेंगे। सपा ने दयाशंकर मिश्र को पार्टी में शामिल कर ब्राह्मण वोटों को पाले में लाने की कोशिश की है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

मध्यम वर्ग चुनाव से अलग

दरअसल, उप्र में अब केवल मोदी के नाम पर जनता किसी को भी चुनकर भेजने को तैयार नहीं है। उसका भले ही कुछ हद तक मोदी से मोहभंग हुआ हो लेकिन वह विपक्षी गठबंधन को लाने के लिए तैयार भी नहीं है। इसलिए खासकर मध्यम वर्ग ने खुद को चुनाव से अलग कर लिया है। इसी का परिणाम है कि मतदान प्रतिशत आंशिक रूप से कम हो रहा है। बीते दो आम चुनावों में मतदाताओं ने मोदी के नाम पर कमजोर-मजबूत सभी प्रत्याशियों को जीत दिला दी, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। भाजपा ने मोदी लहर के नाम पर फिर से उन्हीं प्रत्याशियों को जनता पर थोप दिया, जिनको लेकर जनता में भारी नाराजगी थी। हालांकि विपक्ष इस नाराजगी को भुना नहीं पाया है, लेकिन फिर भी भाजपा को पूर्वांचल की कई सीटों पर केवल प्रत्याशियों के चयन के चलते नुकसान उठाना पड़ेगा।

तेजस्वी के तेज की परीक्षा...

बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को जिताने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर है। कहने को तो राजद कांग्रेस, वाम दलों और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन महागठबंधन का सारा दारोमदार इस बार करीब-करीब उन पर ही है। जाहिर है, चुनावों के आने वाले चरणों के प्रचार के लिए तेजस्वी न तो प्रचंड गर्मी के कारण रुकना चाहते हैं, न किसी अन्य कारण से। तेजस्वी का कहना है कि उनका दर्द बिहार के करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ नहीं है, जो नौकरी की आस में बैठे हैं और जिनके सपनों को विगत 10 वर्षों में धर्म की आड़ में कुचला जा रहा है। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आराम के अभाव और निरंतर यात्रा के कारण दो हफ्ते से उनकी कमर में दर्द था, जो अचानक बढ़ गया।

विपक्ष की अधिकतर पार्टियों और राजद के लिए भी यह चुनाव करो या मरो वाली स्थिति है। तेजस्वी को यह बखूबी पता है कि उन्हें न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा की लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता वापसी से रोकने के लिए अपना योगदान देना है बल्कि अपनी पार्टी की लोकसभा चुनावों में धमक के साथ वापसी करानी है। पिछले आम चुनाव में राजद का एक भी उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ था। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के वजूद में आने के बाद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 2019 में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर एनडीए को जीत मिली थी। विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस को प्रदेश में एक सीट मिली थी। इसलिए इस चुनाव में तेजस्वी के दो लक्ष्य हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए वे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।

हालांकि पिछले चुनाव में शून्य पर आउट हो जाने के बाद तेजस्वी की पार्टी का ग्राफ बिहार में और नीचे नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद महज कुछ सीटों को जीतने की नहीं है। उनका इरादा प्रदेश में कम से कम 2004 के लोकसभा चुनाव के परिणाम दोहराने या उससे बेहतर करने की है, जब उनके पिता लालू प्रसाद के नेतृत्व में राजद को 22 और उनके गठबंधन को कुल 29 सीटों पर जीत मिली थी। जाहिर है, बिहार जैसे बड़े राज्य में अगर राजद और उसकी सहयोगी पार्टियां इस चुनाव में सम्मानजनक प्रदर्शन करती हैं तो भाजपा की हैट्रिक राह में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन क्या यह संभव है?

राजद की छवि बदलने में जुटे तेजस्वी

तेजस्वी पिछले कुछ चुनावों से राजद की छवि बदलने के प्रयास में जुटे हैं। इस बार उम्मीदवारों के चयन में उन्होंने चर्चित पूर्व मुखिया रितु जायसवाल (शिवहर) और पटना के कॉमर्स कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक कुमार चंद्रदीप (मधेपुरा) जैसे युवा और स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है, लेकिन यह सभी उम्मीदवारों के बारे में नहीं कहा जा सकता। पार्टी ने मुन्ना शुक्ला (वैशाली) और सजायाफ्ता अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी (मुंगेर) को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने पूर्णिया से बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया, जहां कांग्रेस के पप्पू यादव बेहतर उम्मीदवार हो सकते थे। तेजस्वी बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, जबकि मोदी और नीतीश उन्हें भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरभंगा की एक रैली में नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर गोधरा कांड के अभियुक्तों को बचाने का आरोप लगाया। नीतीश स्वयं अपनी चुनावी सभाओं में अभी भी 1990 और 2005 के बीच राजद के शासन के दौरान कथित जंगलराज का जिक्र करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वे युवाओं को उस कालखंड के बारे में बताएं, जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है। जाहिर है, तेजस्वी यादव की चुनौती को एनडीए हल्के में नहीं ले रही है, भले ही एनडीए नेता प्रदेश की सभी 40 सीटों को आसानी से जीतने का दावा कर रहे हैं।

यह तो साफ हो रहा है कि इस बार बिहार का मतदाता अपने पत्ते जल्दी खोलने के मूड में नहीं है। अभी तक के वोट प्रतिशत आंकड़ों से यह, तो स्पष्ट है कि वह चुनाव के प्रति उदासीन भी है, लेकिन अंतिम समय में वह किसका पलड़ा भारी करेगा, यह कहना आसान नहीं है। वोट प्रतिशत की एनडीए और महागठबंधन अपने-अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि महागठबंधन के समर्थक इतने निराश हो चुके हैं कि वे वोट देने बूथ पर जा ही नहीं रहे हैं। राजद इसे मोदी सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी बता रही है, जिसके कारण वे चुपचाप एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। राजद ने एक स्लोगन भी दिया है, चुपचाप, लालटेन छाप।

इस चुनाव में साइलेंट वोटर किसके पक्ष में है, यह तो चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा। यह भी पता चलेगा कि प्रदेश में घटता वोट प्रतिशत केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मतदाताओं की उदासीनता दर्शाता है या मोदी को चुनौती देने वाली विपक्ष के प्रति घोर निराशा। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिकतर संसदीय क्षेत्रों में एनडीए के उम्मीदवारों के प्रति लोगों का रोष दिखता है। अधिकतर सांसदों के खिलाफ आरोप है कि पिछले 5 वर्षों में वे उनकी सुध लेने नहीं आए। राजनीतिक विश्लेषक इसका एक ही कारण बताते हैं। उनके अनुसार, सत्तारूढ़ गठबंधन के अधिकतर सांसद मोदी के नाम पर पिछली बार चुनकर आए थे और इस बार भी इसी उम्मीद में हैं। अश्विनी चौबे और रमा देवी जैसे अपवाद छोड़ दिए जाएं, तो भाजपा ने बिहार में इस बार अधिकतर सांसदों को एक और मौका दिया है, जिनका प्रदर्शन उल्लेखनीय नहीं रहा है। उनके पास अपनी उपलब्धियों को गिनाने के नाम पर कश्मीर में अनुच्छेद-370 का निरस्त होना और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण है। स्थानीय स्तर पर जनहित मामलों के नाम पर उनके अपने खाते में कुछ खास नहीं है। लेकिन क्या स्थानीय सांसदों के प्रति नाराजगी एनडीए, खासकर भाजपा के लिए भारी पड़ेगी? यह भी फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले आम चुनाव के परिणामों को फिर हासिल करना उसके लिए आसान नहीं होगा। मधुबनी संसदीय क्षेत्र के सूरतगंज के मानस कुमार का कहना है कि भाजपा के निवर्त्तमान सांसद अशोक कुमार यादव के प्रति लोगों में नाराजगी है, फिर भी उन्हें मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। यही स्थिति कमोबेश हर क्षेत्र में है।

● **विनोद बक्सरी**

रईसी की मौत पर मातम और राहत

राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर ईरानी मातम मना रहे हैं तो दूसरी ओर वो लोग भी हैं जो रईसी की मौत पर राहत की सांस ले रहे हैं। ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथ को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले रईसी की मौत से एक ओर जहां ईरान को लेकर विश्व राजनीति पर असर पड़ेगा वहीं घरेलू स्तर पर भी ईरान में उथल-पुथल बढ़ेगी। ऐसे समय जब रईसी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हो रहे थे, उनका ना होना, ईरान में एक बड़ी उथल-पुथल का कारण बन सकता है। ईरान पहले से ही अमेरिका और अन्य देशों द्वारा जारी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और अंदर से भी कई झंझावातों को झेल रहा है। ऐसे में रईसी का न रहना एक संभावित संकट की ओर भी इशारा कर रहा है।

इस्लामिक तालिमात में महारत रखने वाले 63 वर्षीय रईसी 2021 में ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। हालांकि ईरानी जनता के एक बड़े वर्ग ने उनका बहिष्कार किया था क्योंकि इस इस्लामिक गणराज्य के इतिहास में तब सबसे कम वोट (लगभग 45 प्रतिशत) पड़े थे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई का उनको समर्थन प्राप्त हुआ और वे राष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित हो गए। राष्ट्रपति बनकर रईसी एक तरफ अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़े और साथ ही पश्चिम के साथ टकराव की नीति भी कायम रखी तो दूसरी ओर ईरान में कमजोर पड़ रही इस्लामिक क्रांति को दोबारा से स्थापित करने का प्रयास किया। अभी एक महीने पहले ही रईसी ने इजराइल पर एक बड़ा हमला करवाया और अमेरिका को भी खुली चुनौती दे डाली थी।

ईरान में रईसी को रूढ़िवादी नेता माना जाता था। उन पर अपनी सरकार में प्रमुख पदों पर अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति का भी आरोप लगता रहा, जबकि ईरान की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट का सामना कर रही है। इसके अलावा आसमान छूती कीमतों को लेकर भी ईरान में काफी असंतोष बढ़ने लगा है। सुधारवादी आलोचक बार-बार यह कहते रहे कि रईसी के पास किसी भी समस्या का हल नहीं है। हालात इस खतरनाक स्थिति में पहुंचने लगे थे कि 2019 जैसा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन होने की आशंका बढ़ने लगी है। लेकिन खुमैनी की तरह रईसी भी ईरान पर इस्लामी आदर्शों और प्रथाओं को थोपने पर ही जोर देते रहे। ईरानी विरासत और संस्कृति की रक्षा के नाम पर ईरान में मजहबी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा। यहां तक कि पारंपरिक लोक संगीत और नृत्य पर भी पाबंदी लगा दी गई। सैय्यद इब्राहिम रईसी को अपने पड़ोसियों पर प्रभुत्व जमाने, व्यक्तिगत अधिकारों का दमन करने और युद्ध पर आमादा रहने के लिए भी जाना जाता है।

बदलाव की ओर बढ़ रहे थे रईसी

रईसी ने हाल के दिनों में अपनी कूटनीतिक गतिविधियां तेज कर दी थीं। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए शायद टकराव का रास्ता छोड़ना जरूरी लगने लगा था। रईसी चीन, सीरिया और वेनेजुएला की मध्यस्थता में सऊदी अरब से अपने रिश्ते सुधारने में लगे थे। उन्होंने अरब के राजनयिकों की मेजबानी भी की। अपने विरोधी अमेरिका के साथ भी अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए ओमान की सहायता ली। वह अपने परमाणु कार्यक्रम को कम करने और अमेरिकी कैदियों की रिहाई के माध्यम से तनाव कम करने लिए किसी गुप्त समझौते पर भी काम कर रहे थे। शायद उनको उम्मीद थी कि इस तरह के प्रयासों से ईरान में अनियंत्रित मुद्रास्फीति शांत हो जाएगी और डॉलर के मुकाबले रियाल का मूल्यह्रास भी रुक जाएगा और अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो जाएगी। रईसी ने खुद को नई विश्व व्यवस्था में ढालने की कोशिश भी की। उन्होंने चीन, इंडोनेशिया, वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा का दौरा किया। जब मौका मिला साम्राज्यवादी शक्तियों की निंदा भी की। उनके नेतृत्व में ईरान को यह उम्मीद थी कि एक दिन पश्चिमी देशों को भी वे यह मानने के लिए मजबूर कर देंगे कि मध्य एशिया में उनको छोड़कर नहीं चल सकते। वो जिंदा रहते तो इस विरोधाभास को कैसे साधते यह तो पता नहीं लेकिन उनके न रहने से ईरान के भीतर और बाहर उनके समर्थक उदास, तो विरोधी खुश दिखाई दे रहे हैं।

1970 के दशक में, ईरान भी अन्य यूरोपीय और पश्चिमी समाजों की तरह खुले विचारों का देश था। महिलाएं कार चलाती थीं, स्कूल-कालेज जाती थीं, नौकरियां करती थीं और अपनी इच्छा के अनुसार सड़कों पर चलती थीं, लेकिन जब 70 के दशक के अंत में धार्मिक नेताओं का ईरान पर नियंत्रण हुआ तो सारी सामाजिक प्रगति रुक गई। राष्ट्रपति बनने के बाद रईसी ने समाज को दकियानूसी से निकालने के बजाय लोगों को उल्लंघन के लिए दंड देना शुरू कर दिया। उन्होंने घरेलू विरोध प्रदर्शनों पर कठोर कार्रवाई की। अपने चुनाव के एक साल बाद ही उन्होंने महिलाओं की पोशाक और व्यवहार को प्रतिबंधित करने के लिए ईरान में हिजाब कानून को सख्ती से लागू कर दिया और जब ईरान के युवा वर्ग ने विरोध किया तो उसे कुचल दिया। उसी दौरान एक युवा कुर्द ईरानी लड़की महसा अमिनी को पुलिस हिरासत में मार दिया गया। दर्जनों अन्य लोग भी मारे गए।

राष्ट्रपति बनने के बाद रईसी ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों और प्रथाओं का भी खूब उल्लंघन किया। उनके अड़ियल रुख के कारण ही ईरान की परमाणु वार्ता विफल हुई, क्योंकि ईरान लगातार अपनी भूमिगत परमाणु सुविधाओं की स्थापना और विस्तार करता रहा। वह यूरेनियम के भंडार को भी आवश्यकता से कहीं अधिक समृद्ध करने पर जोर देता रहा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षकों को भी ईरान आने की अनुमति नहीं दी। रईसी धीरे-धीरे परमाणु हथियार क्षमता विकसित करने और उसका इस्तेमाल अपने कथित दुश्मन मुल्कों पर करने की नीति पर चलते रहे। ईरान ने यमन, सीरिया और लेबनान में भी हथियारों की खेप भेजने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूक्रेन में बड़े पैमाने पर नागरिक हताहतों के साथ-साथ सीरिया में अमेरिकी सेना के खिलाफ छिटपुट हमलों में भी ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के प्रयोग देखे गए। रईसी ने पश्चिम के प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए चीन और रूस की सहायता ली।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

ब्रिटेन का संक्रमित रक्त घोटाला

50 साल बाद रिपोर्ट में आया भयावह सच

6 साल तक चली जांच में सरकार, एनएचएस, दवा कंपनियों और राष्ट्रीय रक्त सेवाओं के साक्ष्यों की समीक्षा की गई। इसमें प्रभावित लोगों और परिवारों के 4,000 से अधिक मौखिक और लिखित बयानों को भी ध्यान में रखा गया। जांच में पता चलता है कि मरीज की सुरक्षा की अनदेखी की गई, निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी और लंबी थी, लोगों की स्वायत्तता और निजता की उपेक्षा की गई, सरकारें और एनएचएस अधिकारी रक्षात्मक रुख अपनाए हुए थे, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी से उन लोगों के साथ अन्याय और बढ़ गया जिनका जीवन संक्रमण से नष्ट हो गया था। अमेरिकी आयात के लिए लाइसेंस 1973 और उसके बाद के दशकों में दिए गए थे, इस सबूत के बावजूद कि व्यावसायिक रूप से निर्मित रक्त उत्पाद एनएचएस कॉन्संट्रेट या क्रायोप्रेसीपिटेट की तुलना में कम सुरक्षित थे। रोगी की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसके अलावा रिपोर्ट में पाया कि व्यक्तिगत रोगी की स्वायत्तता के लिए सम्मान की अत्यधिक अनैतिक कमी थी। चिकित्सक, लोगों को संक्रमण के खतरों, वैकल्पिक उपचारों की उपलब्धता या एचआईवी या हेपेटाइटिस सी के लिए परीक्षण किए जाने के बारे में बताने में विफल रहे।

50 साल बाद एक जांच रिपोर्ट ने ब्रिटेन की कुख्यात चिकित्सा त्रासदी पर प्रकाश डाला है। ब्रिटेन में 1970 और 1990 के दशक के बीच, अमेरिका से आयातित दूषित रक्त और रक्त उत्पाद प्राप्त करने के बाद 30,000 से अधिक लोग एचआईवी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गए थे। इस रिपोर्ट ने ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) के इतिहास में सबसे खराब उपचार आपदा बना दिया है। जांचकर्ताओं की टीम के अध्यक्ष ब्रायन लैंगस्टाफ ने इस रिपोर्ट की घोषणा करते हुए कहा कि यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी। सत्ता में बैठे लोगों, डॉक्टरों, रक्त सेवाओं और सरकारों ने स्वास्थ्य देखभाल और उपचार के मामलों में भारी मूर्खता की। यही नहीं उन्होंने रोगी की सुरक्षा को प्राथमिकता पर नहीं रखा।

छह साल की लंबी जांच के बाद यह रिपोर्ट जारी की गई है। यह एक सुनियोजित साजिश की तुलना में एक ऐसी स्थिति को उजागर करती है जो अपने निहितार्थों में अधिक सूक्ष्म, अधिक व्यापक और अधिक भयावह थी। यह घटना अपनी इज्जत बचाने और खर्च बचाने के लिए की गई थी। आपदा को सरकार की रक्षात्मकता नीति के कारण और दशकों से इसकी सार्वजनिक जांच कराने से इनकार के कारण और अधिक विनाशकारी बना दिया गया था।

रिपोर्ट सरकारी विफलताओं की सूची में पहली बार, जीवित बचे लोगों और मरने वालों के परिवारों के विनाशकारी हृदयविदारक और दुख की पुष्टि करती है। ब्रायन लैंगस्टाफ कहते हैं कि इतनी सारी मौतें और संक्रमण क्यों हुए, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं था। यह सार्वजनिक जांच यूके में की जाने वाली अपनी तरह की सबसे बड़ी जांच थी। यह 2017 में उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए शुरू की गई थी जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा इलाज किए गए 1970 से पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को संक्रमित रक्त और संक्रमित रक्त उत्पाद दिए गए थे। पिछले दशकों में संक्रमित रक्त प्राप्त करने के कारण कम से कम 3,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। हीमोफीलिया सोसायटी का अनुमान है कि जांच शुरू होने के बाद से 680 अन्य लोगों की मौत हो चुकी है। एक अनुमान के अनुसार यूके में अभी भी हर चार दिन में एक संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूषित रक्त से जुड़ी मौतें और संक्रमण ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, जापान, पुर्तगाल और अमेरिका में भी दर्ज किए गए। पहले प्रकाशित एक अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्त घोटाले ने व्यक्तिगत, सामूहिक और प्रणालीगत स्तर पर की गई विफलताओं को उजागर किया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1974 और 1975 में हेपेटाइटिस की उच्च दर वाले देशों से रक्त उत्पादों के आयात के खिलाफ चेतावनी दी थी, जैसे कि 1983 में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा के यूएस स्पेंस गैलब्रेथ ने स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र भेजा था, जिसमें आग्रह किया गया था कि सभी रक्त 1978 के बाद यूएस में दान किए गए रक्त से बने उत्पादों को तब तक उपयोग से हटा दिया जाना चाहिए जब तक कि इन उत्पादों द्वारा एड्स संचरण के जोखिम को स्पष्ट नहीं किया जाता है। जांच से पता चला कि अमेरिका से आयातित दूषित रक्त प्लाज्मा उत्पादों का उपयोग हीमोफिलिया से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए किया गया था। जनवरी 1982 में प्रमुख विशेषज्ञ आर्थर ब्लूम ने हीमोफीलियाक केंद्रों को एक चेतावनी भरा पत्र लिखा, जिसमें सुझाव दिया गया कि नए उपचारों की संक्रामकता का परीक्षण करने का सबसे स्पष्ट तरीका उन रोगियों पर था जो पहले बड़े-पूल सांद्रता के संपर्क में नहीं आए थे। जिनमें बच्चे भी शामिल थे। लैंगस्टाफ हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों के लिए एक विशेषज्ञ स्कूल, हैम्पशायर के ट्रेओलर कॉलेज में होने वाले कार्यक्रमों का विवरण देते हैं। बच्चों को अनुसंधान की वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया गया और सुरक्षित उपचार चुनने के बजाय अनावश्यक रूप से सांद्रण के साथ इलाज किया गया।

एक जांच में पाया गया कि 1974 और 1987 के बीच ट्रेलोर में भाग लेने वाले 122 विद्यार्थियों में से 75 की एचआईवी और हेपेटाइटिस सी संक्रमण से मृत्यु हो गई। जांच में यह भी पाया गया कि ब्लूम जोखिमों से अवगत थे और उन्होंने आंतरिक एनएचएस दिशा-निर्देशों को खारिज कर दिया था जो बच्चों पर फैक्टर VIII उपचार के परीक्षण को हतोत्साहित करते थे। क्लिनिकल परीक्षण इस सबूत के बावजूद जारी रहे कि फैक्टर VIII रक्त सांद्रण प्राप्त करने वाले लोगों को एचआईवी संक्रमण का खतरा था। उनमें से अधिकांश की बाद में एड्स-संबंधी बीमारी से मृत्यु हो गई। 1970 के दशक की शुरुआत में रोगियों का इलाज करने वाले हीमोफिलिया विशेषज्ञ एडवर्ड टुडेनहैम ने स्काई न्यूज को बताया, निश्चित रूप से, हमें पता चलता है कि इसके कारण बहुत से लोग संक्रमित हुए और परिणामस्वरूप बहुत से लोग मर गए।

● **कुमार विनोद**

परिवार से है हमारी खुशी

हर परिवार में अनबन, मतभेद, छिटपुट लड़ाई-झगड़े होते हैं। मगर इन बातों को जितनी जल्दी भूलकर एकजुट हो जाया जाए उतना अच्छा। क्योंकि परिवार में आपसी सहयोग और समर्थन की जैसी निस्वार्थ भावना मिल सकती है, वैसी कहीं और नहीं मिल सकती। परिवार के सदस्य सहानुभूति से हमारी चिंताओं को खत्म कर सकते हैं। अकेलेपन, अवसाद को दूर करने के लिए परिवार अचूक दवा है जिससे हम बेहिचक अपने डर को साझा कर भयमुक्त हो सकते हैं।

आज परिवार का मतलब पति, पत्नी और बच्चों तक सिमट चुका है। पर परिवार की अहमियत को देखते हुए इसे किसी भी रूप में बचाने और मजबूत करने की आवश्यकता है। कोरोना के समय में पूरी दुनिया ने परिवार की अहमियत को समझा। यही कारण है कि अब पूरी दुनिया में परिवार नाम की संस्था को मजबूत बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। पश्चिमी देशों ने इसे केयर इकोनॉमी का नाम दिया है। हालांकि मां की ममता, पिता के संरक्षण, परिवार के साथ को इकोनॉमी का नाम देना भावनात्मक रूप से स्वीकार्य नहीं। पर फिर भी परिवार संस्था को बचाने के लिए जो भी प्रयास हो उसकी सराहना की जानी चाहिए। आइए हम भी अपने परिवार के साथ अपने होने के अर्थ को तलाशें। हमारे देश में परिवार नाम की संस्था बहुत मजबूत है फिर भी संयुक्त परिवारों के विखंडन के साथ इसकी नींव में दरारें तो पड़ ही चुकी हैं। इसलिए हमारे देश में भी परिवार की अवधारणा को सींचने व पोषित करने की जरूरत आन पड़ी है। परिवार के महत्व और उसकी अहमियत को बताने के उद्देश्य से हर वर्ष 15 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है।

जन्म के समय बच्चा पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है। इसलिए बच्चे को जन्म लेते ही सबसे पहले परिवार की जरूरत होती है। परिवार ही एक मां को नवजात को संभालने-सहेजने के तरीके बताता है। अपने अनुभवों की सीख दे बच्चे के लालन-पालन में मदद करता है। एक बच्चे का समाज उसके परिवार से ही शुरू होता है। परिवार उसे जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है। संस्कारों, आदर्शों, नैतिकता, मानवीयता जैसे गुणों की सीख देकर उसे समाज में रहने के योग्य बनाता है। बच्चे के कोरे मन मस्तिष्क में सामाजिक सरोकारों, दायित्वों व कर्तव्यों की पहली शिक्षा परिवार ही देता है। परिवार के बिना बच्चे का विकास अनगढ़ और बेढंगा हो जाएगा। हम जन्म लेते ही किसी न किसी रिश्ते से बंध जाते हैं। हालांकि हमारा सबसे पहला रिश्ता गर्भ में मां से बनता है पर बाहर निकलते ही हम अनेक रिश्तों की डोर से बंध जाते हैं। परिवार के ये रिश्ते ही एक नन्हे से शिशु को इतना दुलार देते हैं कि वह बचपन में स्वयं को शहंशाह समझता है। बच्चे परिवार के हर सदस्य के सामने अधिकार की भावना प्रकट करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है परिवार में सब उसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हमें भावनात्मक सम्बल, आर्थिक सुरक्षा और मानसिक परिपक्वता परिवार के सानिध्य में ही मिलती है। बड़े होने के बाद भी प्यार-दुलार की स्मृतियां खत्म नहीं हो पातीं।

परिवार का सही मतलब प्रेम, विश्वास, भरोसा, जिम्मेदारी, अपनत्व होता है। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है जब हम बहुत खुश होते हैं या बड़ी कामयाबी पाते हैं। तब सबसे पहले हम अपनी खुशी अपने परिवार को बताना चाहते हैं। वहीं कभी बहुत दुखी और उदास हों तब भी हमें परिवार की याद आती है। हम उनसे अपना दुख शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि परिवार ही हमारे सुख-दुख का सच्चा साथी है। हमारे भाई-बहन, माता-पिता परिवार के लोग ही हमारे सच्चे समर्थक होते हैं। दुख-सुख के भागीदार। मुसीबत में सबसे पहले वही हमारे पास आते हैं। हमारे अकेलेपन, निराशा, हताशा के पलों में परिवार हमारे साथ खड़ा रहता है। हमें टूटकर बिखरने नहीं देता। और खुशी के पलों में हमारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है। जन्म के साथ मिले संबंध-नाते जीवन में घनी छाया की भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले माता-पिता, फिर बहन-भाई, दादा-दादी, चाचा-ताऊ, मामा-मासी, बुआ और फिर चचेरे-ममेरे पारिवारिक रिश्ते। इस तरह रिश्तों का व्यापक ताना-बाना है जो एक परिवार में जन्म के साथ ही व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन इन सबमें नजदीकी रिश्ता है माता-पिता का। आधुनिक संदर्भों में तो एकल परिवार में माता-पिता ही प्रमुख अभिभावक व पालनहार होते हैं। लेकिन प्रकृति ने सबसे नजदीकी रिश्ता मां का ही बनाया है। दरअसल, जो कभी भी नहीं बदलती, वो मां ही होती है। उसकी शख्सियत बहुत ही विराट है। यह भी सही है कि एक पिता बच्चे के पालन-पोषण व संरक्षण के मोर्चे पर ताउम्र एक मूक योद्धा की भूमिका निभाता है। वहीं जरूरत-मुसीबत में भाई-बहन से मिलने वाले सहारे-संबल का जवाब ही नहीं। दरअसल सिबलिंग घर में मौजूद निकटस्थ मित्र होते हैं। जो बात बड़ों को कहते हुए हमें अक्सर भय-संकोच रहता है वह उनसे झट से शेयर कर सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे अच्छी दोस्त, सबसे अच्छी बहन, सबसे अच्छा भाई, सबसे अच्छी टीचर और कभी-कभी तो सबसे अच्छे पापा, दादा, दादी ये सभी हमारी मां में ही रचे-बसे हैं।

● **ज्योत्सना**

हर किरदार निभाती है मां

मां जीवन के हर किरदार को निभाती है। मां बच्चे के लिए मजबूत विश्वास है। एक मां जिसकी कोई उपमा न हो, जिसके प्रेम को कभी पतझड़ ने स्पर्श न किया हो। जिसने हमें जन्म दिया, इस सुंदर धरती पर लेकर आई, जो बेमिसाल है। तुलना कैसे और किससे कर सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं को अनदेखा कर बच्चों के शौक पूरा करती है मां। उनके सुख-दुख, प्रगति और पतन से, मां ही जुड़ी होती है। सचमुच उसका होना ही सुकून का अहसास है क्योंकि बड़ी से बड़ी परेशानी से लेकर अचार डालने के तरीके तक सारे हल मां के पास हैं। जब सृष्टि बनी तो संसार में जीवन का आधार मां बनी जो आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। धर्म गुरु श्रीश्री रविशंकर कहते हैं- ईश्वर की तुलना मां से की गई है। उन्हें मीनाक्षी कहा गया है-जिसका अर्थ है कि ईश्वर जिसके पास मीन यानी मछली की आंखें हैं। मछली ही एकमात्र ऐसा जीव है, जो अपनी आंखें कभी भी बंद नहीं करती। वह अपने बच्चों पर नजर रखते हुए सदा उनके पीछे चलती रहती है। इसीलिए ईश्वर को मीनाक्षी-मां कहा गया है। बच्चे जहां कहीं भी, किसी भी रास्ते पर गए हों, मां की नजर से बाहर नहीं होते। उसका प्रेम हमेशा उनके साथ चलता रहता है।

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

मुखिया

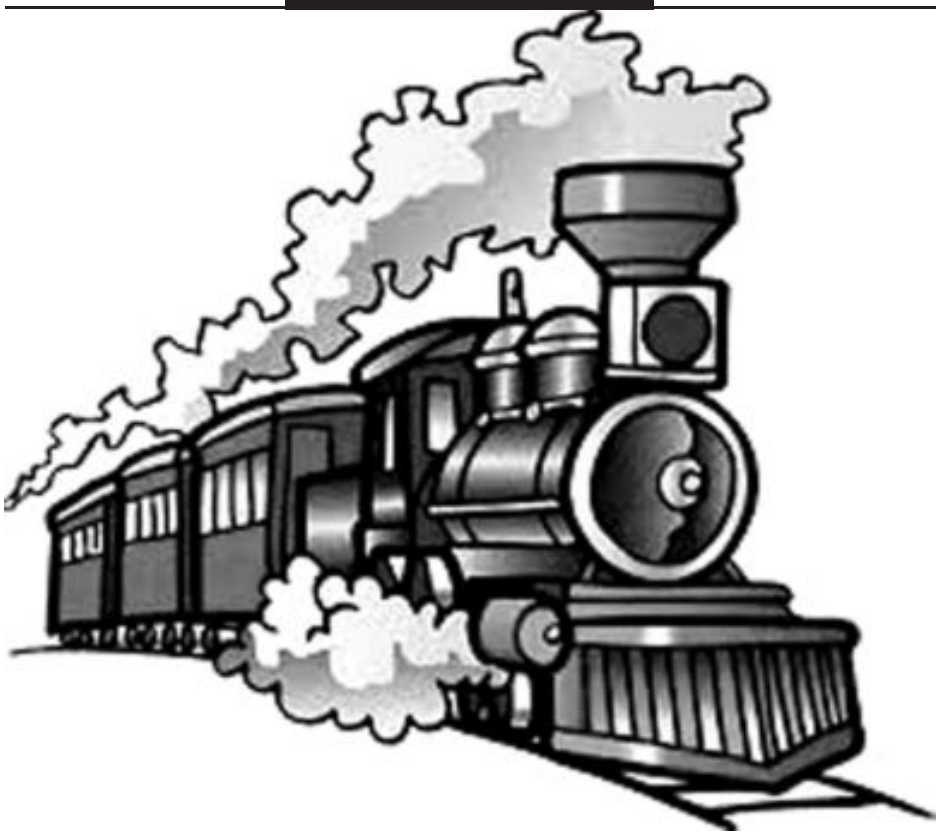

सत्संग में प्रवचन चल रहा था। बात मुखिया की चल रही थी।

जब हिंदुस्तान में नई-नई रेलगाड़ी चली तो एक डेरे के बाबा जी प्रतिदिन रेलगाड़ी देखने जाते थे। एक दिन डेरे के सेवादारों ने पूछ ही लिया कि आप रोज रेलगाड़ी देखने क्यों जाते हैं?

मुझे रेलगाड़ी के इंजन से प्यार हो गया है। बाबा जी ने जवाब दिया। सेवादारों ने कारण पूछा।

बाबा जी बोले, इसकी कुछ खास वजहें हैं। एक तो रेलगाड़ी का इंजन अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकता है, दूसरे अपने हर डिब्बे को साथ लेकर चलता है। फिर इंजन आग खुद खाता है और डिब्बों को खाने नहीं देता है। यह अपने तय रास्ते से भटकता नहीं है।

पांचवीं और आखिरी वजह यह है कि इंजन डिब्बों का मोहताज नहीं है। तनिक रुककर बाबाजी बोले।

मुखिया को भी रेलगाड़ी के इंजन जैसा ही होना चाहिए। वहां बैठे परिवारों और संगठनों के मुखियाओं ने निष्कर्ष निकाला।

- लीला तिवानी

जन्मभूमि

योजना, कर्म, संतुष्टि के बिन,
टारगेट जब तनाव देते हैं,
कर्म न हम कर पाते हैं।
योजना, कर्म, संतुष्टि के बिन,
असमय ही मर जाते हैं।।
जीवन का है अर्थ समझना।
नहीं किसी को गलत समझना।
संदर्भ और प्रयोग समझकर,
जिज्ञासु! वाक्य का अर्थ समझना।
जीवन का ही लक्ष्य न समझे,
लक्ष्य का गाना गाते हैं।
योजना, कर्म, संतुष्टि के बिन,
असमय ही मर जाते हैं।।
कर्म तुम्हारे हाथ सही है।
यही सीख गीता में कही है।
यात्रा का आनंद उठाओ,
आगे भी तो वही मही है।
कर्म बीज है, धैर्य सिंचाई,
समय से फिर फल आते हैं।
योजना, कर्म, संतुष्टि के बिन,
असमय ही मर जाते हैं।।
राष्ट्रप्रेमी की नहीं है इच्छा।
कदम-कदम है मौज परीक्षा।
कर्म की खातिर कर्म करो बस,
अनुभव देता सच्ची दीक्षा।
फल नहीं, बस कर्म लक्ष्य है,
छात्रों को समझाते हैं।
योजना, कर्म, संतुष्टि के बिन,
असमय ही मर जाते हैं।।

- डॉ. संतोष गौड़ राष्ट्रप्रेमी

परिणाम

बच्चों की तरह इंतजार करते हैं चुनाव के नतीजों का। जिस प्रकार बच्चा पेपर देता है और उसके दिल मैं डर रहता है कहीं फेल न हो जाऊं, उसी प्रकार नेताजी सोचते हैं कि हार गया तो कुर्सी चली जाएगी। कुर्सी के जाते ही जो बची-खुची इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। सुरेश जी आपका जबाब नहीं... क्या उदाहरण देकर समझाते हैं।

राम जी ने कहा। अब तो मुझे भी इंतजार है। देखना है क्या होता है। कितने पार जाते हैं। कितने डूब जाते हैं।

हां राम जी मुझे भी इंतजार है। चलो अब घर चलते हैं। वरना हमें आज भी ठंडा खाना खाने मिलेगा। अगर देर हो गई तो।

- अभिषेक जैन

अतुलनीय रहा आईपीएल का सीजन

क्रिकेट की सबसे महंगी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 17वें सीजन 2024 का समापन हो गया है। इस सीजन एक ओर जहां सिनेमा जगत के किंग खान शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को खिताबी मुकाबले में आठ विकेट से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे कीर्तिमान बने जिन्हें तोड़ना काफी मुश्किल होगा। इनमें एक टी-20 मैच में सबसे ज्यादा छक्कों से लेकर सबसे बड़ा स्कोर, बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो या फिर सबसे ज्यादा बार 200 रनों से ज्यादा स्कोर जैसे कई बड़े कीर्तिमान शामिल हैं। एक तरह से कहा जाए तो आईपीएल का यह संस्करण अतुलनीय रहा है। खेल विश्लेषकों का कहना है कि इस सीजन बने कीर्तिमानों को तोड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन होना है और सारी टीमें लगभग बदल जाएंगी। सनराइजर्स हैदराबाद या कोलकाता नाइट राइडर्स के पास मौजूदा संयोजन वाले खिलाड़ी नहीं होंगे। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता।

आईपीएल 2024 के 30वें मैच में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हैदराबाद ने इतिहास रचते हुए तीन विकेट पर 287 रन बनाकर आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। इसके साथ ही हैदराबाद ने इसी आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाए गए अपने तीन विकेट पर 277 रनों के सर्वोच्च स्कोर को पीछे छोड़ दिया। इस सीजन से पहले आईपीएल का उच्चतम स्कोर पांच विकेट पर 263 रन था, जो बेंगलुरु ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में बनाया था। 2024 सीजन में इससे बड़े चार टोटल बन गए। इनमें से तीन सनराइजर्स हैदराबाद के नाम रहे। यही नहीं यह टी-20 क्रिकेट का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। टी-20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर तीन विकेट पर 314 रन है, जो नेपाल ने 2023 में मंगोलिया के खिलाफ बनाया था।

आईपीएल 2024 के 42वें मैच में पंजाब किंग्स ने इतिहास रचते हुए टी-20 क्रिकेट और लीग के इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल कर दिखाया। उसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 262 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे पंजाब ने दो विकेट गंवाकर 8 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। ऐसा कर पंजाब ने टी-20 क्रिकेट में सबसे बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने का एक साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरियन में 259 रन चेज किए थे। इससे पहले 2020 में राजस्थान ने पंजाब के खिलाफ ही शारजाह में 224 रन सफलतापूर्वक चेज किए थे। इसी सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चिन्नास्वामी में हुए मैच में दोनों पारियों को मिलाकर 549 रन बने थे, जो आईपीएल में किसी एक मैच में दोनों पारियों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन हैं। इस मैच में सनराइजर्स ने 20 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 287 रन बनाए थे। वहीं बेंगलुरु की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 262 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा शतक आईपीएल 2024 में 14 शतक लगे हैं जो कि पिछले किसी भी संस्करण से ज्यादा हैं। इससे पहले 2023 में 12 शतक लगे थे। वहीं साल 2022 में 8, साल 2016 में 7, साल 2008 में 6 शतक लगे थे। आईपीएल के इस सीजन से पहले तक 1 सिर्फ दो मौके ऐसे आए थे जब 250 से ज्यादा रनों का स्कोर बना था। लेकिन इस सीजन 2024 में 8 बार 250 या इससे ज्यादा का स्कोर बना। आईपीएल 2024 में रनों की बारिश देखने को मिली। इस सीजन 41 बार 200 या इससे ज्यादा के स्कोर बने, जो पिछले सभी संस्करणों से ज्यादा हैं। पिछले साल यानी आईपीएल 2023 में 74 मैचों की 147 पारियों में 37 बार 200 या इससे ज्यादा के स्कोर बने थे। हालांकि इस सीजन यह रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है। वहीं, 2022 में 74 मैचों की 148 पारियों में 18 बार 200 या इससे ज्यादा के स्कोर बने थे। 2023 में ही इम्पैक्ट प्लेयर का नियम आईपीएल में लागू हुआ था और उसके बाद से 200 से ज्यादा के स्कोर में गजब की बढ़ोतरी हुई है। जहां 2022 में 200 से ज्यादा का स्कोर बनने की दर 12.16 प्रतिशत थी, वहीं 2023 में यह बढ़कर 25.17 फीसदी हो गई थी जो इस सीजन बढ़कर 27.70 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

आईपीएल 2024 के 42वें मैच में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले में पंजाब की ओर से 24 तो कोलकाता की ओर से 18 छक्के लगे। दोनों पारियों को मिलाकर कुल 42 छक्के लगे थे जो किसी एक टी-20 मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है। इस मामले में दूसरे नंबर पर भी आईपीएल के मुकाबले ही हैं। इसी सीजन सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच हैदराबाद में खेले गए मैच में 38 छक्के लगे थे। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच इसी सीजन चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भी 38 छक्के लगे थे। पंजाब और कोलकाता के बीच में पंजाब किंग्स टीम की ओर से 24 छक्के लगे, जो आईपीएल मैच की किसी एक पारी में किसी टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। इससे पहले इसी सीजन चिन्नास्वामी में सनराइजर्स ने बेंगलुरु के खिलाफ 22 छक्के जड़े थे। वहीं, टी20 क्रिकेट में किसी एक पारी में लगे यह दूसरे सबसे ज्यादा छक्के हैं। पंजाब से आगे केवल नेपाल की टीम है। उसने 2023 में एशियाई खेलों के दौरान मंगोलिया के खिलाफ 26 छक्के जड़े थे। आईपीएल 2024 में कुल 1260 छक्के लगे, जो कि पिछले किसी भी सीजन से ज्यादा हैं। इससे पहले सिर्फ 2023 और 2022 में ही हजार से ज्यादा छक्के लगे थे। 2022 में 1062 छक्के और 2023 में 1124 छक्के लगे थे।

● आशीष नेमा

पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर

पावरप्ले यानी पारी के पहले 6 ओवर बल्लेबाज को जोखिम उठाने और आउट होने की चिंता किए बिना बड़े शॉट लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। गेंदबाजों को भी पावरप्ले से लाभ मिल सकता है, क्योंकि कई बार बल्लेबाज बहुत लापरवाह हो जाते हैं। पावरप्ले के ओवरों में ज्यादा रन बनाने वाली ज्यादातर टीमें मैच जीत जाती हैं। आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले 6 ओवर में 125 रन बनाकर केकेआर द्वारा 2017 में बनाए गए 105 रनों के सर्वोच्च रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ शुरुआती 10 ओवर के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। एसआरएच ने लखनऊ के खिलाफ 9.4 ओवर में ही बिना विकेट गंवाए 167 रन बनाए थे। शुरुआती 10 ओवर में दूसरे सबसे ज्यादा रन भी हैदराबाद ने ही बनाए हैं। सनराइजर्स ने इसी सीजन दिल्ली के खिलाफ शुरुआती 10 ओवर में चार विकेट गंवाकर 158 रन बनाए थे। वहीं, सनराइजर्स की टीम ही तीसरे स्थान पर भी है। उन्होंने मुंबई के खिलाफ 10 ओवर में दो विकेट गंवाकर 148 रन बनाए थे।

फिल्म इंडस्ट्री के वो टैलेंटेड एक्टर जिनकी एक्टिंग को लोग थिएटर से बाहर निकलकर भी याद किया करते थे। साल 2005 में एक्टिंग की दुनिया में एंट्री करने के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। लेकिन साल 2007 में एक ऐसा रोल निभाया जिसके बाद वह खुद नशे की लत में डूब गए थे।

2007 की हिट फिल्म का हीरो, शराबी का किरदार निभाकर लूटी वाहवाही, लगी ऐसी लत... 1 साल तक नशे में डूबा रहा एक्टर

हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर अभय देओल की। अभय ने हिंदी फिल्मों के अलावा कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी काफी काम किया है। देओल परिवार में जन्मे अभय ने अपने करियर में कई ऐसे रोल निभाए हैं जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया था। वो बात अलग है कि वह आज एक्टिंग की दुनिया में उतने एक्टिव नहीं हैं।

अपनी हर फिल्म में अभय ने अपने किरदारों के साथ पूरी तरह न्याय किया है। अपने हर कैरेक्टर में वह ऐसे डूब जाते हैं कि लगता ही नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं। जिस तरह आमिर खान अपने हर रोल के लिए जी जान लगा देते हैं। उसी तरह अभय भी अपने रोल में जान फूंक देते हैं। एक बार तो अभय की जिंदगी पर एक किरदार ने ऐसा असर छोड़ा, जिससे निकलना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया था। ऐसा एक्टर के साथ हुआ साल 2007 में आई उनकी फिल्म देव डी के दौरान, जिसमें उनके अपोजिट माही गिल नजर आई थीं। अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी फिल्म देव डी को लोगों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म में अभय देओल के किरदार को मॉर्डन देवदास भी बताया गया था। इस फिल्म में अभय ने एक ऐसे शख्स की भूमिका निभाई थी जो अपनी ही लाइफ नशे की लत में डूबो कर खराब कर रहा था।

अब कहां हैं राज कपूर की हीरोइन, शोहरत मिलते ही 80 के दशक की एक्ट्रेस ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? सालों बाद बताया दर्द

साल 1985 में आई राम तेरी गंगा मैली से मंदाकिनी ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म को रिलीज हुए करीब 39 साल हो चुके हैं लेकिन मंदाकिनी की मासूमियत को आज भी कोई नहीं भुला पाया है। उनकी बोलती आंखें आज भी दर्शकों को काफी पसंद है। 80 के दशक में मंदाकिनी काफी फेमस एक्ट्रेस थीं। मंदाकिनी ने करीब 40 से अधिक फिल्में करने के बाद बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।

मंदाकिनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम और पेमेंट डिफरेंस का काफी सामना करना पड़ा था। उनकी सैलरी औरों से काफी कम थी। इतना ही नहीं उनकी टॉप एक्ट्रेस की सैलरी और टॉप हीरो की सैलरी में काफी अंतर था। मंदाकिनी ने भी कहा था कि उनकी लाइफ में कई बार ऐसे मौके आए जब उनके हाथ में आईं कई फिल्में इसलिए निकल गई क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर से अपनी फीस ज्यादा मांग ली थी। उन्होंने कहा था कि 1.5 लाख रुपए के फीस के कारण निर्माताओं ने उनकी जगह 75,000 रुपए फीस लेने वाली एक्ट्रेस को रख लिया था। उन्होंने कहा था चंद पैसे की कटौती भले ही कुछ फर्क नहीं पड़ता था लेकिन इसने उनके करियर को प्रभावित किया। कम फीस और अपने घटते हुए फेम को देख मंदाकिनी ने फिल्मों में काम नहीं करने का फैसला किया।

किस दुकान से तुमने खरीदा ये सूट? जब भरी महफिल में दिग्गज अभिनेता राजकुमार ने उड़ाया था अमिताभ बच्चन का मजाक!

राजकुमार बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता थे। राजकुमार हमेशा एक अलग तेवर में रहा करते थे। साथ ही, उनकी आवाज भी दूसरों से काफी अलग थी। एक बार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी उनकी चपेट में आ गए थे। एक बार राजकपूर ने एक पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें इंडस्ट्री के तमाम सितारे पहुंचे थे। इस पार्टी राजकुमार के साथ-साथ अमिताभ भी शामिल हुए।

पार्टी में अमिताभ सूट-बूट में पहुंचे थे और जो भी उनसे मिल रहा था, उनकी जमकर तारीफ कर रहा था। ये सब राजकुमार नोटिस कर रहे थे। तभी वो अमिताभ के पास गए और बोले- जानी, मुझे तुम्हारा सूट पसंद आया। यह सुनते ही अमिताभ गदगद हो गए। फिर राजकुमार ने अमिताभ से पूछा कि यह सूट तुमने किस दुकान से खरीदा है? अमिताभ ने भी तुरंत उस दुकान का नाम उन्हें बता दिया, फिर उन्होंने राजकुमार से पूछा कि क्या आपको भी इस तरह का सूट सिलवाना है? अमिताभ के इस सवाल पर राजकुमार ने जो जवाब दिया, वो हैरान करने वाला था।

राजकुमार ने अमिताभ से कहा, मुझे अपने घर के लिए कुछ पर्दे सिलवाने हैं और मुझे तुम्हारे सूट का कपड़ा पसंद आया। कहा जाता है कि ये बात सुनते ही अमिताभ बिना कुछ बोले वहां से चले गए। वैसे, राजकुमार से जुड़ी ऐसी कई कहानियां, जिसे जान आप हैरान रह जाएंगे।

कीचड़-उछाल युग

यह कीचड़-उछाल संस्कृति का युग है। यत्र-तत्र-सर्वत्र कीचड़-उछाल उत्सव का वातावरण है। कोई भी कीचड़ उछालने में पीछे नहीं रहना चाहता। इसलिए दूसरे पर कीचड़ उछालने में वह अपने अंतर की हर दुर्गंध, दूषण, कचरा, कपट, कुभाव, कुवृत्ति, कुविचार और कुभाषा को कषाइत करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। यह वह स्थान है, जहां हर मानव अपनी मानवता को तिलांजलि देता हुआ बिना किसी भेदभाव के एक ही आसन पर बैठा हुआ पाता है। वहां पद, प्रतिष्ठा, पाप-पुण्य आदि ठीक वैसे ही एकासन पाते हैं, जैसे श्मशान में किसी के अंतिम संस्कार में जाते समय अपने अहं को बिसार निर्वेद भाव पर निसार हो जाते हैं। हां, एक विपरीत स्थिति यह भी है कि यहां अहं नष्ट नहीं होता, अपितु अपने चरम पर होता है। यदि स्वयं का अहं ही नष्ट हो जाएगा तो पराई कीचड़ भी सुगंधित मिष्ठान्न बन जाएगी। फिर वह बाहर उछाली न जाकर हृदयंगम ही की जाएगी।

यह भी परम सत्य है कि कभी किसी भी मानव या महामानव अथवा महानारी ने अपने गले में झांककर नहीं देखा। यद्यपि वह देख सकता था। यदि देख पाता तो कीचड़-उछाल का आनंद नहीं ले पाता। अपने और अपनों को छोड़ सर्वत्र कीचड़ ही कीचड़ का दृष्टिगोचर होना उसे देवता नहीं बना देता, क्योंकि सभी देवतागण दूध के धोए नहीं हैं। अब चाहे वे देवराज इंद्र ही क्यों न हों। अपने को स्थापित करने के उद्देश्य से दूसरे की बुराई देखना और उसे सार्वजनिक करना ही कीचड़-उछाल कहा जाता है। लेकिन क्या इससे कोई कीचड़-उछालू गंगा जल जैसा पवित्र मान लिया जाता है?

यों तो कीचड़ उछालना मानव मात्र की चारित्रिक विशेषता है। किंतु साथ ही वह उसकी नकारात्मक वृत्ति ही है। वह उसकी महानता में निम्नता लाने वाली है। कीचड़ उछालने वाला अपने अहंकार में किसी को महत्वपूर्ण नहीं मानता। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता हुआ मानव-शिरोमणि होने का अवार्ड अपने नाम कर लेता है। मैं ही हूं सब कुछ, सर्वज्ञ, सर्वजेता, सर्वश्रेष्ठ। यह भाव उसके विवेक पर पूर्ण विराम लगाता हुआ उसकी चिंतना को प्रभावित करता है। यह उसके अध: पतन और विनाश का मूल है। वह नहीं चाहता कि कोई और आगे बढ़े। वह किसी भी व्यक्ति या संस्था में अच्छाई नहीं देखता। उसे सर्वत्र बदबू और प्रदूषण ही दृष्टिगोचर होता है। परिणाम यह होता है कि वह एकला चलो रे की स्थिति में आकर अकेला ही पड़ जाता है। जब तक उसे अपने स्वत्व और दोष का बोध होता है, तब तक गंगा में बहुत ज्यादा पानी बह चुका होता है। एक प्रकार से इसे अज्ञान का मोटा पर्दा ही पड़ा हुआ मानना चाहिए। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।

यद्यपि वर्तमान रजनीति में कीचड़-उछाल का विशेष महत्व है। किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ अबोध जन द्वारा वैसा ही मान लिया जाता है। कहना यह भी चाहिए कि कीचड़ राजनीति की खाद है, वह उसकी पोषक तत्व है। जो जितनी कीचड़ उछालने की दम रखता है, उस नेता का स्तर उतना ही बढ़ जाता है। बस कीचड़ उछालने का सामर्थ्य होना चाहिए। यह सामर्थ्य धन बल, पद बल और सत्ता बल से आता है। भूखा आदमी भला क्या खाकर कीचड़ इकट्ठा करेगा। कीचड़ को भी बटोरना, समेटना और सहेजना पड़ता है। कीचड़-उछालूं में दूर दृष्टि, पक्का इरादा और सहनशीलता की अपार सामर्थ्य होना चाहिए। सहनशीलता इस अर्थ में कि उसे भी दूसरे की कीचड़ सहन के लिए दृढ़ता होनी चाहिए।

कीचड़-उछाल भी एक प्रकार की होली है, जिसमें कोई किसी के द्वारा कुछ भी डाल देने का बुरा नहीं मानता। अपनी मान, मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा आदि को तिलांजलि देकर ही कीचड़-उछाल की शक्ति आती है। यह भी नेतागण का परम त्याग है, तपस्या है और है अपने चरित्र और गरिमा को अहं के नाले में विसर्जित करने की अपार क्षमता। इस स्थान पर आकर व्यक्ति परम हंस हो जाता है। फिर तो उसे अपने खाद्य-अखाद्य में भी भेद करने का भाव भी समाप्त हो जाता है। यह उसके चरित्र की पराकाष्ठा है।

कीचड़ वर्तमान राजीनीति का शृंगार है। आज की राजनीति में कीचड़-गंध की बहार है। इसे कुछ यों समझिए कि यह जेठ-वैसाख की तपते ग्रीष्म में सावन की मल्हार है। वसंत की बहार है। भेड़ों की तरह हांकी जा रही जनता का प्यार है। वह भी इसी को पसंद करती है, क्योंकि ये नेतागण भी तो वही डोज देते हैं, जिससे जन प्रिय बनने में कोई रोड़ा न आए। और फिर ये नेताजी भी तो उसी समाज के उत्पादन हैं, जिन्हें उसकी सारी खरी-खोटियां देखने-समझने का सुअवसर पहले से ही मिला हुआ है।

आदमी है, वहां कीचड़ भी है। वह हर मानव समाज का अनिवार्य तत्व है। यह अलग बात है कि वह सियासत का सत्व है। कीचड़ से नेताजी का बढ़ता नित गुरुत्व है। जब नाक ही न हो, तो कीचड़ की बदबू भी क्यों आए? इस बिंदु पर बड़े-बड़े तथाकथित महान भी स्थित पाए। दृष्टिकोण बदलने से दृष्टि भी कुछ और ही हो जाती है। इसलिए भले ही कहीं कितनी भी कीचड़ हो वहां पावनता ही नजर आती है। एक की खूबी स्थान भेद से कीचड़ बन जाती है। इसका अर्थ भी स्पष्ट ही है कि जो कुछ है कीचड़मय है। इसीलिए कीचड़ के प्रति प्रियता है, लय है। कीचड़ ही वर्तमान सियासत का तीव्रगामी भय है। कीचड़ में वैचारिक क्रांति का उदय है; क्योंकि जन भावना का निज स्वार्थों में विलय है।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

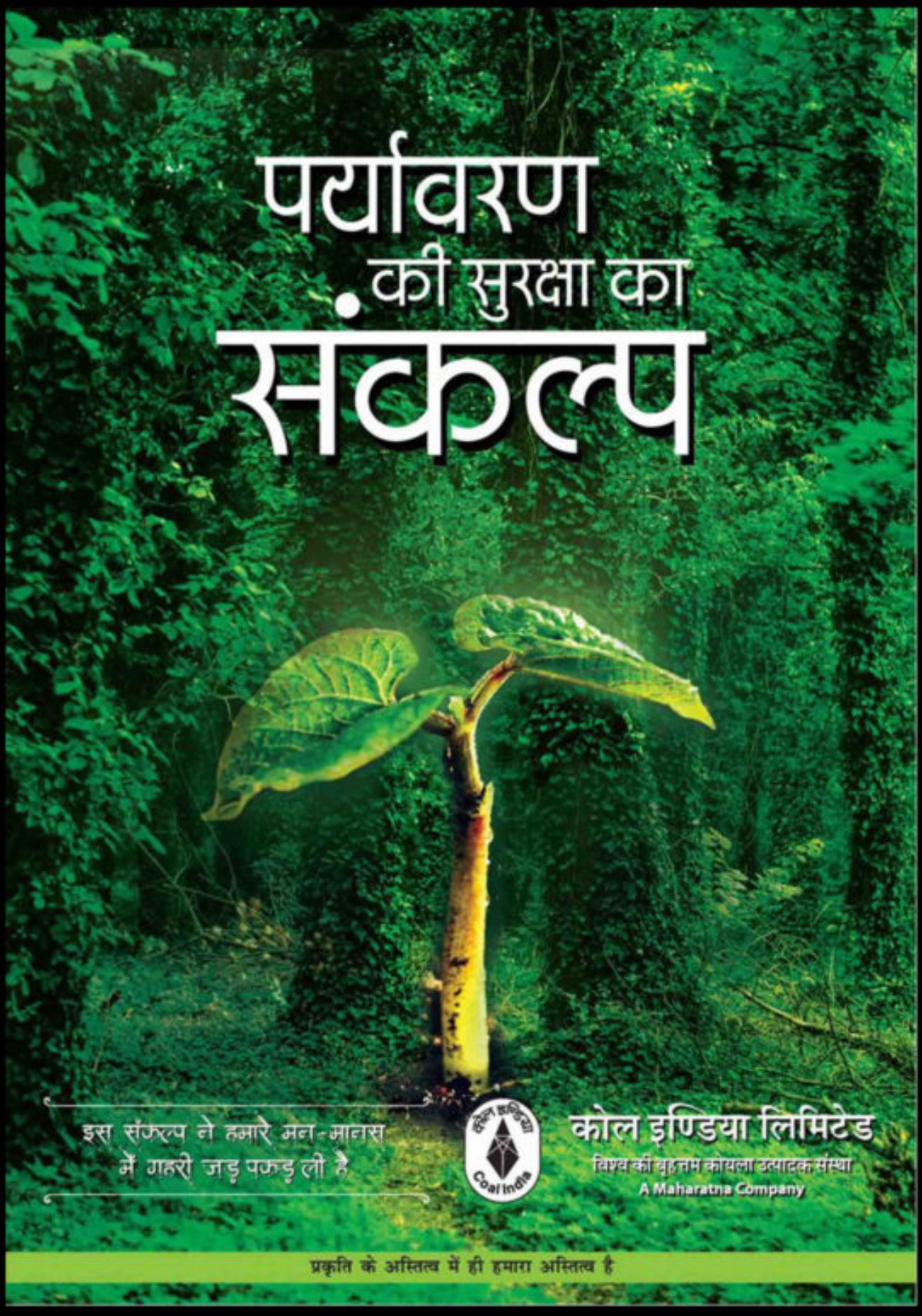

पर्यावरण
की सुरक्षा का
संकल्प
इस संकल्प ने हमारे मन-मानस
में गहरी जड़ पकड़ ली है
कोल इण्डिया लिमिटेड
विश्व की वृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था
A Maharatna Company
प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है